हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

12 मार्च, 2008

खण्ड 1, अंक 4

अधिकृत विवरण

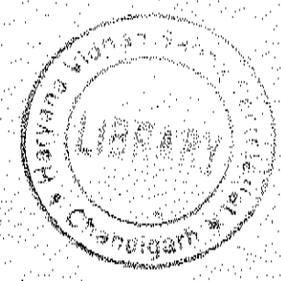

विषय सूची

बुधवार, 12 मार्च, 2008

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(4)1
हिन्दू गर्ल्ज कालेज, जगाधरी के विद्यार्थियों का स्वागत	(4)3
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(4)3
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(4)20
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(4)26
अनुपस्थिति की अनुमति	(4)27
अनुपस्थिति संबंधी सूचना	(4)28
सदन के निर्णय को रद्द करना	(4)28
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(4)32
वाक आउट	(4)64
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(4)66

मूल्य : 68

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 12 मार्च, 2008

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री० रघुवीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

Steps taken to Supply Canal Water upto Tail-end

*** 816. Shri Radhey Shyam Sharma :** Will the Irrigation Minister be pleased to state the steps taken by the Government to supply canal water upto tail-end of the villages of Rai Malikpur, Banyal and Daukhera of Narnaul constituency?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Village Rai Malikpur of Narnaul constituency falls at the tail-end of Budhwal Sub Minor which off-takes from Dhantal Minor of Nolpur Distributary System. The work of internal clearance of Nolpur Distributary, Dhantal Minor and Budhwal Sub Minor is in progress and is likely to be completed by 31-5-2008. Availability of water in the J.L.N. system has been increased and pumps on this system are also being rehabilitated to increase pumping capacity. With these steps, the canal water supply position upto the tail, end of village Rai Malikpur will improve.

The area of villages Daukhera and Banyal of Narnaul Constituency is hilly and has not been covered under the command of Mahendergarh Canal System of J.L.N. Lift Irrigation Project.

श्री राधे श्याम शर्मा अमर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि मई तक ये इन माइनर्ज की सफाई का काम कम्पलीट कर देंगे, इसके लिए इनका धन्यवाद। दौखेड़ा और बनयाल क्षेत्र जहां पर 10 ढाणियां आ जाती हैं और 4 गांव आ जाते हैं उनको लिफ्ट इरीगेशन प्रोजैक्ट में कवर ही नहीं किया गया है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इनको पानी कैसे मिलेगा?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, नौलपुर डिस्ट्रीब्यूट्री.अटेली डिस्ट्रीब्यूट्री के 4.694 किलोमीटर से निकलती है यह तकरीबन 41 किलोमीटर लम्बी है। हमारे पास पानी की कमी है और वह कमी इसलिए है क्योंकि बी०एम०एल० हांसी बुटाना लिंक कैनाल अभी

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

तक नहीं बन पाई है। इसके बनने पर ही कुछ इम्प्रूवमैंट होगी। पानी नौलपुर डिस्ट्रीब्यूट्री में 28 किलोमीटर तक चल रहा है। पहले मात्र भंगोल तक पानी जाया करता था लेकिन अब हमने चक मलिकपुर तक पानी पहुंचवाया है। रैस्टोरेशन और रिहेबीलिटेशन के काम भी चल रहे हैं। 21 पम्पस इनके हल्के के हमने ठीक करवाए हैं और 23 पम्पस ऐसे हैं जिनकी मरम्मत का कार्य चल रहा है। 25.250 किलोमीटर पर जो एम०एल०डी० 8 है वहां पर बामड़वास गांव है यह गांव आखिर में पड़ता है लेकिन है आसपास, वहां का पम्प हाउस भी काम नहीं कर रहा है। आगे जाकर नैन माइनर जहां से निकलती है वहां पर भी पम्प हाउस काम नहीं कर रहा है। जितनी डिस्ट्रीब्यूट्रीज आगे बनाई हैं खासतौर से धनताल माइनर वगैरह, इनमें प्रोब्लम यह आ रही है कि ये हिली एरिया हैं इसलिए इतना कुछ करने के बाद भी मुझे बहुत कम उम्मीद है कि पानी की जितनी एवेलेबिलिटी है उसके मुताबिक पानी वहां तक पहुंच पाएगा। पम्प हाउसिज की सफाई भी हम करवा रहे हैं और पम्प हाउसिज को हम ओपरेट भी कर देंगे। लेकिन जब तक बी०एम०एल० हांसी बुटाना लिंक नहर नहीं बनती है और जब तक पानी की एवेलेबिलिटी ज्यादा नहीं बन पाती तब तक वहां तक पानी पहुंचाना बड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन फिर भी हमारे विभाग का पूरा प्रयास रहेगा कि वहां पर पानी पहुंचे। टेल पर पानी न पहुंचने का दूसरा कारण यह भी है कि हैड्ज पर पानी की काफी चोरियां होती हैं। उन चोरियों को रोकने के लिए हमारी तरफ से पेट्रोलिंग भी की जाती है। मैं विशेष तौर पर पूरे सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि बगैर आउटलैट के लोग पम्पस लगाकर जहां पर भी पानी की चोरी करते हैं उनको वे ऐन्क्रेज न करें क्योंकि पानी की चोरी होने के कारण ही टेल पर पीने का पानी नहीं पहुंच पाता। अध्यक्ष महोदय, फिर भी मैं मेरे माननीय साथी शर्मा जी को बताना चाहूंगा कि जिन गांवों का वे जिक्र कर रहे हैं वहां तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे।

श्री राधेश्याम शर्मा अमर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इन्होंने नौलपुर डिस्ट्रीब्यूटरी, धनताल माईनर और बुधवाल सब-माईनर की आन्तरिक सफाई की बात की है। मैं इनकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि मैंने दौखेड़ा और बनयाल गांवों के बारे में प्रश्न किया है ये गांव सहवागपुर डिस्ट्रीब्यूटरी से कवर हो सकते हैं, नौलपुर डिस्ट्रीब्यूटरी से कवर नहीं हो सकते क्योंकि नौलपुर डिस्ट्रीब्यूटरी और उन गांवों के बीच में कृष्णावती नदी पड़ती है इसलिए नदी के बीच में ये कैसे नहर बनायेंगे? इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन चार गांवों और उनके आस-पास 10-11 ढाणियों में नहरी पानी कैसे पहुंचाया जायेगा?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने अपने प्रश्न में सहवागपुर डिस्ट्रीब्यूटरी का कोई जिक्र नहीं किया जबकि अब ये कह रहे हैं कि उन गांवों को सहवागपुर डिस्ट्रीब्यूटरी से जोड़ा जा सकता है।

श्री राधेश्याम शर्मा अमर : अध्यक्ष महोदय, मैं तो दौखेड़ा और बनयाल आदि गांवों में नहरी पानी की व्यवस्था करने के बारे में प्रश्न पूछ रहा हूं। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटरी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मंत्री जी केवल यह बता दें कि दौखेड़ा और बनयाल आदि गांवों में पीने के लिए ये नहरी पानी किस तरह से पहुंचायेंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने राय मिलकपुर, दौखेड़ा और बनयाल गांवों के बारे में प्रश्न पूछा है। ये गांव सहवागपुर डिस्ट्रीब्यूटरी से काफी दूरी पर हैं। ये गांव नोलपुर डिस्ट्रीब्यूटरी की टेल पर पड़ते हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा अमर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि नोलपुर डिस्ट्रीब्यूटरी और इन गांवों के बीच में कृष्णावती नदी पड़ती है। यहां से ये किस तरह से पानी इन गांवों में पहुंचायेंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इसको हम एग्जामिन करवा लेते हैं। यदि नदी को पार करके पानी पहुंच सकता है तो नोलपुर डिस्ट्रीब्यूटरी से पानी पहुंचाया जायेगा और यदि कोई दूसरा हल निकलेगा तो वह निकालेंगे। अगर इसमें कोई फिजीबिलटी होगी तो हम जरूर पानी पहुंचायेंगे। वैसे ही बेकार में इन रजबाहे बनाते रहें और सरकार का पैसा वेस्ट करते रहें, उसका कोई मतलब नहीं है।

हिंदू गर्ल्ज कालेज, जगाधरी के छात्र-छात्राओं का स्वागत

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, अगला प्रश्न पूछा जाये उससे पहले मैं आपकी अनुमति से सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हिंदू गर्ल्ज कॉलेज, जगाधरी के बी०ए०-II और बी०ए०-III क्लासिज के 52 छात्र-छात्राएं और उनके चार अध्यापक इस समय दर्शक दीर्घा में मौजूद हैं। मैं इन सबका पूरे सदन की तरफ से स्वागत करता हूं। ये छात्र-छात्राएं हमारी अगली पीढ़ी हैं। मुझे आशा है कि वे आज इस सदन की कार्यवाही से एक नई प्रेरणा लेकर जायेंगे।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

To reclaim the Water Logging Land in the villages of District Bhiwani

***827. Shri Ranbir Singh Mahendra :** Will the Irrigation Minister be pleased to state—

(a) whether any scheme has been formulated by the State Government to reclaim the water logging land of Chang, Mitathal, Gujrani, Sai, Kaluwas, Nathuwas, Ghuskani, Tigrana, Badesara, Jatai, Dhanana and Madhana villages of District Bhiwani ;

(b) if so, the status of the said scheme togetherwith the steps taken in this regard alongwith the time by which the farmers will get relief therefrom ; and

(c) whether the State Government has discussed with the Central Ground Water Board in this regard ?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

(a) Yes, Sir. A scheme namely constructing Mithathal—Ghuskani Link drain to reclaim water logging land in Distt. Bhiwani has been formulated.

(b) The scheme has been approved and is likely to be completed by 30.6.2009.

[Capt. Ajay Singh Yadav]

(c) This scheme does not require approval of Central Ground Water Board.

श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा है कि क्या जिला भिवानी के चांग, मिताथल, गुजरानी, साई, कालुवास, नाथुवास, घुसकानी, तिगड़ाना, बढेसरा, जताई, धनाना तथा मधाना गांवों की सेमग्रस्त भूमि का सुधार करने के लिए सरकार कोई योजना बना रही है या नहीं। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में जिस स्कीम का जिक्र किया है उस स्कीम में ये गांव नहीं आते। इन गांवों के लिए क्या कोई दूसरी स्कीम सरकार बना रही है ताकि वहां के गांवों की सेम की समस्या दूर हो सके?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे साथी चांग गांव की बात कर रहे हैं it is served by Chang Drain No. 2 और वहां के पानी को लिफ्ट करके भिवानी डिस्ट्रीब्यूटरी में आर०डी० 155000 में डाला जायेगा, जिसका काम पूरा हो चुका है। दूसरा साई गांव है, जहां तक मेरी जानकारी है वहां पर ड्रेनेज की कोई प्रोब्लम नहीं है। कभी-कभी बरसात के दिनों में थोड़ा बहुत पानी जुड़ जाता है। उस पानी को पम्पस से लिफ्ट करके आर०डी० 132 से 138 में डाल दिया जाता है। जो सुई है वह भिवानी-धग्गर ड्रेन सर्व करती है और उस पर काम चल रहा है। रेवाड़ी खेड़ा के बारे में इन्होंने कल भी जिक्र किया था इसके बारे में मुझे बताया गया है कि वहां पर ड्रेनेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कालूवास में मियाथल ड्रेन नम्बर 3 से पानी ड्रेन आऊट होगा जिसका काम कम्पलीट हो गया है। गुजरानी ड्रेन का काम भी कम्पलीट हो गया है। मियाथल ड्रेन नम्बर 2 का काम भी कम्पलीट हो गया है। मियाथल-घुसकानी ड्रेन से पानी ड्रेन होने का काम अण्डर प्रोग्रैस है। तिगड़ाना से मियाथल घुसकानी ड्रेन से पानी निकाला जायेगा यह काम भी कम्पलीट हो गया है। प्रेम नगर ड्रेन से पानी निकालाने का काम अण्डर प्रोग्रैस है। मुंढाल-तालू लिंक ड्रेन का काम भी कम्पलीट हो गया है। लोहारू-जाटू जो कि मुंढाल तालू लिंक ड्रेन द्वारा निकाला जायेगा वह काम भी कम्पलीट हो गया है। मुंढाल कलां ड्रेन से उसका पानी निकाला जायेगा वह काम भी कम्पलीट हो गया है। इसी प्रकार से मुंढाल खुर्द का काम भी कम्पलीट हो गया है इसे बास ड्रेन से और बौहनी थाका ड्रेन से हम ड्रेन करेंगे। एक गांव है सुखपुरा जो कि मुंढाल सुखपुरा लिंक ड्रेन से निकाला जायेगा जिसका काम अण्डर प्रोग्रैस है और जतोई ड्रेन का काम भी कम्पलीट हो गया है। बड़ेसरा ड्रेन नम्बर 1 और 2 से निकाला जायेगा और इसका काम भी कम्पलीट हो गया है। मिरान ड्रेन का काम अण्डर प्रोग्रैस है और सगनाम जो भिवानी-धग्गर ड्रेन से निकाला जायेगा यह काम भी कम्पलीट हो गया है। अध्यक्ष महोदय, यह जो स्कीम है यह इसी सरकार के दौरान हमने शुरू की थी और इसमें जहां तक मैं समझता हूं यह काम 30 जून, 2008 तक पूरा कर दिया जायेगा। पहले यह हमने केवल आर०डी० 0 से 50100 तक पर ही कार्य किया था और अब इसको हम आर०डी० 50100 से लेकर 70630 तक पूरा करेंगे। यह स्कीम 29 जनवरी, 2008 को अप्रूव हुई है और 30 जून, 2008 तक हम इसको पूरा कर देंगे।

श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक बात कहना चाहूंगा जो सदन के सामने इन्होंने मुंढाल की ड्रेन के बारे में बताया है इसके बारे में जो-जो इनफर्मेशन इनको दी गई है उसकी ये दोबारा फिर से जांच करवा लें क्योंकि

जो मुढांल-सुखपुरा ड्रेन है उसका तो सैक्शन नम्बर 4 का नोटिस भी नहीं हुआ है और उसके बारे में पेपर में भी कुछ नहीं आया है इसलिए उसके कम्पलीट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात माननीय मंत्री जी से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मधाना और धनाना गांवों के लिए कोई स्कीम नहीं है और न ही अब तक कोई स्कीम तैयार की गई है। मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वह इसको भी दोबारा एग्जामिन करवा लें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुंढाल ड्रेन का सम्बन्ध है तो उसका काम कम्पलीट हो गया है और सुखपुरा ड्रेन का काम अण्डर प्रोग्रैस है। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि इसमें कई जगह अवार्ड होना बाकी है जिसके लिए हमने पैसा जमा करवा दिया है। सैक्शन-9 भी हो गया है और यह काम अण्डर प्रोग्रैस है और जैसे ही अवार्ड होगा हम इसका काम शुरू कर देंगे। लेकिन जब तक अवार्ड नहीं होगा तब तक काम शुरू नहीं हो सकता। अवार्ड करने का काम डी०आर०ओ० का है और डी०आर०ओ० लगाने के लिए मैंने कल भी रेवेन्यू मिनिस्टर से रिकवैस्ट की थी इसके अतिरिक्त आपने दो और गांवों के बारे में जिक्र किया है यह काम अभी तक नहीं हुआ और मुंढाल लिंक ड्रेन से उसका वर्क कम्पलीट हो गया है। फिर भी अगर आपको कोई संशय हैं तो इस बारे में मैं अपने अधिकारियों से बात कर लूंगा। इसके अतिरिक्त अगर आप कोई और सुझाव भी देना चाहते हैं तो उन्हें हमारे पास भिजवा दें, हमारे अधिकारी उन पर भी आवश्यक कार्यवाही कर लेंगे।

श्री रामकिशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, ये जो ड्रेन निकाली जा रही हैं मैं इनके बारे में कहना चाहता हूं। जैसे भिवानी में गंदे पानी का नाला जो हमारे तोशाम, बवानी खेड़ा, आलमपुरा, बालावास, कंवारी, धमाना, धमाकुंजा और कुंगड़ के पास से निकलता है उसके पास किसानों को निकलने के लिए रास्ता नहीं है। सरकार जो जमीन ड्रेन के लिए एक्वायर करती है वह कम करती है जिसके कारण किसानों को रास्ते कम मिलते हैं। जो पुल बनाए जाते हैं बरसात के दिनों में उनकी मिट्टी कट कर वह रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है जिसके कारण किसानों को रास्ता नहीं मिलता। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी इन पुलों और दूसरे रास्तों का समाधान करने के लिए कोई कदम उठायेंगे ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहां तक ड्रेन के ऊपर रास्ते की बात है तो हमारे नार्मस के मुताबिक जो रास्ते हैं जो गांवों से गांवों को जोड़ते हैं उनके ऊपर तो हम पुल बनवाते हैं। जहां रास्ते हमारे नार्मस में कवर नहीं होते और कोई जरूरी रास्ता है तो वह केस माननीय मुख्य मंत्री जी तक जाता है अगर मुख्यमंत्री जी से अप्रूवल मिल जाती है तो हम उसको बना देते हैं। माननीय सदस्य के इलाके में ऐसे कई एरिया हैं जहां पर वास्तव में पुलों की जरूरत है। ऐसे पुलों को हम अवश्य ही बनायेंगे।

Vigilance Enquiry

@832. Shri Shamsher Singh Surjewala : Will the Chief Minister be pleased to state whether any criminal case/enquiry is pending against Shri Om Parkash Chautala and his associates before the Haryana Vigilance Bureau; if so, the details thereof ?

@ Put by Sh. Karan Singh Dalal, M.L.A.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Yes, Sir. A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

One criminal case FIR No. 20 dated 18.10.2005 under Sections 420/467/468/471/120-B IPC & 13 of P.C. Act has been registered at Police Station State Vigilance Bureau, Hisar against Sh. Om Prakash Chautala, ex-Chief Minister, Shri K.C. Bangar and others arising from Enquiry No. 3/2005 Chandigarh regarding alleged irregularities in the selection of H.C.S. and Allied Services and other posts. Haryana Public Service Commission has refused to handover most of the relevant record to the State Vigilance Bureau. In order to obtain record, State Vigilance Bureau filed an application in the Court of Chief Judicial Magistrate, Hisar for obtaining search warrants but the request was rejected. Thereafter, State Vigilance Bureau went in revision before the Sessions Judge, Hisar which was also dismissed. Thereafter, the State Vigilance Bureau filed a Criminal Misc. Petition under section 482 Cr. P.C. in the Hon'ble Punjab and Haryana High Court challenging the orders of the Chief Judicial Magistrate, Hisar and Sessions Judge, Hisar. The petition is being heard by Hon'ble Punjab and Haryana High Court. In view of the non-supply of the relevant records by the Haryana Public Service Commission, further investigation by State Vigilance Bureau is held up.

In addition, Enquiry No. 10/2005-Chandigarh against Sh. Om Prakash Chautala, ex-Chief Minister and the then Director, Animal Husbandry, Haryana regarding alleged misappropriation of grants under various centrally sponsored programmes in the Animal Husbandry Department and purchases made thereunder, is also pending.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला जी के प्रश्न के जवाब में जो वक्तव्य सदन के पटल पर रखा है उससे यह प्रमाणित होता है कि श्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके साथियों के विरुद्ध जो मुकद्दमे दर्ज किये हैं वह इसलिए किए गए क्योंकि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में बंगलिंग उन दिनों की गई। जो नियुक्तियां की गई उनके बारे में आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने अपने जवाब में जिक्र किया है कि "alleged irregularities in the selection of HCS and Allied Services." सर, इनके शासन के दौरान 3 बार एच०सी०एस० और एलाईड सर्विसिज में सलैक्शन हुआ है। यह कौन से साल का एडवरटाईजमैंट था और ये जो वैकेन्सीज हैं ये कौन से साल की थी जिनके अगेंस्ट या जिस शिकायत पर इन्होंने मुकद्दमा दर्ज किया है? अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने अपने वक्तव्य में जो यह कहा है कि निदेशक, पशुपालन हरियाणा और श्री ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ पशुपालन विभाग में की गई अनियमितताओं व गबन के बारे में भी इन्क्वायरी है तो यह इन्क्वायरी क्या है और क्या इसकी तफतीश पूरी हो चुकी है और अगर इसकी तफतीश पूरी हो चुकी है तो इसमें भी क्या विजिलैंस विभाग या पुलिस विभाग मुकद्दमा दर्ज करेगा? जो इसमें गबन किया गया है उसकी मात्रा क्या है वह गबन कितने रुपये का है या उस गबन की संख्या क्या है? क्या यह बताने का कष्ट करेंगे?

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल तो श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला जी के नाम था तो फिर श्री कर्ण सिंह दलाल कैसे पुट अप कर रहे हैं?

Mr. Speaker : Hon'ble members, Shri Shamsher Singh Surjewala has authorized Shri Karan Singh Dalal to ask the question, under Rule 52(3) of Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly. Under rule 52(3), any member can authorize any other member of the House to put the question on his behalf, if the Speaker allows. The written request of Shri Shamsher Singh Surjewala is here and I have allowed Shri Karan Singh Dalal to ask the question.

डॉ० सुशील इन्दौरा : ठीक है सर, मैं यही जानना चाहता था। अगर रिटन में परमिशन है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से हमने स्टेटमैंट हाउस के पटल पर रखी है। माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा इसमें हमने इन्क्वायरी नं० 3 ऑफ 2005 की चर्चा की है जिसके बारे में माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि ये कौन-कौन से वर्ष की सिलैक्शन थी। अध्यक्ष महोदय, इस केस के बारे में हमें कुल 37 शिकायतें मिली हैं जो कि हरियाणा के भिन्न-भिन्न व्यक्तियों से प्राप्त हुई हैं। ये शिकायतें उन लोगों ने भी की हैं जो खुद इस पद के सिलैक्शन के लिए उम्मीदवार थे। इन शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि इन सिलैक्शन के लिए उस समय के आयोग के सदस्यों द्वारा अथवा उस वक्त की सरकार के मुखिया द्वारा पैसा लिया गया है। भिन्न-भिन्न शिकायतें हमारे पास लम्बित हैं जो अनियमितताएं हुई हैं उनकी लिस्ट बड़ी लम्बी है इसलिए मैं माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल जी को इसकी कॉपी भिजवा दूंगा। इन शिकायतों पर जांच चल रही है। यह अकेली एच०सी०एस० की सिलैक्शन की शिकायत नहीं है इसके साथ ही बहुत सारी एलॉयड सर्विसिज के साथ रिलेटिड शिकायतें भी हैं। उदाहरण के तौर पर मैं सदन को बताना चाहूंगा कि फोरैस्ट सर्विसिज ग्रुप 'बी' कैटेगरी के अन्दर शारीरिक परीक्षा में भारी हेरा-फेरी हुई है इसकी जांच विजिलैंस के पास है। इसी प्रकार से नायब तहसीलदार, एच०सी०एस०, नॉमिनेटिड कैटेगरी में लगाए हैं उनके बारे में भी शिकायत प्राप्त हुई है। एस०डी०ओ०, इलैक्ट्रिकल के पद के लिए गोल्ड मैडलिस्ट कुमारी बिन्दलेश daughter of श्री बिन्दलेश को गोल्ड मैडलिस्ट होने के बावजूद सिलैक्शन से छोड़ दिया गया जबकि सैकण्ड और थर्ड डिवीज़न वाले कैंडीडेटस को सिलैक्ट कर लिया गया। उसकी शिकायत हमारे पास आई है। इसी तरह से सीनियर ऐनालिस्ट के पदों की भर्तियां जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा की गई उसमें ऐसे कैंडीडेट की सिलैक्शन हो गई जो मिनिमम योग्यता भी पूरी नहीं करता था, उसकी शिकायत भी हमारे पास आई है। डिप्टी डायरैक्टर, एग्रीकल्चर के बारे में माननीय कृषि मंत्री महोदय ने बताया था कि सरकार कार्यवाही कर रही है। एक ऐसे व्यक्ति का सिलैक्शन कर लिया गया है जो अपनी आयु सीमा पार कर चुका है। इसी प्रकार की कई और खामियां उसके अन्दर पाई गई हैं। डिप्टी डायरैक्टर, एग्रीकल्चर सिलैक्शन में अनियमितताओं के बारे में एफ०आई०आर० दर्ज करवाने के बारे में आदेश माननीय कृषि मंत्री जी ने दे दिये हैं। वे तीनों अधिकारी जो नाजायज तरीके से सिलैक्ट हुए थे उन्हें सस्पैंड कर दिया गया है। डिप्टी डायरैक्टर, एग्रीकल्चर की नियुक्ति में भारी अनियमितताएं हुई हैं। इसी प्रकार से एच०सी०एस० और एलॉयड सर्विसिज की सिलैक्शन में भारी अनियमितताएं की गई। कायदे कानून को ताक

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

पर रख कर सिलैक्शन में कानून की धज्जियां उड़ाई गई। जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनमें से कुछ केसिज हाई कोर्ट में चले हुए हैं। स्टाटिस्टिकल रिसर्च ऑफिसर की जो 17 लोगों की सिलैक्शन की गई है उसमें भी शिकायत प्राप्त हुई है। जो हमारे दलित भाई हैं उनमें से कइयों के साथ ज्यादती की गई है। उनकी शिकायत भी हमारे पास आई है। अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही लम्बी-चौड़ी लिस्ट है। कोई भी ऐसी सिलैक्शन नहीं बची है जिसमें हेरा-फेरी की शिकायत न की गई हो। जो शिकायतें आई हैं वे इस समय विजिलैंस के पास हैं और अण्डर इन्वैस्टिगेशन हैं। Regarding inquiry No. 10 of 2005 जिसमें यह इल्जाम है कि ऐनीमल हस्बैंडरी डिपार्टमैंट का पैसा श्री ओम प्रकाश चौटाला तथा डायरैक्टर ने मिल कर खुर्द-बुर्द कर लिया है जिससे सरकार को हानि पहुंची है। यह मामला अभी भी अण्डर विजिलैंस इन्वैस्टिगेशन है। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि सरकार ने ऐसे निर्देश दे दिये हैं कि जून, 2008 तक इस इन्क्वायरी को पूरा करवा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह भी पूछा है कि जो इल्जाम लगाया गया है कि इसमें कितने पैसे का गबन हुआ है। इस बारे में इस वक्त मेरे पास पूरे तथ्य उपलब्ध नहीं हैं लेकिन जो रिकार्ड मैंने देखा है उसके मुताबिक उसमें तकरीबन 130 लाख रुपये की राशि इन्वाल्वड है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में सदन को बताया है कि जो नियुक्तियां की गई हैं उसमें किस प्रकार से अनियमितताएं की गई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जब ये जान चुके हैं कि आयोग ने लोगों की भर्ती रिश्वत, सिफारिश, जाति और धर्म के नाम पर की है और वे लोग विभिन्न महकमों में बैठकर प्रदेश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनके अन्दर यह काबलियत नहीं है कि वे उन महकमों के साथ इन्साफ कर सकें। क्या माननीय मंत्री जी सदन में आश्वासन देंगे कि जिन नियुक्तियों के बारे में ये मानते हैं वे नियुक्तियां अयोग्य होते हुए भी की गई हैं। इसके मायने उनको ये नौकरियां नहीं दी जानी थी लेकिन उनको यह नौकरियां दी गई थीं। उनको बजाए अन्डर रूल सात चार्जशीट करने के क्या शो-काज नोटिस देकर फौरन बर्खास्त करने के बारे में ये विचार करेंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, जैसा कि मैंने बताया है कि डिप्टी डायरैक्टर, एग्रीकल्चर की इन्कवायरी रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है। इस बारे में कल माननीय कृषि मंत्री जी ने सदन में बताया था कि हमने यह निर्णय लिया है कि इण्डियन पिनल कोड की धारा 420, 467 और 471 जिनमें फौर्जरी डाकूमैंट वगैरह के मामले आते हैं उनके तहत हमने मुकद्दमा दर्ज करवाने का निर्णय ले लिया है। जहां तक उनको नौकरी में लगाने और न रखने का सवाल है तो इस बारे में इनका जो सुझाव है कि ऐसे व्यक्तियों को शो-काज नोटिस देना चाहिए, सरकार इस बारे में एडवोकेट जनरल से ओपिनियन ले लेगी। उनकी ओपिनियन के मुताबिक ही हम कार्यवाही करेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहुत अच्छी बात कही है। यह जो एच०पी०एस०सी० ने नियुक्तियों की सिफारिश की है इसमें साफ तौर पर अनियमितताएं सामने आई हैं। इसमें बहुत बड़ा धोखा प्रदेश की जनता के साथ हुआ है। अध्यक्ष महोदय,

आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अयोग्य व्यक्ति अपने सरकारी कामकाज का निपटारा अच्छी तरह से नहीं कर सकता है। वह आदमी सारा दिन दफ्तरों में न बैठकर के जैसी उनकी फितरत है, जैसे उनके आचार-विचार हैं, वे लोगों के साथ धोखा-धड़ी करते रहे हैं वही काम करते रहते हैं जिन अधिकारियों ने एच०पी०एस०सी० में ये गलतियां की हैं उनके खिलाफ सरकार ने मुकदमे दर्ज किए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन अधिकारियों ने जानबूझकर ऐसे व्यक्तियों को विभागों में नौकरियां दी हैं, उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया है कि यह सिलैक्शन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा की गई हैं और इस प्रकार की खामियां उस वक्त का हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन था जो आज भी है, हमने और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब यह पाया कि इसमें भारी अनियमिताएं पूरी सिलैक्शन के वक्त में की गई हैं। जो मैरिटोरियस कैंडिडेटस थे, जो काबिल उम्मीदवार थे उनको छोड़ दिया जाता था और नियुक्ति किसी अन्य आधार पर की जाती थी। ये सब बातें सोच कर राष्ट्रपति जी को हरियाणा सरकार ने एच०पी०एस०सी० की इम्पीचमैंट का रैफरैंस दिया है, जो कि विचाराधीन है। आज पब्लिक सर्विस कमीशन कोई सिलैक्शन करके भेजेगा तो हम उस सिलैक्शन को करने के लिए बाध्य हैं। परन्तु फिर भी अगर माननीय सदस्य को लगे कि इसके अन्दर किसी अधिकारी की अनियमितता में भागीदारी है तो ये उस स्पैसिफिक इन्सटांस के बारे में हमें लिखकर भेजें। मैं इनसे सरकार की तरफ से वायदा करता हूं कि हम उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने बताया है कि भिन्न-भिन्न अनियमितताओं की बहुत सी कम्पलेंटस हैं। जब सरकार को इतना पता लग गया है कि सर्विस कमीशन ने बेहताशा धांधली की है तो ये सारी अनियमितताओं के बारे में एक ही इन्कवायरी करें और इन्क्वायरी ऐसी न करें जैसे कि एक केस में 3 साल इन्क्वायरी करते हुए हो गए हैं। मेरा निवेदन है कि ये इन्क्वायरी को टाईम बाऊंड करें।

श्री अध्यक्ष : मान साहब, जिस पोस्ट के लिए गलत सिलैक्शन हुई है जैसे कि 10 पोस्ट्स हैं और उनमें से 2 की गलत सिलैक्शन हैं। क्या आप उन दो पर इन्क्वायरी करवाना चाहते हैं या 10 के खिलाफ ही इन्क्वायरी करवाना चाहते हैं?

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : नहीं सर, मैं तो कहता हूं कि जो भी कारगुजारी उस वक्त 10.00 बजे के पब्लिक सर्विस कमीशन ने पांच-छः साल के समय में की, उसकी जांच करवानी चाहिए। उस वक्त इस कमीशन को भंग करके सभी सदस्यों के इस्तीफे दिलवाकर रिप्लेस करके दोबारा से मैम्बर बना दिया गया था लेकिन इसके बाद उनका चरित्र हाई कोर्ट में और विभिन्न नियुक्तियों में सामने आ गया था। क्या सरकार ऐसा सोच रही है कि उस समय टोटल जितनी भी नियुक्तियां की गयी हैं चाहे वह पोल्यूशन बोर्ड में नियुक्ति की गयी हों जिसमें जे०ई०ज० से सीधे ही ऐक्सियन बना दिया गया, उनकी इन्क्वायरी का कोई समय निर्धारित है? स्पीकर सर, अब तक तीन साल हो गये हैं इसलिए इनका समय निर्धारित किया जाना चाहिए। स्पीकर सर, मेरा दूसरा सवाल हालांकि इस प्रश्न से रैलेवैन्ट नहीं है लेकिन फिर भी मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरे हलके के उस वक्त के विधायक के गांव में जो नम्बर ऑफ मर्डर्ज हुए थे उनके करने वाले आज तक अनट्रेस्ड

[श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान]

हैं। उन लोगों के खिलाफ इन्क्वायरी भी पूरी नहीं हुई है इससे ऐसा लगता है कि इस मामले में कहीं न कहीं मिलीभगत तो जरूर है। क्या मंत्री जी इस मामले की भी इन्क्वायरी करवाएंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है उससे मैं भी अपने आपको जोड़ता हूं। मैं इनसे केवल यह कहना चाहूंगा कि हमने जो एक स्टेटमैंट टेबल ऑफ दी हाउस में रखी है उसको ये पढ़ें क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो इंक्वायरी नम्बर 3/2005 है वह regarding alleged irregularities in the selection of H.C.S. and allied services and other posts के बारे में है। अध्यक्ष महोदय, इसको लेकर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से रिकार्ड मांगा था ताकि जो बात सच है वह सामने आ जाए और अगर कम्प्लेंट झूठी है तो वह भी सामने आ जाए। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने वह रिकार्ड देने से इंकार कर दिया, वह रिकार्ड दिखाने से इसलिए इंकार कर दिया ताकि तफतीशी अफसर इंक्वायरी करके सच का सच और झूठ का झूठ सामने न ला सके। स्पीकर सर, अब इस मामले को लेकर हाई कोर्ट के अंदर विजीलैंस ब्यूरो गया है और वहां पर इस समय यह प्रक्रिया प्रोग्रैस में है। इस मामले में माननीय हाई कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा उसके मुताबिक हम फर्दर कार्यवाही करेंगे। इनकी यह बात सही है कि इस मामले में तीन साल का समय बीत गया है। अध्यक्ष महोदय, हम यही कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस इंक्वायरी का निपटारा कर सकें।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे मेरे दूसरे सवाल का भी जवाब दे दें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, हालांकि इनका वह प्रश्न मेन सवाल से जुड़ा हुआ नहीं है परन्तु इस मामले में जो शिकायत पार्टी है यदि उनकी तरफ से लिखवाकर भिजवा दें तो मैं मान साहब को ऐश्योरैंस देता हूं कि इस मामले में भी कार्यवाही की जाएगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नाम से एक दरख्वास्त ये शिकायत पार्टी से लिखवाकर मुझे दिलवा दें, हम 6 महीने के अंदर इंक्वायरी पूरी करके क्रिमनल इन्वैस्टीगेशन डिपार्टमैंट को देंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने अपने सवाल में श्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके ऐसोसिएटस के राजकाज में हरियाणा के अंदर जो खुली लूट और खसौट के काम हुए हैं, उनके बारे में पूछा है। उस समय कई ऐसे वाकये हुए थे जिनकी अब पुलिस, विजीलैंस और सी०बी०आई० जैसी संस्थाएं जांच कर रही हैं और मुकद्दमें दर्ज हो रहे हैं। इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी और हाई कोर्ट से भी फैसले आए हैं। मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो सिरसा में बिजली विभाग की जमीन पर कब्जा हुआ है।

Mr. Speaker : Dalal Sahib, please ask your supplementary only pertaining to this question. In this regard, you can ask separate question.

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, चूंकि यह भी ओम प्रकाश चौटाला एंड ऐसोसिएटस का मामला है इसलिए मैं पूछना चाहता था लेकिन अगर आप मुझे इस बारे में पूछने के लिए एलाऊ नहीं करते हैं तो मैं अपना दूसरा प्रश्न पूछ लेता हूं। इनके समय में जो एच०सी०एस०

गलत तरीके से नोमीनेट हुए हैं उनमें एक प्रताप सिंह नाम का एच०सी०एस० भी है। पहले यह हुडा विभाग में कार्यरत था लेकिन इसको स्टैनो होते हुए भी सीधे ही एच०सी०एस० बनाया गया। इनके खिलाफ शिकायतें पिछले और अब के शासन के सामने आयी हैं तो क्या मंत्री जी इस बात का विश्वास दिलाएंगे कि जो एच०सी०एस० पिछली सरकार ने नोमीनेट किए और बोर्ड एवं कारपोरेशंज के नियमों को बदलकर या न बदलाव भी नोमीनेट किया, क्या माननीय मंत्री जी उन अन्य एच०सी०एस० को जिनको हटाने का सरकार ने नोटिस दिया है, उनके साथ उस प्रताप सिंह को जिनको स्टैनो से एच०सी०एस० बनाया था, उसका भी चयन उसी लिस्ट में हुआ था, क्या इसको हटाने के बारे में माननीय मंत्री जी कार्यवाही करेंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने जिस व्यक्ति विशेष को लेकर प्रश्न पूछा है तो इस बारे में पूरे तथ्य इस समय मेरे पास हैंड इन नहीं हैं लेकिन जो भी उचित कार्यवाही होगी वह हम अवश्य करेंगे ऐसा मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं। अगर किसी की नियुक्ति नियमों को ताक पर रखकर की गई है तो ऐसे किसी व्यक्ति को नौकरी में रहने का अधिकार नहीं है। सरकार उस पर नियमों के मुताबिक उचित कार्रवाई अवश्य करेगी।

श्री फूल चंद मुलाना : स्पीकर सर, क्या मंत्री महोदय यह विचार भी कर रहे हैं कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन क्रिमिनल की हैल्प कर रहा है उसके मायने ये हुए कि वह भी उसमें इन्वौल्व है, उसकी मंशा क्या है ? They are concealing the record in order to help the criminals. क्या ऐसे कमीशन के खिलाफ नो कांफीडैंस मोशन या क्रिमिनल प्रौसीडिंग्स स्टार्ट करने का सरकार विचार रखती है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सबसे वरिष्ठतम सदस्यों में से एक मुलाना जी हैं। उनकी चिंता वाजिब है कि जब हाईऐस्ट सलैक्शन बॉडी इस प्रकार के मैपुटिज्म और इरैगुलैरिटीज में इन्वौल्व हो जाए तो फिर प्रांत की 2 करोड़ 30 लाख जनता का विश्वास अपने आप सलैक्शन प्रोसैस के बारे में संदेह के घेरे में आ जाता है।

Mr. Speaker : No running comments. ओढ़ साहब, आपको बैठे-बैठे नहीं बोलना चाहिए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मौजूदा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन और उसकी प्रक्रिया दोनों भारी संदेह के घेरे में हैं। उनकी निष्पक्षता, उनकी काबिलियत and their capacity to make fair and independent selection is in serious doubts. इसके लिए संविधान के अंदर जो प्रक्रिया है उसमें इम्पीचमैंट का प्रावधान है, मुख्यमंत्री जी ने सारी बात को देखकर इसका बड़ा कड़ा नोटिस लिया और हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को हटाने के लिए एक रिफरैंस राष्ट्रपति जी को दे दिया है। दूसरा प्रश्न माननीय मुलाना साहब ने किया है कि क्या इंडिपैंडैंट ऑफ इम्पीचमैंट और नो कांफीडैंस मोशन के अलावा आपराधिक मुकद्दमा ऐसे पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों और उनके मुखिया के खिलाफ दर्ज करेंगे। मैं उनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस मामले में इंक्वायरी जारी है। माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल ने जो पब्लिक इंट्रैस्ट लिटिगेशन इस मामले में डाली थी, वह मामला भी उच्च न्यायालय के अंदर विचाराधीन है। दोनों की फाइंडिंग्स

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

आते ही जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वह किसी भी स्तर का आदमी क्यों न हो, उसके खिलाफ आपराधिक मुकद्दमा अवश्य दर्ज किया जाएगा ।

Promoting the Livestock

***852. Shri Randhir Singh :** Will the Animal Husbandry & Dairying Minister be pleased to state the steps taken by the Government for promoting the livestock in the State and whether the farmers are being encouraged for promoting livestock; if so, the details thereof ?

Agriculture Minister (Sardar H.S. Chatha) : Sir, the Government is undertaking various programmes in the State to promote the livestock and encourage the farmers. In brief the details are placed on the Table of the house.

Annexure - I

The department is taking up following activities to improve the livestock and encourage the farmers in the State :—

1. The State of Haryana is credited with having the best infrastructure in the country. A total of 2605 Veterinary Institutions catering to the needs of livestock owners. On an average one Veterinary Institution per less than three villages.
2. The Haryana Livestock Development Board has been constituted with a view to boost up the genetic improvement of livestock in the State. It is the State Implementing Agency of National Project for Cattle and Buffalo Breeding (100% Centrally Sponsored Scheme). The different breeding activities, starting from quality frozen semen production to doorstep A.I. services are carried out under this programme.
3. To preserve, improve & fast multiply quality Murrah germplasm, a noble programme of identifying top yielding Murrah buffaloes and giving incentive to the owners of such recorded animals has already started showing encouraging results. Under this programme, cash incentive to the owners of buffaloes yielding 11-15 Kg. of milk per day are given Rs. 3000/- whereas the owners of the buffaloes yielding above 15 to 20 kg and above 20 kg. are given Rs. 6000 and 10000, respectively. All the identified buffaloes are insured and 100% insurance premium in the case of Scheduled Castes and 75% in the case of general farmers is borne by the Government. Male calves born to these high yielding buffaloes are pruchased by the Government and reared as future bulls for supply to the Gram Panchayat at subsidized rates. The topmost bulls categorized on the basis of dam yield are being maintained at the high-tech sperm stations (Semen Banks) for production of semen.
4. There has been export of Murrah bulls and semen to institutes of national and international repute like National Dairy Development Board, Bhartiya Agro Industries Foundation in addition to several

states of the country including Punjab, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Uttaranchal, Gujrat, Chhatisgarh and Delhi.

5. The State is taking all necessary steps to keep its livestock healthy. The implementation of Foot & Mouth Disease control programme is a success story. Its incidence during the last three years has been as good as zero.

6. We are the first State to provide an insurance cover to "Hariana' cows and bullocks and 50% of the insurance premium in the case of general category farmers and 100% in the case of Scheduled Castes farmers is borne by the Government in such cases.

7. To promote cattle production and conservation, registered Gaushalas numbering 157 in the State are assisted from time to time through various State & Central agencies.

श्री रणधीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जानकारी दी है वह बहुत सराहनीय है। मैं उनका और मुख्यमंत्री जी का इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूं। पिछले सैशन के दौरान मैंने कुछ सुझाव दिये थे उन सुझावों को सरकार ने लागू किया है और इन सुझावों पर हरियाणा प्रदेश के हजारों किसानों को फायदा भी हुआ है। इससे हरियाणा प्रदेश के किसान जो पशुपालक हैं उनका हौंसला बढ़ा है, रुचि बढ़ी है इसी के साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी को यह भी सुझाव देना चाहता हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सप्लीमैंट्री पूछिए।

श्री रणधीर सिंह : ठीक है सर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पशुपालकों के पशुओं के लिए जो बीमा राशि योजना रखी गई हैं वह भैंसों के लिए और गायों के लिए 30 हजार रुपये रखी गई हैं जबकि आज के दिन जो मुर्रा भैंस की वैल्यू है।

श्री अध्यक्ष : आप यह पूछो कि इस राशि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

श्री रणधीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस बीमा राशि को भैंसों के लिए 50 हजार या 60 हजार तक बढ़ाने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और जो गाय के लिए बीमा राशि रखी गई है क्या उसको 20 हजार तक तथा जो क्रोस ब्रीड की राशि है उसको 30 से 40 हजार रुपये तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, इसके साथ-साथ जो हमारी हरियाणा नस्ल की गाय की बीमा राशि दस हजार रखी गई है क्या उसको भी बढ़ाने का कोई विचार है ?

सरदार एच०एस० चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, श्री रणधीर सिंह जी ने बहुत बढ़िया बात की है हम इस बीमा राशि को जरूर बढ़ायेंगे।

श्री अध्यक्ष : आपने दो सप्लीमैंट्री पूछ ली हैं अब आप केवल एक और पूछ सकते हैं, I will allow only one more supplementary.

श्री रणधीर सिंह : स्पीकर सर, मुर्रा नस्ल की भैंस जो 18 किलो दूध देती है उसके कटड़े की कीमत हरियाणा सरकार के हिसाब से दस हजार रुपये है।

श्री अध्यक्ष : आपका अपना कोई डेयरी फार्म है क्या?

श्री रणधीर सिंह : स्पीकर सर, गरीब आदमी और किसान इसी व्यवसाय से गुजारा कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार मुर्रा नस्ल की भैंस के कटड़े की कीमत दस हजार से बढ़ाकर 25-30 हजार रुपये करने के बारे में विचार करेगी क्योंकि इस कटड़े पर किसान का एक वर्ष का खर्चा दस हजार रुपये से ज्यादा आ जाता है। मैं माननीय मंत्री जी का और हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने हिसार में एक पशु विश्वविद्यालय स्थापित करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही मैं मंत्री जी से एक बात और पूछना चाहता हूं कि जो सरकार ने और विभाग ने पशुओं के लिए पोली क्लीनिक की योजना बनाई है जो अभी दो जिलों में शुरू की है क्या सरकार इस योजना को सभी जिला हैडक्वार्टर्ज पर खोलने का विचार करेगी?

सरदार एच०एस० चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी रणधीर सिंह जी को मुबारिकबाद दिए बगैर नहीं रह सकता क्योंकि इनका जो डेयरी फार्म है वह हरियाणा प्रदेश के बैस्ट डेयरी फार्मज में से एक है और मैं यह कहूं कि सबसे बैस्ट है तो कोई गलत नहीं होगा। इसलिए इनको डेयरी फार्म के बारे में ज्यादा नॉलेज है।

श्री अध्यक्ष : अब तो किसी की नजर नहीं पड़ेगी। आप इस बारे में एग्जामिन करवा लेना।

सरदार एच०एस० चट्ठा : ठीक है सर, इसके बारे में एग्जामिन करवा लेंगे।

श्री सुखबीर फरमाणा : स्पीकर सर, मेरे हल्के के गांव सुसाना में एक किसान की भैंस जिसकी कीमत 50 हजार रुपये थी उसको किसी ने जहर दे दिया और उस भैंस की मौत हो गई क्या सरकार उस किसान की कोई मदद करेगी?

श्री अध्यक्ष : श्री रणधीर सिंह जी ने जो सवाल पूछा है पशुओं की चोरी या मरने के बाद बीमा राशि देने के बारे में है।

सरदार एच०एस० चट्ठा : स्पीकर सर, हरियाणा हिन्दुस्तान में पहला राज्य है जिसके हर तीसरे गांव में या तो पशुओं का होस्पिटल है या डिस्पैंसरी खोली गई हैं। हिन्दुस्तान में ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसमें इतने डिस्पैंसरीज या होस्पिटल्ज पशुओं के लिए खोले गये हों। सरकार कोशिश कर रही है कि हर गांव में पशुपालन विभाग का एक वर्कर काम करे जो इन मुर्रा भैंसों की देखभाल करे। हरियाणा हिन्दुस्तान में नम्बर एक है जिसके सबसे ज्यादा बैस्ट एनीमल्ज हैं। मुर्रा नस्ल की भैंस हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में बैस्ट है। Murrah buffalo is number one in India.

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न थोड़ा सा हटकर है इसलिए मैं आपकी इजाजत से मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि हिन्दुस्तान में जब भी कहीं बर्ड फ्लयू आता है तो उसका डर हरियाणा के पोल्ट्री फार्मस में भी आता है। इसके कारण पोल्ट्री में अंडे वगैरह जो भी चीजें होती हैं उनको कोड़ियों के भाव बेचनी पड़ती है क्या सरकार ने उन्हें मुआवजा देने के बारे में सोचा है और कोई ऐसा कदम उठाया है जिससे आने वाले समय में हरियाणा में कभी बर्ड फ्लयू न फैले?

सरदार एच०एस० चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, बहन जी का सवाल इस सवाल से कनैक्ट नहीं करना चाहता। लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगा कि हरियाणा में बर्ड फ्लयू नहीं है, हरियाणा इस बीमारी से फ्री है। हरियाणा में सारे डाक्टर्ज, यूनिवर्सिटीज को हिदायत है कि कहीं भी एक या दो मुर्गी मर जाएं तो उनका पोस्ट मार्टम करें इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि जब हरियाणा में बीमारी है ही नहीं तो फिर किस बात के लिए हम कोई कदम उठाएं?

श्री सुखबीर फरमाणा : अध्यक्ष महोदय, जिन किसानों के पशु मर जाते हैं या फिर चोरी हो जाते हैं क्या उनकी मदद करने का कोई प्रस्ताव सरकार का है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अपनी शिकायत डी०सी० को लिखवाकर भिजवा दें।

श्री सोमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी कांस्टीच्युंसी के कई गांवों में पशु अस्पताल बने हुए थे और वहां वी०एल०डी०ए० बैठते थे लेकिन अब 3 सालों से कई अस्पतालों की बिल्डिंग्ज खाली पड़ी हैं, उनमें पशु अस्पताल की तरफ से कोई कर्मचारी नहीं बैठता, क्या मंत्री जी उन अस्पतालों में कोई वी०एल०डी०ए० या वैटरनरी डाक्टर एप्वांयट करने की कृपा करेंगे।

सरदार एच०एस० चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, इनकी यह बात वाजिब है कि काफी अस्पतालों में वैटरनरी डाक्टर्ज नहीं हैं। पीछे हमने इन डाक्टर्ज की भर्ती की थी लेकिन वे सारे लग चुके हैं और अब हम 200 वैटरनरी डाक्टर्ज और वी०एल०डी०ए० जल्दी ही भर्ती करने वाले हैं। कोई भी पशु अस्पताल ऐसा नहीं होगा जहां वैटरनरी डाक्टर न हो।

श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, कैटल ब्रीडिंग में भुर्रा ब्रीड के लिए हरियाणा में कई जिले सिलैक्ट हुए हैं, कैथल भी उन जिलों में से एक है, उन जिलों के लिए कई प्रकार के कंसैशन भी दिए हुए हैं लेकिन चिकित्सा सर्विस जिसका आपने जिक्र किया कि हर गांव में एक वर्कर रखेंगे तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या हर गांव में एक छोटी सी डिस्पैंसरी खोलने का कोई प्रावधान करने का सरकार का विचार है क्योंकि इसकी जरूरत भी है?

सरदार एच०एस० चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, आप इस डिपार्टमैंट के पी०एच०डी० हैं। हम हरियाणा में इनसैमीनेशन डिवैल्पमैंट स्कीम लाए हैं, कोई एनीमल जो तीन साल का हो वह कंसीव नहीं करता अगर कंसीव करता है तो गिर जाता है उसके इलाज करने के लिए हमने हरियाणा के सारे गांवों को कवर करने का प्रोग्राम बनाया है। मुर्रा नस्ल को इम्प्रूव करने के लिए हमने कुछ जिले सिलैक्ट किए हैं यह ठीक है, इसका मतलब यह नहीं कि हमने दूसरे जिलों को रिजैक्ट किया है, दूसरे जिलों को भी इसी तरह इमदाद मिलती रहेगी, उसी तरह अच्छी दवाइयां मिलती रहेंगी। हरियाणा हिन्दुस्तान में सबसे पहली स्टेट है जहां मुंहखुर की बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई है।

Class I and II Officers on deputation to Boards/Corporations

***880. Shri Karan Singh Dalal :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of Class I and II Haryana Government Officers presently working on deputation in various Boards and Corporations ;

(b) the number of those in (a) above who have overstayed their normal deputation period of three years ;

(c) The number of those in (b) above who are staying on deputation without equivalent or higher sanctioned posts ; and

(d) The number of those deputationists in (a) above who have gone back to the same or other Board/Corporation without spending the minimum required cooling period in their parent Department ?

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, the information is as as under —

(a) Class-I 49 and Class-II 36;

(b) Class-I 2 and Class-II 6;

(c) Class-I 2 and Class-II 2

(d) Nil

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने (a) के जवाब में कहा है कि श्रेणी-I के 49 और श्रेणी-II के 36 अधिकारी विभिन्न बोर्ड और निगमों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि श्रेणी-I और श्रेणी-II के अधिकारी जिन बोर्ड और निगमों में तीन वर्ष की अवधि से अधिक ठहरे हुए हैं उन बोर्ड और निगमों का क्या नाम है?

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आपका यह सवाल पूछने के पीछे क्या मंशा है?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में बहुत से बोर्ड और निगम हैं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो अधिकारी विभिन्न बोर्ड और निगमों में डैपुटेशन पर गये हुए हैं वे एच०एस०आई०आई०डी०सी० और हुडा जैसे महत्वपूर्ण बोर्ड और निगमों में गये हुए हैं या दूसरी जगह गये हुए हैं? अध्यक्ष महोदय, बोर्ड और निगम ओटोनोमस बोडी बनाई गई हैं जिनमें सरकार का बहुत कम दखल होना चाहिए। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में जो हमारे अधिकारी विभिन्न बोर्ड और निगमों में बैठे हुए हैं, उन बोर्ड और निगमों का क्या नाम हैं?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, दलाल साहब के प्रश्न के हिस्से का जवाब है श्रेणी-1 के 49 और श्रेणी-II के 36 अधिकारी विभिन्न बोर्ड और निगमों में डैपुटेशन पर गये हुए हैं। क्योंकि इनके प्रश्न के इंटैंट से नहीं मालूम था कि ये बोर्ड और निगमों का नाम भी जानना चाहेंगे इसलिए अभी मुझे बोर्ड और निगमों का नाम मालूम नहीं है। मैं मेरे माननीय साथी को बाद में लिखकर बोर्ड और निगमों का नाम भिजवा दूंगा। इसके अतिरिक्त जो कर्मचारी ओवर स्टे कर गये हैं उनका जवाब 'ख' पार्ट में दिया हुआ है। उन बोर्ड कारपोरेशंज का नाम मैं बताना चाहूंगा कि ये कर्मचारी हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, कुरुक्षेत्र डिवैल्पमैंट बोर्ड, हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन और हरियाणा रूरल डिवैल्पमैंट फण्ड एडमिनिस्ट्रशन बोर्ड के अंदर कार्यरत हैं।

श्री अमीर चंद मक्कड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इनके पास लिस्ट होगी कि कौन-कौन से अधिकारी कौन-कौन से बोर्ड और कारपोरेशंज में ओवर स्टे पर रूके हुए हैं। क्या उनको वहां से बदलने के लिए सरकार कोई प्रयास करेगी?

Mr. Speaker : Makkar Ji, it is not possible to give reply. You may ask your separate question in this regard and Hon'ble Minister will give reply.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी सप्लीमैंटरी यह है कि आज तमाम दुनियां के सभी देश आपस में एक दूसरे के ज्ञान से नये-नये अविष्कारों से जुड़े हुए हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस बारे में सदन को आश्वस्त करेंगे कि हमारे जितने भी बोर्ड और निगम हैं उनके अंदर जो स्पेशलिस्ट अधिकारी हैं, जो बोर्ड एवं निगमों को बहुत अच्छे तरीके से चला सकें उनकी नियुक्ति की जाये ताकि बोर्ड एवं निगम तरक्की कर सकें। क्या इस बारे में मंत्री जी सदन को आश्वस्त करेंगे ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह पृथक प्रश्न है परन्तु यह नीति का प्रश्न है इसलिए मैं जवाब देना चाहूंगा कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की स्पष्ट नीति रही है कि जो अधिकारी सबसे काबिल और योग्य हैं वे अधिकारी किसी भी बोर्ड और निगम में कार्य कर सकते हैं। अध्यक्ष महादेय, हमारी सरकार ने विभिन्न विभागों में कई दूरगामी निर्णय लिये हैं। मेरे माननीय साथी यदि किसी स्पेसिफिक केस के बारे में या स्पेसिफिक बोर्ड या निगम के बारे में जानना चाहते हैं तो उस बारे में हमें लिखकर भिजवा दें, हम उसका जवाब लिखकर दे देंगे।

Construction of By-Pass of Dadri City

*927. **Shri Nirpender Singh Sangwan :** Will the P.W.D. (B & R) Minister be pleased to state the time by which the construction work on by-pass of Dadri City is likely to be started togetherwith the time by which the said by-pass is likely to be completed ?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Land acquisition process has been initiated for Dadri by pass. Work shall be taken up after land is acquired.

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहूंगा कि दादरी के अंदर ढ़ाणी मोड़ पर जो रेलवे ओवर ब्रिज बन रहा है उसकी वजह से दिल्ली रोड पर ट्रैफिक बंद हो जाता है और दूसरा रोड दादरी शहर के बीच में से है। उस रोड़ पर हर रोज तकरीबन 1100-1200 डम्पर खेड़ी बुरा, अटेला और माणकावास की पहाड़ियों से कंकरीट लेकर दिल्ली की तरफ जाते हैं। दादरी शहर के अन्दर से अगर ये सारे का सारा ट्रैफिक निकालेंगे तो ट्रैफिक जाम, एक्सीडैंट्स और पॉल्यूशन जैसी अनेक गम्भीर समस्यायें पैदा हो जायेंगी। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जब तक यह बाई-पास नहीं बनता है तब तक सारे का सारा ट्रैफिक दादरी शहर के बीच में से न निकाला जाये। यह बहुत जरूरी बात है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, दादरी शहर के बाई-पास के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि बाई-पास के बारे में जो रिपोर्ट थी वह आ चुकी है। टोटल 15.27 करोड़ की लागत से यह आर०ओ०बी० बनेगा। इसका सैक्शन 4 सरकार ने कर दिया है। इसमें लैंड एक्वीजीशन की कॉस्ट 6.38 करोड़ रुपये होगी और इसके कंस्ट्रक्शन पर तकरीबन 8.79 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। एल०ए०डी०बी० 4.50 करोड़ हमने इसकी दे दी है और बाकी के लिए नाबार्ड को भेज रखा है। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा बताई गई ट्रैफिक जाम और दूसरी समस्याओं का सम्बन्ध है तो इसके लिए हम साईड में काफी स्पेस रखेंगे। कई अन्य जगहों पर भी इस तरह स्पेस हमने रखा है। अगर उससे बात नहीं बनी तो जहां-जहां से ट्रैफिक निकल सकता होगा उसको देखते हुए हम इसके लिए आलटरनेटिव रूट भी बनाकर देंगे जिससे वहां पर इस प्रकार की कोई प्रोब्लम नहीं होगी।

श्री बलवंत सिंह सढ़ौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सारे हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का सारा ट्रैफिक यमुनानगर शहर के बीच में से होकर निकलता है जिससे वहां पर हर रोज घंटों जाम लगा रहता है तो क्या यमुनानगर में उत्तर प्रदेश की तरफ जाने के लिए सरकार के पास कोई बाई-पास बनाना विचाराधीन है?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इसके लिए ये मुझे अलग से नोटिस दें, फिर हम इसकी फिजीबिलटी को कम्पलीटली एग्जामिन करवा लेंगे। मेरे विचार से यह बात इनकी सही है कि वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और जगह बहुत कम है। इस काम के लिए हम एक कंसलटैंट भी हायर कर देंगे और अगर फिजीबिलटी बनेगी तो हम वहां पर बाई-पास जरूर बनायेंगे।

Opeining of an I.T.I. in Pataudi Constituency

***863. Shri Bhupinder Chaudhary :** Will the Industrial Training and Vocaltional Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open an Industrial Training Institute in Pataudi constituency.

Urban Development Minister (Shri A.C. Chaudhry) : Yes, Sir. It is proposed to convert the Vocational Education Institute at Mojabad into an ITI with effect from the next academic session.

श्री भूपेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्री जी का जबाव सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि 14 मई, 2006 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाऊंस किया था कि हम पटौदी के अन्दर आई०टी०आई खोल रहे हैं। यह मामला विचाराधीन है और इसके लिए जमीनों का सर्वे भी को चुका है। मौजाबाद का तो सैपरेट इश्यू है। यहां पर आई०टी०आई० खोलने की बात मैंने पूछी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2006 में अनाऊंसमैंट की थी जिसको 2 साल हो चुके हैं तो यह काम कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री ए०सी० चौधरी : स्पीकर साहब, चूंकि सवाल अंग्रेजी में पूछा गया था इसलिए मैंने जवाब भी अंग्रेजी में ही दिया है। अब मैं ऑनरेबल मैम्बर को यह बताना चाहता हूं कि इन्होंने पूछा है कि पटौदी में आई०टी०आई० खोली जायेगी या नहीं तो मैंने इनको बताया है कि हम वोकेशनल इंस्टीच्यूट को ही आई०टी०आई० में कन्वर्ट कर रहे हैं। जहां तक पटौदी में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई अनाऊंसमैंट का सम्बन्ध है तो इस बारे में इनको बताना चाहूंगा कि अभी तक हमारे पास उसके लिए जमीन का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। ऐसे केसिज में हमारे द्वारा कुछ नॉर्मज फिक्स किए गए हैं और जब तक वे पूरे नहीं होते तब तक हम कोई आई०टी०आई० खोलने का प्रस्ताव नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, अनाऊंसमैंट के बाद निर्धारित नॉर्मज को पूरा करवाना होता है इसलिए आप निर्धारित नॉर्मज को पूरा करवाइये। मंत्री जी ने आपको आश्वासन दे दिया है आपकी आई०टी०आई० बन जायेगी।

Sarva Shiksha Abhiyan

***904. Shri Shahida Khan :** Will the Educaiton Minister be pleased to state the percentage of the amount spent under the Sarva Shiksha Abhiyan in the district Mewat out of the total amount allocated for the state ?

Education Minister (Shri Mange Ram Gupta) : Sir, in 2006-07, 5.37% and In 2007-08 upto (31-01-2008) 4.01%.

श्री शाहिदा खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो सर्व शिक्षा अभियान है इसमें मेवात के अन्दर बहुत बड़ा घपला हुआ है और इस केस में कई महीने तक लोग जेल मे भी रहे हैं । बाद में इस केस में हेरफेर करके इस केस को बिगाड़ दिया गया क्योंकि जब अधिकारी लोग अपराधियों से हमदर्दी रखेंगे तो केस तो बिगड़ेगा ही । इसके अलावा मेवात को जिला बने लगभग 4 साल हो गये हैं लेकिन आज तक वहां पर कोई भी सीनियर सैकेण्डरी स्कूल नहीं बनाया गया है जबकि सरकार मेवात के बाहर बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगा रही है कि हम शिक्षा के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है शाहिदा जी, आप इस बारे में लिखकर मंत्री जी को भिजवा दें आपको जवाब दे दिया जायेगा । Hon'ble Members, now the question hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Facility of Community Toilets in Bhiwani

***889. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any porposal under consideration of the Government to provide community toilets in following localities of Bhiwani—

1. Singi Kat Basti ;
2. Bawri-Gate ;
3. Hanuman-Gate ;
4. Balmiki Basti ;
5. Kameti Mohalla ;
6. Jain Chowk ;
7. Khadi Mohalla ;
8. Durga Colony ; and
9. Brijawasi Colony ?

शहरी विकास मंत्री (श्री ए०सी० चौधरी) : नहीं, श्रीमान जी ।

Consolidation in Loharu Sub-Division

***920. Shri Somvir Singh :** Will the minister of State for Revenue and Disaster Management and Consolidation be pleased to state —

(a) the number of such villages in Loharu Sub-Division where the consolidation has not been done so far and whether it is also a fact that jamabandi of village Kharkhari have also not prepared ; and

(b) the time by which the said work of consolidation as referred in Part(a) above will be completed ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्रीमती सवित्री जिन्दल) :

(क) श्रीमान जी, सात (7) गांव नामतः गोकलपुरा, मण्डौली कलां, खरकड़ी अलाऊदीनपुर, पहाड़ी, सिंघानी व चहड़कलां की चकबन्दी अभी तक नहीं हुई है। यह भी ठीक है कि गांव खरकड़ी की जमाबंदी अभी तक तैयार नहीं की गई।

(ख) लगभग 3 वर्ष में, बशर्ते इन गांवों के हकदारान सहयोग दें।

Female Foeticide

***894. Shri Sher Singh :** Will the Health Minister be pleased to state whether it is a fact that steps taken by the Government to curb female foeticide have not yielded the desired results ; if so, the reasons thereof ?

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी) : नहीं श्रीमान जी। लिंग अनुपात में सुधार हुआ है। 2001 की जनगणना के अनुसार जन्म लिंग अनुपात 819 था। इस घटते लिंग अनुपात को रोकने के लिए जो कदम उठाए गए उनके फलस्वरूप लिंग अनुपात सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम अनुसार बढ़कर वर्ष 2006 में 857 हो गया तथा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम अनुसार वर्ष 2007 के अन्त तक यह अनुपात बढ़कर 860 हो गया है।

Contribution of Government of India under the B.P.L. Scheme

***898. Shri Tejender Pal Singh Mann :** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the percentage wise details of amount contributed by the Government of India and Haryana Government under the BPL scheme during the period from 1.04.2006 to 31.03.2007 and 1.04.2007 to 31.12.2007 seperately ?

उप मुख्यमंत्री (श्री चन्द्र मोहन) : श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

बी०पी०एल० योजना के अन्तर्गत भारत सरकार का अंशदान

1.4.2006 से 31.3.2007 तथा 1.4.2007 से 31.12.2007 तक की पृथक-पृथक अवधि के दौरान बी०पी०एल० योजना के अन्तर्गत भारत सरकार तथा हरियाणा सरकार द्वारा अंशदान की गई राशि का प्रतिशतवार ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

अवधि	वस्तु	भारत सरकार का अंशदान (करोड़ रुपये) तथा प्रतिशत	हरियाणा सरकार का अंशदान (करोड़ रुपये) तथा प्रतिशत
1.4.2006 से 31.3.2007	गेहूं तथा चावल	263.26 (98.1 प्रतिशत)	5.23 (1.9 प्रतिशत)
1.4.2007 से 31.12.2007	गेहूं तथा चावल	250.00 (98.3 प्रतिशत)	4.38 (1.7 प्रतिशत)

[श्री चन्द्र मोहन]

अवधि	वस्तु	भारत सरकार का अंशदान (करोड़ रुपये) तथा प्रतिशत	हरियाणा सरकार का अंशदान (करोड़ रुपये) तथा प्रतिशत
1.4.2006 से 31.3.2007	मिट्टी का तेल	*374.2 (100 प्रतिशत)	शून्य
1.4.2007 से 31.12.2007	मिट्टी का तेल	*280.6 (100 प्रतिशत)	शून्य

*लगभग

Construction of Bus Stand at Village Badli

***901. Shri Naresh Sharma :** Will the Transport Minister be pleased to state whether it is a fact that the Gram Panchayat of Village Badli, district Jhajjar has transferred land to the Haryana Roadways for construction of Bus Stand ; if so, the details of steps taken by the Transport Department for the construction of Bus-Stand there ?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : जी हां, महोदय। दिनांक 22.2.1989 को 20 कनाल 4 मरला भूमि परिवहन विभाग के नाम स्थानान्तरित की गई थी, लेकिन अभी तक भूमि का वास्तविक मौका पर कब्जा परिवहन विभाग को नहीं सौंपा गया है। प्रस्तावित भूमि खाली नहीं है और इस पर कई पक्की दुकानें तथा मकान बने हुए हैं। परिवहन विभाग को दी गई भूमि पर से ढांचे हटाने के बारे में जिला प्रशासन के साथ मामला उठाया हुआ है। खाली भूमि का कब्जा प्राप्त होने के बाद बस स्टैंड का निर्माण किया जायेगा।

Construction of Bus Stand at Karnal

***909. Smt. Sumita Singh :** Will the Transport Minister be pleased to state—

(a) whether there is any porposal under consideration of the Government to construct a Bus Stand with all the modern facilities including market etc. at Karnal; and

(b) if so, the time by which it is likely to be completed ?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) :

(क) जी हां, महोदया

(ख) प्रस्तावित करनाल बस स्टैंड का निर्माण सभी आधुनिक सुविधाएं सहित सार्वजनिक तथा निजि सहभागिता (बी०ओ०टी०) के माध्यम से निर्माण

किया जाना है । इसके लिए प्रोजैक्ट रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सलाहकार फर्म को सौंप दिया है । जैसे ही प्रोजैक्ट रिपोर्ट तथा प्रस्तावित दस्तावेज तैयार हो जायेंगे तो बस स्टैंड के निर्माण हेतु निविदाएँ मांग ली जायेंगी ।

To Set-up Big Industry in Ateli Constitutency

*929. **Shri Naresh Yadav :** Will the Industries Minister be pleased to state—

(a) whether there is any porposal under consideration of the Government to set up a big industry in the industrially backward area of Ateli constituency ; if so, the details of the steps being taken by the Government in this regard ; and

(b) whether the status of industrial area is being given to the Kanti-Kheri area adjacent to Neemarana (Rajasthan) near Ateli ?

उद्योग मंत्री (श्री लछमन दास अरोड़ा) :

(क) नहीं श्रीमान, अटेली निर्वाचन क्षेत्र के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में बड़ा उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) नहीं, श्रीमान ।

Construction of Bhakra—Hansi—Butana Canal

*819. **Dr. Sushil Indora :** Will the Irrigation Minister be pleased to state—

(a) whether the construction work of Bhakra—Hansi—Butana Canal has been completed ;

(b) if not, the present position thereof ;

(c) whether there is any inter-state dispute in it ; and

(d) whether the rules and regulations have been followed to link the Bhakra main canal and the permission has been obtained from the concerned Department or the Ministry ?

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

(क) श्रीमान जी, हांसी ब्रांच-बुटाना ब्रांच बहु-उद्देशीय सम्पर्क चैनल का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है ।

(ख) 99 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा किया जा चुका है ।

(ग) जी हां श्रीमान जी, पंजाब एवं राजस्थान सरकारों ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 2007 की याचिका क्रमांक 1 तथा याचिका क्रमांक 3 दायर की है ।

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

(घ) जी हां श्रीमान जी, इस परियोजना के लिए नियम तथा विनियमों का पालन किया गया है ।

Power generated by Yamuna Nagar Thermal Power Plant

***803. Dr. Sita Ram :** Will the Power Minister be pleased to state the total quantum of power generated daily after the inauguration of Yamuna Nagar Thermal Power Plant during the period from 1st November, 2007 to December, 2007 togetherwith the quantum of electricity demand of the State met out by the said power plant ?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : श्रीमान, दीनबंधु छोटूराम ताप विद्युत परियोजना, यमुना नगर की 300 मैगावाट की पहली इकाई ने दिनांक 13.11.2007 को समक्रमण होने के बाद, नवम्बर तथा दिसम्बर 2007 के दौरान 73092 यूनिट बिजली का उत्पादन किया है । 28.02.2008 तक इस इकाई ने राज्य की मांग को पूरा करने हेतु 815.96 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया है ।

Construction of New Sabzi Mandi of Narnaul

***815. Shri Radhey Shyam Sharma :** Will the Agriculture Minister be pleased to state the time by which the work is likely to be started on new sabzi mandi of Narnaul ?

कृषि मंत्री (सरदार एच० एस० चट्ठा) : हां, श्रीमान जी, निर्माण कार्य दिनांक 15.04.2008 तक शुरू किये जाने की सम्भावना है ।

Water Logging Land of the State

***828. Shri Ranbir Singh Mahendra :** Will the Agriculture Minister be pleased to state—

(a) whether any survey has been conducted by the State Government in respect of water logging land of the State ; if so, the district wise and village wise details thereof, and

(b) whether any steps have been taken by the Central Ground Water Board in Haryana in this regard, if so, the initiative by the Government in this regard ?

कृषि मंत्री (सरदार एच० एस० चट्ठा) :

(क) हां, श्रीमान जी, इस संबंध में विस्तृत सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है ।

(ख) हां श्रीमान जी, इस संबंध में सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है ।

सूचना

(अ) हां श्रीमान जी, कृषि विभाग की भू-जल कोष शाखा द्वारा नियमित रूप से प्रति वर्ष माह जून (वर्षा ऋतु पूर्व) एवं माह अक्तूबर (वर्षा ऋतु के बाद) राज्य में चुने हुए 2105 ग्रिड बिंदुओं (कुएं, पिज्योमैट्रिक ट्यूब आदि) से जलस्तर नापा जाता है। अक्तूबर 2007 में लिये गये अन्तिम आंकड़ों के अनुसार 0-1.5 मीटर जलस्तर के तहत 111030 हैक्टेयर जिसमें 163 गांव आते हैं और 1.5-3.0 मीटर जलस्तर के तहत 333144 हैक्टेयर में 427 गांव आते हैं।

(ब) श्रीमान जी, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, चण्डीगढ़ द्वारा राज्य के जिला गुड़गांव, झज्जर एवं हिसार की हांसी तहसील में सेमग्रस्त क्षेत्रों में अध्ययन किया गया है तथा उनकी विस्तृत रिपोर्ट सिफारिशों के साथ जारी की गई है।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1997-98 में नीदरलैण्ड सरकार की तकनीकी व वित्तीय सहायता से लवणीय एवं सेमग्रस्त भूमि को सुधारने के लिये एक परियोजना चालू की गई है तथा सोनीपत एवं कैथल जिलों में 2406 हैक्टेयर भूमि का सुधार किया जा चुका है। कृषि विभाग ने वर्ष 2003-04 से भारत सरकार तथा राज्य सरकार की 70:30 हिस्सापूंजी के आधार पर लवणीय एवं सेमग्रस्त भूमि के सुधार के लिये एक योजना क्रियान्वित की जा रही है तथा अभी तक इस योजना के अन्तर्गत भिवानी, झज्जर, सिरसा व सोनीपत जिलों के 1742 हैक्टेयर क्षेत्र का सुधार किया जा चुका है।

Allotment of Residential Plots to Scheduled Caste Families

*833. **Shri Shamsher Singh Surjewala :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether Haryana Government had announced the grant of residential plots measuring 100 yards to each of the landless S.C. families residing in rural areas ;

(b) if so, the time by which the beneficiaries are likely to be given the residential plots ;

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to arrange finance for the construction of houses on such plots ; and

(d) whether the Government intends to develop the land where the plots will be given ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान जी,

(क) पात्र अनुसूचित जाति के परिवारों को 100 वर्ग गज के रिहायशी प्लाट निःशुल्क दिए जाने का निर्णय लिया गया है।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

(ख) क्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। दिनांक 31.3.2008 तक आवेदन पत्र आमंत्रित करने तथा उपयुक्त भूमि की पहचान करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं। प्लाट आबंटन की समब सारणी पात्र लाभार्थियों की संख्या तथा उपयुक्त भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

(ग) नहीं श्रीमान जी, हालांकि, अलाटी अधिसूचित बैंक या राज्य सरकार की अन्य स्कीमों के अधीन पात्रता के अनुसार वित्त व्यवस्था कर सकता है।

(घ) यथासमय गलियां, पेयजल, बिजली इत्यादि की मूलभूत सुविधाएं प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Godowns Hired on Rent

110. Shri Karan Singh Dalal : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state—

(a) the yearwise number of godowns hired on rent by the Food & Supplies Department in the State during the year 2000-2001 till date.

(b) whether prior permission from the competent authority was obtained for hiring the godowns as referred to in (a) above ; and

(c) if so, the details of such godowns with the names of officers who hired these godowns without prior permission/approval of the competent authority alongwith the action taken against them ?

उप मुख्यमंत्री (श्री चन्द्र मोहन) : श्रीमान जी,

(क) खाद्य एवं पूर्ति विभाग द्वारा किराए पर लिये गये गोदामों का वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	किराए पर लिये गये गोदामों की संख्या
2000-01	70
2001-02	113
2002-03	121
2003-04	114
2004-05	68
2005-06	43
2006-07	33
2007-08	28

(ख) गोदाम को किराये पर लेने व संबंधित पार्टी के साथ इकरारनामा करने के लिये जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक स्वयं सक्षम प्राधिकारी है। जिला खाद्य

एवं पूर्ति नियंत्रक पी०आर०मन्यूअल भाग-3 के नियम 6(ए) अनुसार गोदामों के चयन तथा उनको किराए पर लेने के लिये भी सक्षम है।

यद्यपि किराए की अदायगी निदेशक, खाद्य एवं पूर्ति, हरियाणा की पूर्व स्वीकृति से वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत/नियत की गई दरों के आधार पर प्रदान की जाती है। पंजाब वित्तीय नियमावली वाल्यूम-1 के नियम 19.6 क्रम संख्या 8 अनुसार जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक 1000/- रुपये तक तथा निदेशक, खाद्य एवं पूर्ति, हरियाणा 1000/- रुपये से अधिक के किराए की अदायगी करने के लिये सक्षम हैं। इसलिए जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक द्वारा किराए पर गोदाम लेने के लिये पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। परन्तु गोदामों की किराए की अदायगी सक्षम प्राधिकारी यानि निदेशक, खाद्य एवं पूर्ति, हरियाणा की पूर्व अनुमति लेने उपरांत की जाती है। यहां यह भी उल्लेख किया जाता है कि मण्डी से भारतीय खाद्य निगम को स्टाक का सीधा प्रेषण किया जाता है, जो स्टाक प्रेषण के बाद शेष रह जाता है, को खाद्य एवं पूर्ति विभाग द्वारा जन संस्थाओं के साथ-साथ निजी संस्थाओं से किराए पर लिये गये गोदाम/पलिन्थों पर भण्डारण किया जाता है। जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक अपने-अपने जिले में निरीक्षक अमले के साथ तालमेल करके मण्डी के समीप स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गोदाम किराए पर लेते हैं। इसके उपरांत जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक संबंधित पार्टी के साथ निर्धारित पी०आर० 53/96 में इकरारनामा करते हैं।

(ग) जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक द्वारा गोदाम किराए पर लेने के लिए पूर्व अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुपस्थिति की अनुमति

(i)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received Leave of Absence dated 11th March, 2008 from Shri Birender Singh, Finance Minister which reads as under :—

Speaker Sir,

"Due to unavoidable circumstances it would not be possible for me to attend Session on 12th March, 2008. I may please be granted leave of absence from the House."

Question is —

That permission for leave of absence to Shri Birender Singh, Finance Minister to remain absent from the sitting of the House on 12th March, 2008, be granted.

The motion was carried.

(ii)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received Leave of Absence dated 11th March, 2008 from Shri Subhash Choudhry, M.L.A., which reads as under :—

Respected Speaker Sir,

"I am sorry to say that I may not attend the Haryana Vidhan Sabha Session on 12.3.2008 due to personal appearance in Civil Court, Jagadhri on 12.3.08. Therefore, I request you to grant me leave for 12.3.08.

Thanks."

Question is —

That permission for leave of absence to Shri Subhash Choudhry, M.L.A. to remain absent from the sitting of the House on 12th March, 2008, be granted.

The motion was carried.

अनुपस्थिति संबंधी सूचना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I am to inform the House that I have received a letter from Sh. Paramvir Singh, Parliamentary Secretary dated 11th March, 2008, vide which he has expressed his inability to attend the sittings of the House due to his ill-health. He has also stated that he will attend the Session of Haryana Vidhan Sabha as soon as he recovers from his illness.

सदन के निर्णय को रद्द करना

Dr. Sushil Indora : Mr. Speaker Sir, before starting the discussion on the Governor's Address, I want to say something. अध्यक्ष महोदय, पिछले 2 दिनों से हमारे जो इंडियन नेशनल लोकदल के सम्मानित सदस्यगण हैं उनको सदन से निकाला जाता है। हमारे एक माननीय सदस्य श्री रामफल चिड़ाना को सदन की बाकी अवधि के लिए निकाला गया है यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, यह बात तो श्री कर्ण सिंह दलाल जी के सुझाव पर जो मीटिंग हुई है उसमें डिस्कश हो चुकी है।

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, एक अनावश्यक प्रस्ताव हमारे खिलाफ लाया गया है। हमारे ऊपर यह लांछन लगाया गया है कि हम हाउस की कार्यवाही को डिस्टर्ब करते हैं जबकि हकीकत यह है कि सरकार की तरफ से ऐसे प्रोवोकेशन्ज किये जाते हैं। सरकार एक सोची-समझी साजिश के तहत ऐसा करती है कि यहां का माहौल बिगड़े और हम हरियाणा प्रदेश के लोगों की सच्ची बात को हरियाणा विधान सभा में न रख सकें। (शोर एवं व्यवधान)

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, ये बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और यह कहना कि सदन किसी विशेष दल के खिलाफ साजिश कर रहा है, यह अनुचित होगा। (शोर एवं व्यवधान)

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, यह हमारा हक है कि हम अपनी बात को सदन में कह सकें। हमारे साथी को सदन में वापिस बुलाया जाये और सरकार इस पर खेद प्रकट करे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसा है आपने जो प्रस्ताव की बात की है the resolution was adopted by the House unanimously. The Members of different parties were sitting in the House. It was adopted unanimously, रही बात unanimously resolution को वापिस लेने की तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। दूसरी बात आपने श्री रामफल चिड़ाना को पूरे हाउस के लिए निकालने की कही है तो उसके बारे में संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब देंगे।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दो दिन पहले इस सदन के अन्दर एक ऐसा वाक्या हुआ जिस पर मुझे लगता है कि हर सदस्य को, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी को भी, एन०सी०पी० के सदस्य को भी, बी०एस०पी० के सदस्य को भी, बी०जे०पी० के सदस्यों को भी, कांग्रेस के सदस्यों को भी और निर्दलीय सदस्यों को भी खेद है। वह दिन इस सदन के लिए भी एक खेद का दिन था। अध्यक्ष महोदय, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी से हमारे वैचारिक मतभेद हैं। हमारे वैचारिक मतभेद बी०जे०पी० के साथियों से भी हैं, बी०एस०पी० के साथियों से भी हैं, एन०सी०पी० के साथियों से भी हो सकते हैं। हमारे नीतिगत मतभेद भी हो सकते हैं। स्पीकर सर, सत्ता पक्ष का विपक्ष की सारी बात से और विपक्ष का सत्ता पक्ष की सारी बात से सहमत होना जरूरी नहीं है, यही प्रजातंत्र की खूबसूरती भी है। इस खूबसूरती में sometimes we also agree and sometimes we disagree. Sir, इसलिए विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है और सत्ता पक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है। मुख्तलिफ दलों को अपनी बात कहने का अधिकार है परन्तु यह अधिकार किसी भी सदस्य को नहीं है कि वह दूसरे सदस्यों पर हाथ उठाए या उनके साथ गाली-गलौच की भाषा का इस्तेमाल करे। अध्यक्ष महोदय, इसी विषय पर माननीय सदस्य इन्दौरा साहब ने एक बात उठाई है। वे अपनी पार्टी के डिप्टी लीडर भी हैं और अगर वे अपनी पार्टी में उनकी बात को आगे ले जाते हैं तो मैं इस सदन के सामने इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो हुआ it is highly condemnable Sir. यह बहुत ही निन्दनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, इस सदन की जो गरिमामयी परिपाटी है उसको देखते हुए बगैर आरोप-प्रत्यारोप के माननीय विपक्ष के हमारे साथी खेद प्रकट करें और इस सारे इंसिडैंट को कण्डैम करें तो मुझे लगता है कि let by gone be by gone Sir, और हम लोग एक नई प्रणाली की, एक नई मर्यादा की, एक नई परम्परा की शुरूआत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर वे खेद प्रकट करें तो हम एक नई शुरूआत करें। अगर वे खेद प्रकट करते हैं तो हाउस की कार्यवाही में भाग लेने के लिए उनको वापिस बुला लिया जाए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, सारा सदन इस बात के लिए आपकी तारीफ कर रहा है। पिछले दिन जो कुछ हुआ है उन सब बातों को दरकिनार करके आपने

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

फ्राखदिली दिखाई। जब सभी माननीय सदस्यों ने आपसे अनुरोध किया तो आपने आज सवेरे अपने चैम्बर में सभी दलों के माननीय विधायकों को बुलाया। माननीय मंत्री जी भी वहां पर थे। आदरणीय इन्दौरा साहब की मौजूदगी में वहां पर जो बात हुई वहां पर भी आपने फ्राखदिली दिखाई और यहां तक भी कहा कि जैसे ये लोग चाहते हैं हम वैसे ही सदन को चलाने को तैयार हैं। मीटिंग के अन्दर मुख्तलिफ तौर पर जो बात हुई थी इन्दौरा साहब वहां पर खुद मौजूद थे। जो बात यहां पर आई है यह बैठक में नहीं हुई थी। इस बैठक में तीन बातें तय हुई थीं। पहली बात यह थी कि माननीय स्पीकर साहब के प्रति कोई भी सदस्य अपशब्द नहीं कहेगा और किसी तरह की टीका-टिप्पणी नहीं करेगा। नम्बर दो, क्वैश्चन आवर का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जिसमें प्रदेश के लोग यह जानना चाहते हैं कि सरकार उनके लिए क्या करने जा रही है। माननीय किसी विधायक को अगर किसी विभाग की कारगुजारी से कोई तकलीफ है तो वह भी प्रश्नकाल के अन्दर ही उस विभाग से कोई जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही यह तय हुआ था कि प्रश्नकाल के दौरान कोई भी माननीय सदस्य किसी तरह का व्यवधान पैदा नहीं करेगा। अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात यह हुई थी कि जो माननीय सदस्य हाउस से निकाल दिए गए हैं उस बारे अब कोई भी बात दोहराई नहीं जाएगी क्योंकि अगर फिर से उस बात को दोहराते हैं तो उससे फिर से एक उत्तेजक माहौल बन सकता है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि माननीय सदस्य इन्दौरा साहब सुबह की बैठक में मौजूद थे इसलिए मैं आपकी मार्फत इन्दौरा साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो भी व्यवस्था दी है वे अपनी तरफ से लागू करवाएं और श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला तथा हम इस बात को अपनी तरफ से लागू करवाएंगे तथा यह आश्वासन देंगे कि कोई भी सदस्य इस प्रकार की कोई बात नहीं करेगा जिससे माहौल खराब हो। इस बात का फैसला मीटिंग के अन्दर ही हो चुका है। इस बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय अपना फैसला देंगे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, सदन के अन्दर जिस प्रकार का वातावरण हुआ उसकी तो सभी लोग निन्दा करते हैं लेकिन प्रश्न यह है कि यह हुआ क्यों? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात यहां पर हो रही है। हमारे सदस्य को अपमानित किया गया। बीच में जो विधायक थे, वे इस समय हाउस में मौजूद नहीं हैं, उनकी हर समय ऐसी सोच रहती है और वे गाली-गलौच पर आ जाते हैं। सदन में सम्मानित सदस्य यहां पर गालियां खाने के लिए तो नहीं आये हैं। जो कसूरवार है वह मुआफी मांगे फिर उसके बाद अगली कार्यवाही शुरू की जाए।

श्री अध्यक्ष : ऐसी बात मेरे हिसाब से नहीं हुई है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बहुत लम्बे अर्से से इस सदन के सदस्य हैं, तजुर्बेकार हैं, मैं इनसे यह अनुरोध करूंगा कि जो मौजूदा सदन के अन्दर गतिरोध पैदा हुआ है उसको छोड़कर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ही प्रजातांत्रिक मूल्यों का हम सभी निर्वहन कर पाएंगे। हम सब अपने-अपने इलाकों से चुनकर आए हैं। हरियाणा के 2 करोड़ 30 लाख लोगों की जिम्मेवारी हम सब पर है इसलिए हमें कई बार छोटी-छोटी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। आरोप और प्रत्यारोप हमेशा

लगाए जाएंगे और हमेशा लगाए जा सकते हैं। परन्तु जैसा आपने खड़े होते हुए ही कहा था कि सदन में जो हुआ है उसका सबको खेद है। इसको कहकर मुझे लगता है कि हम इस बात को आगे ले जा सकते हैं। ऐसा करके हम सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चला सकते हैं। मैं इनसे उम्र में और तजुर्बे में छोटा हूं और मैं इनसे आदर के साथ यह अनुरोध जरूर करूंगा कि अगर आज भी आरोप-प्रत्यारोप के अन्दर पड़े रहेंगे तो इस सदन की सुचारू तरीके से कार्यवाही चलाने में दिक्कत आएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य के साथ एक सदस्य की दुर्घटना हुई। उस दुर्घटना की हम सब निन्दा करते हैं और अगर आप सब सहमत हैं तो हम आपसे सादर यह अनुरोध करेंगे कि उस सदस्य को सदन में वापिस बुला लिया जाए। वे सदन में आकर अगर कहें कि यह घटना नहीं होनी चाहिए थी और उनको भी इस घटना पर खेद है। तब हम आगे चलेंगे। अगर हम इसी तरह से इल्जाम और काऊंटर इल्जाम लगाते रहेंगे तो सदन आगे नहीं चल पायेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से आगे चलनी चाहिए।

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that Shri Ram Phal Chirana, M.L.A. may be called back in the House ?

Voices : Yes.

Mr. Speaker : Now the Parliamentary Affairs Minister will move a motion.

Power Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move —

> That the decision of the House taken on 10th March, 2008 in respect of Shri Ram Phal Chirana, M.L.A. suspending him for the remainder of the present Session under Rule 104 read with Rule 121 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, be rescinded.

Mr. Speaker : Motion moved —

> That the decision of the House taken on 10th March, 2008 in respect of Shri Ram Phal Chirana, M.L.A. suspending him for the remainder of the present Session under Rule 104 read with Rule 121 of the Rules of Procedure and conduct of business in the Haryana Legislative Assembly, be rescinded.

Mr. Speaker : Question is —

> That the decision of the House taken on 10th March, 2008 in respect of Shri Ram Phal Chirana, M.L.A. suspending him for the remainder of the present Session under Rule 104 read with Rule 121 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, be rescinded.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, I allow Mr. Ram Phal Chirana, M.L.A. to participate in the proceedings of the House.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर आपकी फिराखदिली की दाद देता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। मैं सभी माननीय सदस्यों से तथा सीनियर मैम्बर्ज से अनुरोध करता हूं कि हम इन बातों में न पड़कर के क्योंकि यह बजट सैशन है और इस बजट सैशन में विपक्ष जो भी कहना चाहता है वह बिना किसी टीका-टिप्पणी के कहे। विपक्ष सरकार को इस बात के लिए विवश कर दे कि वाकई कहीं पर कोई अनदेखी हुई है और गलत कार्य हो रहा है। ऐसी हैल्दी डिस्कशन करके सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की तरफ ध्यान आकर्षित करें।

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन बीती बातें विसार दे और आगे की सूध ले। आगे सदन सुचारू रूप से चलेगा ऐसी हम कामना करते हैं।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Yesterday, Somvir Ji was on his legs. Please, continue your speech on Governor Address.

श्री सोमवीर सिंह (लोहारू) : स्पीकर सर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। गवर्नर एड्रैस में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में दिखाया गया है। इस एड्रैस से साफ झलकता है कि यह सरकार किसानों की विशेष तौर पर मदद करने का इरादा रखती है और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसानों के बिजली के 1600 करोड़ रुपये माफ किए हैं। अध्यक्ष महोदय, यह जो जमींदारों की जमीन एक्वायर की जाती है उसका फ्लोर रेट हरियाणा में दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, सन् 2007 में वर्षा ज्यादा होने के कारण और ओलावृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ था उसका 208 करोड़ रुपये का मुआवजा सरकार ने दिया है। इसी तरह से सरसों और चने की फसल को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। इसी तरह से मार्किटिंग बोर्ड के द्वारा गन्नौर में 500 एकड़ जमीन पर विश्व स्तर की टर्मिनल मार्किट बनाई जा रही है जिससे किसानों को बहुत फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा दिवस पर सरकार ने जमींदारों के कोआप्रेटिव बैंकों के लोन का जो इन्ट्रस्ट माफ किया है इससे जमींदारों को बहुत फायदा होगा। सरकार ने 830 करोड़ रुपए के कर्जों के इंट्रस्ट को माफ किया है, उससे आम आदमी जो इन्ट्रस्ट के बोझ में दबा हुआ था, इससे उसको बहुत राहत मिली है। इसी तरह से पशु विश्वविद्यालय की स्थापना हिसार में की जा रही है जिससे किसानों को बहुत फायदा होगा। इसी तरह से समान पानी के बंटवारे का एक साहसिक कदम इस हरियाणा सरकार द्वारा उठाया गया है यह बहुत ही सराहनीय कदम है। इस हांसी-बुटाना लिंक कैनाल को बनाने का करीब-करीब 90 फीसदी काम हो चुका है। **(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री आनन्द सिंह डांगी चेयर पर पदासीन हुए)** सभापति महोदय, इससे पहले तो कुछ जिलों को पानी का फायदा हो रहा था लेकिन आने वाले समय के अन्दर हम उम्मीद करते हैं कि दक्षिणी हरियाणा को इसका काफी फायदा मिलेगा। इसी तरह से यह सरकार पीने के पानी पर काफी जोर दे रही है।

खासतौर पर अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सरकार ने बहुत अहम कदम उठाए हैं। उनके लिए 200 लीटर की पानी की टंकी मुफ्त में देने और पानी का कनैक्शन देने का काम किया है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने हरियाणा में 'इन्दिरा गांधी पेय जल स्कीम' की शुरूआत की है। सभापति महोदय, हमारे यहां पर सबसे बड़ी प्रोब्लम जो है वह बिजली की है। बिजली की इस समस्या को हल करने के लिए हरियाणा सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सबसे पहले यमुनानगर थर्मल प्लांट के अंदर 300-300 मैगावाट की दो यूनिट्स लगायी हैं। इसी तरह से हिसार के खेदड़ गांव के अंदर थर्मल प्लांट का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री खुद आए थे। वहां पर 1200 मैगावाट का थर्मल प्लांट लगाया जा रहा है। यह प्लांट वर्ष 2010 तक पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार झाड़ली गांव के अंदर श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 1500 मैगावाट का थर्मल प्लांट लगाने की शुरूआत की है। यह प्लांट वर्ष 2010 में चालू किया जाना है। इसी तरह से 'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना' के अन्तर्गत कई गांवों में ग्रामीण कनैक्टिविटी में सुधार की स्कीम लागू की गयी है। इस योजना में 242 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस योजना से आम आदमी को फायदा होगा। इसी तरह से शहरों के अंदर नगरपालिकाओं की मदद करने के लिए उनको वित्तीय सहायता दी जा रही है। गुड़गांव में भी एक नये नगर निगम की स्थापना की जा रही है। इसी तरह 8 नगरपालिकाओं की भी स्थापना की गयी है। इन 8 नगरपालिकाओं में मेरे लोहारू शहर को भी शामिल किया गया है जिसके लिए मैं सरकार का बार-बार धन्यवाद करता हूं। इसी तरह से अनुसूचित जाति के लोगों की मदद करने के लिए जिन शहरी क्षेत्रों के वार्डों में उनकी आबादी 50 परसैंट से अधिक है वहां 144 वार्डों में सरकार आने वाले दो साल के अन्दर 144 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसी तरह से शहरों के अंदर भी हाउस टैक्स माफ किया गया है। इसी तरह से देहात के अंदर चूल्हा टैक्स भी माफ किया गया है। यह चूल्हा टैक्स अनुसूचित जाति के लोगों का तो अनाउंसमैंट के वक्त से ही माफ कर दिया गया था और जो बाकी लोग हैं उनका भी चूल्हा टैक्स 31 मार्च तक हमेशा के लिए माफ कर दिया जाएगा यदि वे अपना टैक्स 31 मार्च से पहले-पहले पे कर देंगे। इसी तरह से चेयरमैन सर, हुडा ने शहरों के अंदर एक 'आशियाना' नाम की योजना शुरू की है। पंचकूला में 2072 फ्लैटस इसी योजना के तहत बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा फरीदाबाद, रोहतक, बहादुरगढ़, कैथल, सिरसा, अम्बाला और गुड़गांव में भी ऐसे ही बीस हजार फ्लैटस बनाए जाएंगे। इसी तरह से हाउसिंग बोर्ड के द्वारा भी कमजोर वर्गों के लिए 50 हजार मकान बनाए जा रहे हैं इन मकानों में औरतों को 33 प्रतिशत रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसी तरह से गांव के अंदर हुडा की तरह सैक्टर बनाने के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है जिससे गांव के अंदर भी अब तरक्की हो सकेगी। इसी तरह से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिसको पहले महेन्द्रगढ़ और सिरसा में शुरू किया गया था उसको अब अम्बाला और मेवात जिलों में भी लागू किया जा रहा है। आने वाले वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंदर इस योजना को बाकी जिलों के अंदर भी लागू किया जाएगा। इसी तरह से चीफ मिनिस्टर साहब ने गांवों के अंदर एक और योजना लागू की है। यह मुख्यमंत्री दलित गांव उत्थान एवं मलिन बस्ती विकास योजना है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति की 50 प्रतिशत से अधिक की जनसंख्या वाले गांवों में 50 लाख रुपये प्रति गांव खर्च करके मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवायी जाएंगी। इससे इन गांवों के

[श्री सोमवीर सिंह]

लोगों को फायदा होगा। इसी तरह से मुख्यमंत्री जी ने करनाल के अंदर एक रैली की थी जिसमें उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को काफी प्रोत्साहन देने की बात कही थी। जिन अनुसूचित जाति के लोगों के पास रिहायश के लिए एग्रीकल्चर जमीन नहीं है उनको 100-100 गज के प्लाट्स दिए जाएंगे। चेयरमैन सर, यह एक बहुत बड़ा काम है इसका लोगों को बहुत देर से इंतजार था क्योंकि लोगों के पास जगह की कमी थी। मैं इसके लिए सरकार का बार-बार धन्यवाद करता हूं। इसी तरह से गांवों में सफाई कर्मचारी लगाने की बात है। इसके लिए भी एक योजना सरकार के द्वारा चलायी जा रही है। इस योजना के तहत गांवों में 11000 सफाई कर्मी नियुक्त किए जा रहे हैं। इनको 3510 रुपये प्रति हैड के हिसाब से दिया जाएगा। चेयरमैन सर, इससे अनुसूचित जाति के लोगों को बहुत फायदा होगा, उनको बहुत राहत मिलेगी। इतनी भारी संख्या में किसी भी स्टेट के अंदर इम्प्लायमैंट नहीं दी गयी है हरियाणा पहला ऐसा स्टेट है जिसने यह काम किया है। इसी तरह से सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम किए हैं। सरकार ने वर्ष 2008 को 'शिक्षा वर्ष' घोषित किया है। जिन बच्चों ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी उनके लिए आगामी सत्र से सरकार द्वारा बुक्स और एक्सरसाइज बुक्स फ्री दी जाएंगी। इसी तरह से अनुसूचित जाति के लोगों के बच्चों की मदद के लिए एक अलग से मासिक छात्रवृत्ति की योजना बनायी गयी है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ रही अनूसूचित जाति की लड़कियों को 150 रुपये से चार सौ रुपये प्रतिमास तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी तथा अनूसूचित जाति के लड़कों को 100 से 300 रुपये तक की मासिक छात्रवृत्ति के रूप में भत्ता दिया जाएगा। यह पहली क्लास से बारहवीं क्लास तक के लिए तय किया गया है यह भी बहुत अच्छा काम है। इसी तरह से टैक्नीकल ऐजुकेशन पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है ताकि आने वाले समय में बच्चों को रोजगार मिल सके। इसी तरह से गैस्ट टीचर्ज की नियुक्ति कर सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। अब हम किसी भी गांव में स्कूल में जाते हैं तो हमें टीचर्ज की कमी कहीं महसूस नहीं होती है। कुछेक बातें ऐसी हैं जो मैं अपनी कांस्टीच्यूएंसी के बारे में कहना चाहूंगा। चेयरमैन सर, एक बात मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस बार सर्दी बहुत ज्यादा पड़ी है। सर्दी ने इस बार पिछले 50 वर्षों का रिकार्ड तोड़ दिया है। इस सर्दी से मेरे एरिया में सरसों और जौ की फसल का बहुत नुकसान हुआ है। सरकार ने बिजली के बकाया बिल माफ किए हैं और 830 करोड़ रुपया बैंकों का ब्याज छोड़ा है। इसके अलावा भी और बहुत सी राहतें सरकार ने प्रदान की हैं। केन्द्र सरकार ने भी 60 हजार करोड़ रुपया जमीदारों का छोड़ा है। सर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि सरसों और जौ व थोड़े बहुत गेहूं की फसल का जो मेरे एरिया में नुकसान हुआ है उसकी गिरदावरी करवाकर उसका मुआवजा किसानों को दिलवाया जाए। इसी तरह से नेशनल होर्टीकल्चर मिशन ने बहुत बड़ी राशि स्टेट गवर्नमैंट को जमीदारों के लिए दी है। बागवानी के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस मिशन के तहत काफी जगहों पर बागवानी का काम शुरू करवाया जा रहा है। इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पौधे तो लगवा दिये लेकिन उनके रख-रखाव की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। आप पिछले तीन साल का रिकार्ड देख सकते हैं। 20 परसैंट पौधे भी नहीं बचे हैं। पौधे लगा तो दिये जाते हैं लेकिन उनकी मेंटीनैंस की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

इसी प्रकार से मैं सरकार के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत 500 रुपये प्रति कट्टे के ऊपर सब्सिडी दी जाती है। गेहूं के प्रति कट्टे के ऊपर 200 रुपये दिये जा रहे हैं। भिवानी सब-डिवीजन के अंदर इसके तहत 4.5 करोड़ रुपये के बिल सबमिट हुए हैं और भिवानी के लोहारू सब-डिवीजन में अब तक मात्र 4 लाख रुपये की राशि के बिल सबमिट हुए हैं। भिवानी सब-डिवीजन के अंदर 4.5 करोड़ के बिल और अकेले लोहारू के अंदर मात्र चार लाख रुपये के बिल सबमिट हुए हैं इसका कारण क्या है? जबकि लोहारू का क्षेत्रफल भी बड़ा है। इसका कारण यह है कि अधिकारियों की कमी है। भिवानी में 35 ए०डी०ओ० लगे हुए हैं जबकि लोहारू में मात्र 3 ए०डी०ओ० हैं। क्या तीन आदमी इतना काम संभाल लेंगे? इस बात पर सरकार को गौर करना चाहिए। मेरे ऐरिया के किसानों को इस बात का बहुत नुकसान हुआ है। उनको जो सबसिडी मिल सकती थी, उससे वे वंचित रह गए हैं। इसके लिए यह भी करना चाहिए जो लोग अब बिल सबमिट करना चाहते हैं तो उनको टाइम देना चाहिए ताकि वे भी अपने हिस्से की सबसिडी ले सकें। ए०डी०ओ० को आफिस किराए पर लेने के लिस 50 रुपये की राशि दी जाती है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या 50 रुपये की राशि में कोई आफिस किराए पर दे देगा? मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस राशि को बढ़ाया जाए ताकि देहात के अंदर ए०डी०ओ० बैठ सकें और वहां के किसान इस बात का फायदा उठा सकें। इसके अलावा एक और अहम समस्या भी आपके नोटिस में लाना चाहूंगा कि पेस्टीसाइड्स और खेती के बीज बहुत सी जगहों पर डुप्लीकेट दिये जाते हैं और बिल वे देते नहीं हैं। इस बारे में हर तीसरे महीने चैकिंग होनी चाहिए। चैकिंग के लिए जो किसान क्लब बना हुआ है उस किसान क्लब के मैंबर को साथ लाना चाहिए। दक्षिणी हरियाणा में पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ही ज्यादा है। एच०एल०आर०डी०सी० और सोशल कंजरवेशन डिपार्टमैंट को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैं इरीगेशन मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि कुछेक पुल जो कि आउट ऑफ नॉर्म्स हैं बहुत सी जगहों पर कंसोलिडेशन के अन्दर रास्ते कटे हुए हैं। लेकिन इरीगेशन डिपार्टमैंट के नियम में है कि एक किलोमीटर के नजदीक एक साईड और एक किलोमीटर दूसरी साईड में दो किलोमीटर के भीतर हम कोई पुल नहीं बनायेंगे। अगर कन्सोलिडेशन के अन्दर वह रास्ता नजदीक कर दिया गया है तो किसान का क्या कसूर है। उस पुल के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करो यह हम नहीं कहते लेकिन उस किसान का ट्रैक्टर तो उसके खेत में आ - जा सके, उसकी ऊंट गाड़ी तो आ जा सके। अगर ऐसे भी आप पुल बनाएंगे तो ऐसे पुल पर ज्यादा से ज्यादा दो लाख रुपये खर्च हो जाएंगे। मेरे कान्सटीच्यूंशी में ऐसे तकरीबन 15 पुल बनाने की डिमाण्ड बार-बार उठाई गई है जो निचले स्तर पर तो मंजूर हो जाती है लेकिन यहां पर आकर वह रिजैक्ट हो जाती है कि यह तो आऊट ऑफ नार्म्स है। उस जमींदार का क्या कसूर है जिसके खेत के बीचों बीच से नहर निकाली जाती है और उसको उसके खेत में जाने का रास्ता नहीं मिलता। आप कहते हैं ये नार्म्स में नहीं आते।

श्री सभापति : नार्म्स ये होने चाहिए कि जहां कन्सोलिडेशन का रास्ता छुटा है पुल उसी रास्ते पर बनाया जाना चाहिए।

श्री सोमवीर सिंह : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से रिक्वैस्ट करता हूं कि जिस किसान का 20 एकड़ का खेत है और उसके खेत के बीच से नहर निकाली गई

[श्री सोमवीर सिंह]

है और वहां पर कंसोलीडेशन का पाथ नहीं है तो इसमें किसान का क्या कसूर है? नहर निकालते समय यह देखना चाहिए कि उस किसान का खेत एक तरफ रहे और अगर ऐसा संभव नहीं हो पाया तो उसको अपने खेत में जाने के लिए एक तरफ रास्ता तो अवश्य ही दिया जाना चाहिए।

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : चेयरमैन साहब, माननीय सदस्य की यह बात बिल्कुल वाजिब है। जो नहरों पर पुल बनाने का डिस्टैंश है वह अब सरकार ने कम भी किया है। पहले यह डेढ़ किलोमीटर का था जिसे अब घटाकर एक किलोमीटर कर दिया है। लेकिन इसमें हमने यह भी कोशिश की है कि जहां गांव से गांव कनैक्ट करते हों तो उनको भी हमने टेक अप किया है। लेकिन जहां-जहां नहरों पर पुलों को बनाने की ज्यादा जरूरत पड़ती है वहां पर सरकार द्वारा आऊट ऑफ नार्म्स में भी इजाजत दी जाती है। अगर माननीय सदस्य के हलके में ऐसा कोई एरिया है जहां पर नहर पर रास्ता देने की बहुत निहायत जरूरत है तो इस पर सरकार अवश्य विचार करेगी।

श्री सोमवीर सिंह : मेरी कान्सटीच्यूंशी के ऐसे 15 केसिज हैं जो नीचे के आफिसिज से रिकमैण्ड होकर आये हुए हैं। सरकार उन पर विचार करे और कुछ तो किसानों को सुविधा दें। जिसके खेत के बीच से नहर निकली है और जहां कोई कन्सोलीडेशन का पाथ नहीं है वहां पर यह सुविधा मिलनी चाहिए। मैं मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि जो लोहारू फीडर बनाया गया था यह उस समय खासतौर पर लोहारू और बाढ़डा कान्सटीच्यूंसीज के आखरी टेल एण्ड तक पानी पहुंचाने के लिए बनाया गया था और यह बहुत समय पहले बनाया गया था। उस समय पानी की जो मात्रा दी गई थी उसके बाद उस लोहारू फीडर से कम से कम 7-8 जगह नये माईनर और नये लिंक बनाये गए हैं जैसे कि कमोद, बौंद, भागवी, मिसरी, समसपुर माण्डी, मानकावास आदि माईनर बनाये गये हैं। इस तरह से इनका नुकसान तो आखिरी एरिया में पड़ने वाले लोहारू और बाढ़डा एरियाज का ही होता है। जो पानी उस समय लोहारू फीडर और बाढ़डा एरिया के लिए मंजूर किया गया था तो इन नए माईनर्ज के निकलने से जो पानी की कमी होगी तो उन लोगों की होगी जिनका एरिया टेल एंड पर पड़ता है। वहां पर कई लिंक माईनर निकाले गए हैं। मेरी मंत्री जी से इस बारे में बात भी हुई थी उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है कि बौंद लिंक को लोहारू फीडर के साथ न जोड़ा जाए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : सभापति महोदय, यह माननीय सदस्य की सही बात है कि जितने भी कैरियर चैनल्ज हैं उसमें जो भी जगह-जगह मांग आती है विभाग ने यह निर्णय लिया है कि जहां तक हो सके उसमें से मिनिमम कैरियर चैनल्ज माईनर्ज निकाले जायें। विशेष तौर पर लोहारू और बाढ़ड़ा के इलाकों में जहां पीने का पानी नहीं पहुंच पाता है और जहां पानी की चोरी भी होती हैं क्योंकि लोग बीच में सीधे पम्प लगा लेते हैं। माननीय सदस्य ने इस बारे में मुझ से दूरभाष पर भी यह बात की थी। तब विभाग ने इस बारे में मीटिंग ली थी हमने फैसला किया है कि इस प्रकार के सब माईनर कैरियर चैनल्ज न निकाले जायें।

श्री सभापति : जब हांसी-बुटाना लिंक नहर बन जायेगी तो पूरा पानी आ जायेगा और यह समस्या हल हो जायेगी। पानी की अवेलेब्लिटी बढ़ जायेगी।

श्री सोमवीर सिंह : माननीय मंत्री जी से मैंने इस बारे में टेलीफोन पर भी बात की थी कि लोहारू फीडर के ऊपर परमानैंट मोरियों में से इतना पानी नहीं जाता जितना इंजन लगाकर पानी चोरी करके जाता है, कई जगह 8-8 इंच मोटे पाईप परमानैंट लगा रखें हैं और वह चलते भी हैं। अब आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां आठ इंची पाईप नाजायज लग रहे हों और सैकड़ों इंजन नाजायज लगा रखे हों तो आगे पानी कैसे जा सकता है? मैं दावे के साथ कहता हूं कि 7 और 8 तारीख को लोहरवाड़ा और मोरवाला गांव में ऐसी चोरी के केस पकड़े गये थे। जब उन पर विभाग ने ऐक्शन लिया तो लोगों ने रास्ता जाम कर दिया और उनको छोड़ दिया गया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या रास्ता जाम करके पानी की चोरी कर सकते हैं क्योंकि इससे लोगों का नुकसान हो रहा है? अगर ऐसा है तो हम भी रास्ता जाम करवाना शुरू करवा देते हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सख्ती बरतें। उन लोगों के ऊपर भी केस बनाए गए थे। इस बात का आप अपने अधिकारियों से पता करवा लें और डी०सी० से भी पता करवा लें। रास्ते जाम होने की वजह से उन पर से केस भी वापिस हुए थे। उन लोगों को पानी की चोरी करने के लिए पूरी छूट दे रखी थी। जिस दिन से नहर बनी है लोहारू में टेल तक पानी नहीं पहुंचा।

11.00 बजे

कैप्टन अजय सिंह यादव : सभापति महोदय, इन्होंने मुझे परसों सूचना दी थी तो मैंने उसी समय डी०सी० भिवानी और डी०सी० झज्जर से बात की और उनसे कहा कि जहां-जहां इस प्रकार बड़े-बड़े पाईप लगा रखे हैं जिसकी वजह से आगे के एरियाज में पीने का पानी नहीं पहुंच पाता, वहां आप सख्ती से कार्यवाही करें। मैं माननीय साथी को कहना चाहूंगा कि जो इस प्रकार के इलीगल पाईप लगाते हैं उनकी कतई मदद न करें। हमारी पूरी कोशिश है कि इस प्रकार की पानी की चोरियां न हों। इनके कहने पर ही मैंने उसी समय डी०सी०, भिवानी और डी०सी०, झज्जर से बात की थी।

श्री सोमवीर सिंह : तहसील में इस तरह की मैक्सिमम चोरियां हो रही हैं। वहां आपके अधिकारी जाते हैं और तावान लगा देते हैं लेकिन तावान न कोई पे करता है और न कोई तावान से डरता है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप इसके लिए पुलिस की मदद लें और एक्स्ट्रा कर्मचारियों की मदद लें।

श्री सभापति : सोमवीर जी, मंत्री जी ने पूरा आश्वासन दे दिया है इसलिए आप अगला प्वांयट लें।

श्री सोमवीर सिंह : सभापति महोदय, पम्प हाउस नं० 1 से लेकर 8 तक के लिए महकमे ने बिजली की इंडीपैंडैंट लाइन 1970 में ली थी। वहां पर डिपार्टमैंट ने अलग से अतिरिक्त पैसा जमा भी करवाया था। हर महीने करीब डेढ़ करोड़ रुपये का बिल इरीगेशन डिपार्टमैंट पे कर रहा है। लेकिन जो बिजली की लाइनें बिछी हुई हैं उन लाइनों से पी०डब्ल्यू०डी० ने, पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट ने और आई०टी०आई०, बेरला ने भी अलग से कनैक्शन लिए हुए हैं। इन कनैक्शनों की वजह से पम्प हाउसिज पर पूरी वोल्टेज नहीं पहुंच पाती। बार-बार ट्रिपिंग होती है। पीछे से कुछ पम्प चलें और आगे लोड़ नहीं उठता तो उसका कोई फायदा नहीं। हमने बार-बार विधान सभा में यह बात उठाई है कि बिजली नहीं

[श्री सोमवीर सिंह]

मिल रही है हमें बिजली पूरी देने के आश्वासन मिलते रहे हैं और कहा जाता रहा है कि ये कनैक्शन हटवा दिए जाएंगे लेकिन आज तक ये कनैक्शन नहीं हटे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसके लिए कोई टाईम निश्चित कर दें कि इतने समय के बाद ये कनैक्शन हटा देंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : सभापति महोदय, इस इशू के बारे में इनका प्रश्न 678 भी लगा है। यह बात सही है कि पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट को पीने का पानी भी देना होता है, कुछ कनैक्शन पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट ने उन फीडर्स से ले रखे हैं। मैंने पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर से कहा था कि वे बिजली के अधिकारियों को कहें कि या तो उनको अलग से फीडर दें और अगर दिक्कत है तो कम से कम वहां की कैपेसिटी को बढ़ाएं। जहां तक आई०टी०आई बेरला के कनैक्शन लेने के बारे में बात है तो उसके बारे में आदेश दिए गए हैं कि उसका कनैक्शन डिस्कनैक्ट कर दें लेकिन जो प्राइवेट जमींदारों को कनैक्शन देने की बात है तो हमने कोई प्राइवेट जमींदारों को कनैक्शन नहीं दे रखे हैं और अगर कोई ऐसी बात आपके नोटिस में आती है तो आप बताएं उन कनैक्शनों को हम हटवा देंगे। जहां तक पीने के पानी की समस्या है तो उस समस्या को भी दूर करने के लिए हम कदम उठाएंगे।

श्री सभापति : मंत्री जी, इन्होंने प्राइवेट कनैक्शन की बात नहीं की बल्कि चोरी रोकने की बात कही है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : सभापति महोदय, इन्होंने प्राइवेट कनैक्शन की बात की है। जहां तक पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट की बात है तो अगर वे ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन एकदम हटवाएंगे तो दिक्कत आएगी। हमने पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर को कहा था कि इस मामले में कार्यवाही करें और अलग से इंडीपैंडैंट फीडर लगवाएं ताकि हमारे पम्प हाउसिज पर इस तरह की दिक्कत न आ सके। हम कोशिश करेंगे कि वोल्टेज को बढ़ाएं ताकि बार-बार ट्रिपिंग भी न हो।

श्री सोमवीर सिंह : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट ने या पी०डब्ल्यू०डी० ने जो कनैक्शन वहां पर ले रखे हैं उनके लिए एक टाईम निश्चित करें कि कितने टाईम बाद ये कनैक्शन हटा लेंगे।

श्री सभापति : सोमवीर जी, यह प्रश्नकाल नहीं है। आप अपनी बात रखें।

श्री सोमवीर सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूं, ये अपने आप जवाब दे रहे हैं। मैं तो अपनी बात बोलूंगा ही। सभापति महोदय बेरला में पम्प हाउस नं० 6 और 7 को बिजली के कनैक्शन दिए जा रहे हैं। पम्प नं० 6 और 7 को अलग-अलग जगह से कनैक्शन दिए जा रहे हैं। एक जगह से बिजली चली जाती है तो दूसरा पम्प पानी नहीं उठा पाता इसलिए मेरी प्रार्थना है कि पम्प 6 और 7 दोनों को एक जगह से कनैक्शन दिया जाए ताकि बिजली आए तो पानी दोनों जगह से चल सके। अब एक जगह पानी चल पड़ता है और दूसरी जगह पम्प पानी नहीं उठा पाता। सभापति महोदय, बाढ़ड़ा और लोहारू जैसे रेतीले इलाकों के लिए 1970 में लिफ्ट इरीगेशन सिस्टम बनाया गया था। सभापति

महोदय, आपको भी अच्छी तरह से मालूम है कि जितने पानी की जरूरत आज करनाल, सोनीपत और रोहतक जिलों के अंदर एक एकड़ जमीन की सिंचाई करने में पड़ती है लोहारू और बाढ़ड़ा के अंदर एक एकड़ जमीन की सिंचाई करने के लिए उनसे अधिक पानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो वाटर अलाउंस लोहारू और बाढ़ड़ा के लिए पहले थे वह अब दोबारा से शुरू किया जाये। सभापति महोदय, लोहारू और बाढ़ड़ा के लिए 3.05 क्यूसिक पानी प्रति एक हजार एकड़ के लिए अलॉट किया गया था और हमारा टोटल 1380 क्यूसिक पानी बनता है जिसको पिछली सरकार ने कम करके 2.40 क्यूसिक प्रति हजार एकड़ के हिसाब से करके हमारी जनता के साथ बहुत नाइंसाफी की। पिछली सरकार की नाइंसाफी की वजह से लोहारू और बाढ़ड़ा का पानी कम होकर 850 क्यूसिक रह गया। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि लोहारू और बाढ़ड़ा के लिए 3.05 क्यूसिक पानी प्रति एक हजार एकड़ के हिसाब से अलाउ किया जाये ताकि वहां के लोगों को पूरा पानी मिल सके। सभापति महोदय, मैं एक प्रार्थना और करना चाहता हूं। जैसा कि मैं चोरी की बात कर रहा था कि अगर आप पानी को जितने ज्यादा दिन तक चलायेंगे उतना ज्यादा नुकसान लोहारू हल्के को होगा क्योंकि 16 की बजाए 20 दिन 400-400 क्यूसिक या 200-200 क्यूसिक पानी नहर में चलेगा तो लोहारू तक पानी नहीं पहुंचेगा, पहले ही पानी चोरी होता रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि मंत्री जी 8-8 दिन ही इकट्ठा पानी लोहारू हल्के के लिए चलायें ताकि वहां तक पानी पहुंच सके। अगर इनके अधिकारी कहते हैं कि इकट्ठा ज्यादा पानी पम्पस नहीं उठा सकते तो ये उनमें इम्प्रूवमैंट करें या एक्सट्रा पम्प लगायें। सभापति महोदय, दादरी हल्के के अंदर 37 वाटर वर्क्स नये बनाये गये हैं और बाढ़ड़ा के अंदर भी नये वाटर वर्क्स बनाये गये हैं। उन वाटर वर्क्स के लिए अलग से पानी अलॉट नहीं किया गया है। जब तक वे वाटर वर्क्स नहीं भरते किसानों को पानी नहीं मिलता। किसान तो सोचते हैं कि उसमें भी चोरी कर लें। जब अधिकारियों से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि फलां जगह का वाटर वर्क्स भर रहे हैं, कभी कह देते हैं फलां जगह का वाटर वर्क्स भर रहे हैं और हकीकत में कहीं का भी वाटर वर्क्स नहीं भरते और न ही किसानों को पानी देते हैं। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि जो 7-8 दिन निश्चित कर रखे हैं उनमें भिवानी या दादरी के वाटर वर्क्स भरते हैं तो भरें और नहीं भरते हैं तो न भरें लेकिन लोहारू के लिए जितना पानी अलाउड है वह पानी लोहारू को अवश्य मिले। सभापति महोदय, इसी तरह से बीन्द्रावण पम्प हाउस है वहां पर 1998-99 के बीच काफी पानी मिलता था जिससे 8-9 मोटरें पानी उठाती थी और लोहारू डिस्ट्रीब्यूटरी के ऊपर दमगोरा गांव तक पानी चलता था। लेकिन अब 4-5 मोटरें भी वहां पर नहीं चल पाती क्योंकि पानी बहुत कम मिलता है। इसलिए मंत्री जी इस बात के लिए इंश्योर करें कि जैसे वहां पहले पानी मिलता था उसी तरह से पानी मिले। सभापति महोदय, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि कमोद, समसपुर और लोहरवाड़ा आदि गांवों की तरफ भी मंत्री जी ध्यान दें। कई गांवों में सेम की समस्या है उनकी तरफ भी मंत्री जी ध्यान दें। कई गांवों में मोरी नहीं लगी हुई वहां के किसान पानी की चोरी करके धान की बिजाई करते हैं उस तरफ भी मंत्री जी ध्यान दें। चरखी और मानकावास आदि गांवों की तरफ भी मंत्री जी ध्यान दें। सभापति महोदय, जूई नहर के अंदर 8 दिन इकट्ठा पानी मिलता है मैं चाहता हूं कि उसी तरह से लोहारू के अंदर भी इकट्ठा पानी दिया जाये और पहले जो 1380 क्यूसिक पानी हमें अलॉट था वह दोबारा

[श्री सोमवीर सिंह]

से मिलना चाहिए। इसके साथ-साथ मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि लोहारू और बाढ़ड़ा के अंदर अधिकतर खालें कच्चे हैं उन्हें पक्का किया जाये ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया की सिंचाई हो सके। सभापति महोदय, अब मैं रोडवेज के बारे में जिक्र करना चाहूंगा कि मेरे हल्के के जिन गांवों में पहले बसें चलती थी अब वहां नहीं चल रही। नांगल बाजू से बुढ़ड़ी और सिवाणा से बुधशैली, बिधवाण, मण्डौली खुर्द और बहल आदि गांवों में इस समय बसें नहीं चल रही। मंडौली खुर्द है, बहल है ये काफी लम्बे रूट हैं इनके ऊपर कोई बस नहीं चलती। पहले तो वहां पर एक पुल की प्रॉब्लम बताई जाती थी लेकिन वह पुल भी अब नहरी डिपार्टमैंट ने चौड़ा कर दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वहां पर बस सेवा प्रदान की जाये। रोड्स के बारे में भी मैं आपके माध्यम से खासतौर से मंत्री महोदय जी से कहना चाहूंगा कि जो तोशाम, बहल और शुद्धिवास रोड़ है अगर आप उस रोड से जाते हैं तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी जीप को नहीं चलाया जा सकता। इसलिए उस सड़क पर विशेष तौर से गौर करनी चाहिए। बाकी मेरी कांस्टीच्यूएंशी के साथ बड़ी रेल लाईन गुजर रही है वहां पर पहाड़ों से बजरी, पत्थर, कंकर लेकर डम्पर जाते हैं जिनकी वजह से ज्यादातर रोडस का बहुत बुरा हाल है तो मैं चाहूंगा कि गिगनाऊ से लेकर सहर, पहाड़ी और मानफरा से बहल तक इस रोड का खासतौर से ध्यान दिया जाये और जैसे कुछ एक गांवों के अन्दर जो सड़कें बनी हुई हैं वे बहुत ही नीचे में हैं और वहां पर पानी भर जाता है। इस बात को मैंने कई बार संबंधित अधिकारियों के नोटिस में भी लाया और आज फिर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि खासतौर से बडदू जोगी जो गांव है वहां रोडस की इतनी बुरी हालत है और वहां पर हर वक्त कीचड़ भरा रहता है जिससे उस पर पैदल चलना भी मुश्किल होता है। ऐसे कुछ एक और गांवों के बारे में भी मैंने लिखकर दिया हुआ है जहां पर रोडस पर पानी खड़ा रहता है। गुडेडी गांव है और भी कई गांव है जैसे कुशलपुरा है जहां की रोड पर पानी भरता है उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सभापति महोदय, खासतौर से मैं सिवानी जो कि एक सब-डिवीजन है, के बारे में जिक्र करना चाहता हूं कि वहां पर पी०एच०सी० है। उस सब-डिवीजन के अन्दर घुरेरा, लीलस, बड़वा और झुप्पा गांव भी आते हैं लेकिन वहां पर पी०एच०सी० एक है तो मैं आपके माध्यम से हैल्थ मिनिस्टर से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वहां पर 50 बिस्तर का एक हॉस्पिटल बनाया जाये ताकि लोगों को सुविधा हो सके। यह बड़ी शोचनीय बात है कि उस सब-डिवीजन में एक ही पी०एच०सी० है और वहां पर भी कोई डाक्टर नहीं है। 2-3 बातें और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। मैं खासतौर से सिवानी-बड़वा का जिक्र करना चाहता हूं। वहां पर एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग एक सेठ द्वारा बनाई गई है वहां पर हॉस्पिटल चल रहा है लेकिन उस बिल्डिंग की बहुत बुरी हालत है। **(इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)** इस बारे में हम अगर महकमें वालों से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि रिपेयर तो हम नहीं करवा सकते क्योंकि इसका कब्जा हमारे पास नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस बारे में भी कुछ कारगर कदम उठाये जायें। उस बिल्डिंग को अपने कब्जे में लेकर उसकी रिपेयर की जाये क्योंकि इतनी अच्छी और बड़ी बिल्डिंग आपको मुफ्त में मिल रही है उसका आपको फायदा उठाना चाहिए और इसकी समुचित व्यवस्था की ओर

ध्यान देना चाहिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह तीसरा दिन है लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विपक्ष के लोगों को आज तक बोलने का अवसर ही प्रदान नहीं किया गया है। यह तो आपको तय करना चाहिए कि हमें बोलने का अवसर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, अभी तक राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर 85 मिनट का समय अपोजीशन के लिए दिया गया है जिसमें निर्दलीय श्री अर्जुन सिंह 9 मिनट बोले और श्री सुखबीर सिंह फरमाणा 9 मिनट बोले। भारतीय जनता पार्टी के श्री नरेश मलिक 20 मिनट बोले और आप स्वयं 43 मिनट बोले यानि 43 मिनट तक आप ऑन लैग रहे। ठीक है, अगर आप अब बोलना चाहते हैं तो बोलिए I allow you.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह टाइम की शर्त भी इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्यों पर ही लागू होती है क्योंकि इससे पहले तो बोलने वाले बहुत लम्बे समय तक बोलते रहे हैं और आप भी बड़े बुलन्दबांग दावे करते रहे हैं कि पहली मर्तबा इतने लम्बे समय तक सैशन चला है। इतने दिन का सैशन है मुख्यमंत्री जी को 17 मार्च को जवाब देना है उससे पहले तो समय ही समय है इसमें आप कंजूसी किस बात की कर रहे हैं। सभी को बोलने के लिए पूरा समय मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप बोलिए, आपको समय दिया जाता है किसी प्रकार की कंजूसी नहीं है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, शुक्र है आपने मुझे अवसर प्रदान किया। गवर्नर के अभिभाषण पर चर्चाएं चल रही हैं। गवर्नर के अभिभाषण को पढ़ने से ऐसा जाहिर हो रहा है कि यह बिल्कुल नीरस अभिभाषण था, कोई किसी प्रकार से कहीं न कोई रिलीफ दिया गया है और न कोई आगे के लिए व्यवस्था है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ये सब बातें तो आप पहले भी कह चुके हैं फिर इनको दोहराने की क्या जरूरत है?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : मैंने क्या कहा, क्या नहीं कहा यह मेरा काम है। वह तो आपने कह दिया था कि रिकॉर्ड न किया जाये।

श्री अध्यक्ष : यह आपका रिकॉर्ड में है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : रिकॉर्ड में है या नहीं है वह तो रिकॉर्ड देखने के बाद ही पता चलेगा। मेरा कहने का भाव यह था कि गर्वनर के अभिभाषण में एक बात पर बड़ा जोर दिया गया है जो विशेष रूप से मैं समझता हूं कि विधान सभा के दायरे क्षेत्र में थी ही नहीं लेकिन केन्द्र की कर्जा माफी घोषणा को बहुत प्रचारित किया गया। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि इसका लाभ किन-किन लोगों को मिला है? इसमें कई किस्म की शर्तें लगाई गई हैं। छोटे-बड़े किसानों का हवाला भी उसमें दिया गया है, जो डिफाल्टर हैं उनका क्या होगा, इन सब बातों की क्लैरीफिकेशन नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि अर्थशास्त्रियों की तरफ से भी ब्यान आयें हैं कि इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं उस बहस में नहीं जाना चाहूंगा लेकिन उसमें मुतजात किस्म के बयान आये हैं। गवर्नर के अभिभाषण के पेज 5 पर पैरा 9 में जिक्र आया है कि सहकारी बैंकों के 451 करोड़ रुपये के लोन के ब्याज माफ हुए

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

हैं जबकि मुख्यमंत्री का बयान छपा है कि 830 करोड़ रुपये के ब्याज माफ हुए हैं। मुख्यमंत्री का दूसरा बयान छपा है कि 800 करोड़ रुपये का ब्याज माफ हुआ है।

श्री अध्यक्ष : इस पर माननीय वित्त मंत्री महोदय ने क्लैरिफिकेशन दे दी थी कि माफी की योजना में 830 करोड़ रुपये आये हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आपको इसमें क्या आपत्ति है? इसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी देंगे। जब वे जवाब देंगे तो इस बात को क्लीयर कर देंगे लेकिन जो चर्चा आई है तो उसका जिक्र तो मैं करूंगा। उसका जिक्र करना मेरा अधिकार है। यह बात समझ नहीं आ रही है कि इनमें से कौन सी बात ठीक है और कौन सी बात गलत है? मुख्यमंत्री जी के भी दो मुखतलिफ बयान आये हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि 830 करोड़ रुपये के कर्ज माफ हुए हैं जबकि दूसरे में कहा कि 800 करोड़ रुपये के कर्ज माफ हुए हैं। इसके साथ-साथ मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि केन्द्र के फैसले से 10-11 लाख किसानों को लाभ मिलेगा जबकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3 लाख 7 हजार किसान लाभान्वित होंगे। (शोर एवं व्यवधान)

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह सिलसिला फिर से शुरू हो गया तो कैसे काम चलेगा? यह तो तय किया जाये कि किस बात का प्वायंट ऑफ ऑर्डर है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : आप सुनेंगे तो ही पता चलेगा कि किस बात का प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है वैसे कैसे पता चलेगा आपको?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हर सदस्य को अपनी बात कहने का अधिकार है और सरकार को उसका रिप्लाई देना चाहिए। अगर कोई गलत बयान करता है तो उसमें लिखा जायेगा।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, अगर हाउस को बरगलाया जायेगा, कोई सदन को गुमराह करने की कोशिश करेगा तो हमारा यह अधिकार है कि हम सही तथ्य सदन के सामने रखें, सच को सदन के सामने लायें उसमें चाहे चौटाला जी हों या और कोई माननीय सदस्य हो। सदन में कोई सम्मानित सदस्य गैर जिम्मेदाराना बात करेगा तो सरकार को तो तथ्य रखने ही पड़ेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, सही बात तो यह है कि यह बात उस दिन भी आई थी और चौटाला जी ने आज फिर शुरू कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह स्पष्ट कहा था कि 830 करोड़ रुपये की माफी दी गई है। उसमें से जो राशि गवर्नर के अभिभाषण के अन्दर दी गई है यह वह राशि है जो लाभ अब तक ले चुके हैं और वित्त

मंत्री जी ने खड़े होकर यह बात कही थी। मुख्यमंत्री जी को कोट करके बार-बार इस हाउस को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। इन्होंने कहा कि 11 लाख लोगों को लाभ होगा और कभी कहते हैं कि 3 लाख 20 हजार लोन पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, एक ऐतिहासिक फैसला भारत की सरकार ने श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में लिया। 4 करोड़ किसान हैं जिनको पूरे देश के अन्दर 60 हजार करोड़ रुपये की ऋण माफी का लाभ होने वाला है। ऐसा न आज तक हिन्दुस्तान के इतिहास में हुआ और न कोई सरकार कर पाई। इस प्रकार का ऐतिहासिक निर्णय अपने आप में एक बहुत साहसिक कदम था। उन 4 करोड़ में हरियाणा के कितने लोगों को कर्जों का लाभ होगा वह सरकार की केवल अनुमानित फिगर थी कि तकरीबन 4 से 5 हजार करोड़ शायद हरियाणा प्रदेश का भी होगा। स्पीकर सर, अभी यह फिगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सच बात तो यह है कि कई दल ऐसे हैं जिनसे यह बात न निगले बनती है न उगले बनती है। इसके लिए वे न तो सरकार की तारीफ कर पा रहे है न वे उसकी आलोचना कर पा रहे हैं। वे इसको किसी सर्कूटियस तरीके से घुमा कर प्रश्न चिन्ह पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, None less than the Prime Minister of the country has said on the floor of the Parliament that by 30th June, 2008 साठ के साठ करोड़ रुपये के ऋण मुआफी का लाभ हिन्दुस्तान के किसान को मिलने वाला है। 30 जून, 2008 तक इन्तजार कीजिए जो तथ्य और आंकड़े हैं वे सबके सामने हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि कम से कम खड़े हो कर इसकी तारीफ तो करें। (विघ्न) 1600 करोड़ रुपये की जो बिजली बिलों की ऋण मुआफी की थी उसमें से एक हजार करोड़ रुपये का लाभ बिजली उपभोक्ताओं को पहुंच चुका है। अध्यक्ष महोदय, लोक दल के साथियों की यह मानसिकता बन गई है कि खुद तो कुछ करना नहीं और जब कोई दूसरा कुछ करेगा तो उसके अन्दर मीन-मेख निकालने का प्रयास करेंगे। आज चौटाला साहब भी यही कर रहे हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे यह कहना चाहता हूं कि जोर से बोल कर ये इस बात को झुठला नहीं सकते हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात को थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा प्वायंट ऑफ ऑर्डर की आड़ लेकर इनको भाषण झाड़ने की जरूरत नहीं है। मेरा एक अधिकार है और मैं उसी अधिकार से अपनी बात कह रहा हूं। अगर मैं कोई गलत बयानी करता हूं या सरकार को कोई सुझाव देता हूं तो उसका जवाब रिप्लाई में लीडर ऑफ दि हाउस देंगे और उसमें सारी बात क्लीयर हो जाएगी। अगर एक-एक बात को लेकर बीच में इस प्रकार से डिस्टरबैंस की जाएगी तो फिर समय बर्बाद होगा (विघ्न) फिर आपकी सोच भी ऐसी है कि फिर उसके मिनट दर्ज करते चले जाएंगे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आप कांटीन्यू करें। (विघ्न) चौटाला साहब, आप भी भाषण न दें और कान्टीन्यू करें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह क्या है इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है लेकिन जो आंकड़े हैं वे लोगों के सामने आ रहे हैं। जिस प्रकार की चिन्ताएं व्यक्त की जा रही हैं उन चिन्ताओं के दृष्टिगत ही मैं भी अपनी चिन्ता प्रकट करता हूं कि अभी यह क्लीयर नहीं है कि कितना कर्ज मुआफ हुआ है। उसमें छोटे और बड़े किसान का भी हवाला दिया गया है। अभी पार्लियामैंट्री अफेयर मिनिस्टर ने कहा कि यह सबसे पहला अवसर है

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

कि इस प्रकार का लाभ किसानों को मिला है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1990 में स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी ने दस हजार रुपये तक के कर्ज जो हर किसान के ऊपर चढ़े हुए थे वे मुआफ किये थे। उसमें किसी भी छोटे या बड़े किसान की कोई बात नहीं थी। उस दस हजार रुपये तक के कर्ज मुआफ होने में वित्तीय संस्थान थे। सहकारी बैंकों के भी कर्जे थे और दूसरे बैंकों के भी कर्जे थे। वे दस हजार रुपये तक मुआफ हुए थे। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने थोड़ा सा रवैया बदला है, यह बहुत अच्छा है। यह परम्परा बहुत अच्छी है और मैं इसकी सराहना करता हूं।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, यह ऐटीच्यूड की बात है। अगर आप खुद बदल गये हों तो आपको सब बदला हुआ नजर आ रहा है। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रहा था कि 13 मार्च, 1992 को श्री पी०वी० नरसिम्हा राव जी कांग्रेस पार्टी के प्रधान मंत्री थे और केन्द्र में उनकी सरकार थी। उस वक्त इस सदन के एक सम्मानित सदस्य जो आज यहां पर उपस्थित नहीं है और आपकी कलम के नीचे आए हुए हैं। आप उनके बारे में क्या निर्णय लेते हैं यह तो आपका फैसला है। श्री धर्मपाल मलिक जी ने उस वक्त एक सवाल पूछा था कि कितने कर्जे मुआफ हुए हैं तो उसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री श्री दलबीर सिंह का बयान आया कि इस में केन्द्र सरकार पर कुल 7714 करोड़ रुपये का सीधा भार पड़ेगा और 4400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार प्रदेश सरकारों पर है। कुल मिला कर 16514 करोड़ रुपये के कर्ज उस वक्त मुआफ हुए थे और उसमें कोई if-but या किन्तु-परन्तु नहीं था केवल एक सोच थी कि गरीब किसान को राहत मिल सके इस बात को दृष्टिगत रखकर यह निर्णय लिया गया था।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, यह तो चौधरी सम्पत सिंह जी का बयान था।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं बयान की बात नहीं कर रहा हूं मैं रिकॉर्ड की बात कह रहा हूं और पार्लियामैंट में जो जिक्र आया है मैं उसका जिक्र करता हूं। उस वक्त के रुपये की और इस वक्त के रुपये की अगर वैल्यू आंकी जाए तो वह जो पैसा था वह 16514 करोड़ रुपये बनता है जिनके कर्जे मुआफ हुए थे वे एक लाख 32 हजार करोड़ रुपये के बनते हैं। (विघ्न) आज की तारीख में वह एक लाख 32 हजार करोड़ बनता है। कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया था गुप्ता जी। कांग्रेस की सरकार बाद में 1991 में बनी थी और उस वक्त के वित्त राज्य मंत्री दलबीर सिंह ने एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया था। यह जो कर्जा था वह उप-प्रधानमंत्री चौधरी देवी लाल जी ने माफ किया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, हमारे पास आंकड़े हैं और वे यह स्पष्ट दर्शाते हैं कि जब चौधरी देवी लाल जी की सरकार के समय में कर्जा माफ करने की स्कीम आई थी तो उस समय केवल 32 करोड़ रुपए ही माफ किए गए थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही हैरानी होती है कि जिम्मेवारी के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसी बात कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं लोक सभा में दिए बयान आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूं। मंत्री जी सरकारी आंकड़ों की अनदेखी करके उसके बारे में गलत बयानी करने की चेष्टा यहां पर कर रहे हैं। आपके इस सदन में वैसे भी गलत बयानी करना मुनासिब नहीं है, मैं यह सरकारी आंकड़े बता रहा हूं। यह उस वक्त के रिकार्ड की चीज है और मैं यह वित्त मंत्री जी का जवाब बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इसका क्या लाभ होगा और किसको होगा यह तो समय ही बताएगा। चौधरी देवी लाल जी ने उस वक्त कोई राजनीतिक लाभ उठाने की चेष्टा नहीं की थी। उनकी ईमानदारी से यह मन्शा थी कि इस प्रदेश का कृषक सम्पन्न, समृद्ध और खुशहाल हो। इसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किए थे। अध्यक्ष महोदय आज किसानों की हालत सबसे ज्यादा दयनीय है। उनके कर्जे माफ हों यह बहुत अच्छी बात है अगर टोटल कर्जे माफ होंगे तो आगे के लिए किसानों की सोच कैसे ठीक हो इसके लिए सरकार की तरफ से गठित स्वामी नाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए तो सभी को लाभ मिलेगा, पूरे देश को लाभ पहुंचेगा। आज केन्द्र की सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। अगर कोई बात है तो केवल सोच का अन्तर है। उस सोच के अन्तर्गत अगर किसानों को लाभ दिया जाए और आगे के लिए किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए कि उनको भविष्य में कर्जा न लेना पड़े। अगर यह गलत परम्परा चलती रहेगी और कर्जा माफी होती रहेगी तो उसका फायदा तो हमेशा डिफाल्टर लोग ही उठाते रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह गलत परम्परा कायम न हो इसके लिए आज हमारे कृषि प्रधान प्रदेश की सरकार की तरफ से किसानों की समृद्धि के लिए कोई ऐसी समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। आज अभी कुछ मैम्बर्ज ने भी जिक्र किया है कि इस साल न तो किसानों को बिजली मिली है न पानी मिला है। अध्यक्ष महोदय, आप सुनकर हैरान होंगे कि जब से भाखड़ा नहर बनी है तब से लेकर भाखड़ा का क्लोजर चौथे महीने में या 10वें महीने में होता था और फुर्सत का समय देखकर उसकी मरम्मत की जाती थी। लेकिन इस साल 24 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक क्लोजर हुआ है। उसकी वजह से किसानों की फसल पूर्ण रूप से बरबाद हो गई है। वह ऐसा पीरियड है जिसमें किसानों की फसल पूरी तरह से पकती है। अध्यक्ष महोदय, आप खुद किसान हैं, आपको इन सारे हालात का ज्ञान है। पता नहीं किस सोच के चलते हुए इस समय क्लोजर कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, किसान को इस बार ठंड की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। जैसा कि सोमवीर सिंह जी ने बताया है कि सरसों और जौं की फसल का नुकसान हुआ है, इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि केवल इन्हीं फसलों का ही नुकसान नहीं हुआ है बल्कि कनक की फसल का भी नुकसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यह जो ठण्ड पड़ी थी यह सूखी ठण्ड थी और इसकी वजह से कनक में पूरी तरह से फूटारा नहीं आ पाया था। अब जो एकलखत गर्मी आ गई है इसकी वजह से वह वहीं पर सूख जाएगी। इसकी वजह से कनक की फसल का बुरी तरह से नुकसान हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को चाहिए कि जहां पर ये जो इतनी फिराखदिली दिखा रहे हैं, उसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बारे में हमारा मानना है कि ये उसका राजनीतिक लाभ उठाएं लेकिन उसका किसानों को लाभ तो मिलना चाहिए। यह जो ठण्ड की वजह से किसानों की फसल बरबाद हो रही है उसके लिए भी सरकार निर्धारित मुआवजा किसानों को दे ताकि

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

प्रदेश का किसान सम्पन्न, समृद्ध और खुशहाल हो सके। अगर हमारा किसान सम्पन्न, समृद्ध और खुशहाल होगा तो वह हौंसले से ज्यादा पैदावार बढ़ाएगा। इसकी वजह से हमारी सरकार की जो सोच विदेशों से गेहूं खरीदने की है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था स्थापित की जाए तो इस देश के गोदाम पहले भी किसानों ने ठसाठस भरने की कोशिश की थी, इस बार वे पुनः गोदाम भर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, एन०डी०ए० की सरकार के वक्त में ऐसी स्थिति आ गई थी कि कहीं सरकारी गोदामों से गेहूं समुद्र में न फेंकना पड़े। अध्यक्ष महोदय, इसलिए फूड फॉर वर्क के तहत गांव-गांव में गेहूं भेजा गया था ताकि उसका सही उपयोग हो सके। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे हालत यह हो गए हैं कि हम यह बात तो करते हैं कि हमने किसानों को बड़े भारी भाव दिए हैं लेकिन यह भूल जाते हैं कि किसानों की लागत के दाम किस रेशो से बढ़ रहे हैं। खाद के दाम, बिजली के दाम, डीजल के दाम और पैट्रोल के दाम किस रेशो से बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के बनने के बाद पैट्रोल और डीजल के दाम 6 मर्तबा बढ़े हैं यानि कि किसानों की लागत का मूल्य बढ़ा है। अध्यक्ष महोदय, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों की जो लागत है उस पर 50 प्रतिशत और पैसा देकर किसानों को लाभ दिया जाए। इस किस्म की सोच सरकार की होनी चाहिए, लेकिन यह सोच नहीं है। सरकार की सोच तो केवल राजनैतिक लाभ उठाने की है। अगर ये राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं तो उठाएं लेकिन यह पिक्चर भी आने वाले समय में पूरी हो जाएगी। इनके साथ भी वही होगा जो दूसरी सरकारों के साथ पहले होता रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही यहां पर सिंचाई की बात आई और यह जिक्र किया गया था कि नहरों में पानी की दिक्कत आ रही है और प्रस्तावक ने यहां तक भी जिक्र किया था कि एस०वाई०एल० नहर पर बहुत काम हुआ है। अध्यक्ष महोदय, एस०वाई०एल० नहर तो हमारी जीवन रेखा है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसका बहुत मामूली सा जिक्र आया है कि सरकार यह नहर बनाएगी जबकि एस०वाई०एल० नहर के प्रति किसी भी अदालत में कोई फैसला विचाराधीन नहीं है इसलिए सरकार की जिम्मेवारी है कि वह इस नहर को जल्दी से जल्दी बनाए। आज हरियाणा में और केन्द्र के स्तर पर कांग्रेस की सरकार है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि इस नहर को केन्द्र की सरकार बनाए। इस प्रदेश में कांग्रेस की अध्यक्षा तीन मर्तबा आयीं और तीनों मर्तबा न मुख्यमंत्री की ओर से और न किसी ओर की तरफ से एस०वाई०एल० नहर का जिक्र किया गया। इसके अलावा जब मुख्यमंत्रियों की एक कान्फ्रैंस चण्डीगढ़ में हुई थी तो वह एक बहुत अहम मौका था लेकिन उस वक्त भी इस अहम मुद्दे पर किसी ने इस नहर का जिक्र नहीं किया।

Mr. Speaker : Chaudhary Sahib, presidential reference is pending before the Supreme Court. जो फैक्चुअल पोजीशन है आप उस पर बोलें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे अपनी बात तो कहने दीजिए। एस०वाई०एल० नहर से संबंधित कोई भी फैसला आज अदालत के विचाराधीन नहीं है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, फैक्चुअली दो बातें है जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब गलत कह रहे हैं। एस०वाई०एल० नहर के निर्माण को लेकर कांग्रेस पार्टी की उस समय की सरकार ने जो मुकदमा दायर किया था और उस मुकदमे का हमारे

हक में जो फैसला हुआ था। उसके बाद पंजाब की विधान सभा जिसमें इनके मित्र भी शामिल थे और जिसमें कांग्रेस की उस समय की सरकार भी शामिल थी, ने मिलकर एक ऐसा कानून पारित किया था जिसका उनको अधिकार नहीं था।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आप यह बताएं कि क्या हरियाणा सरकार ने इसको चैलैंज किया था?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, उस समय की हरियाणा सरकार जिसके मुखिया ओम प्रकाश चौटाला जी थे, ने यह जहमत नहीं की कि वह हरियाणा के अधिकारों की सुरक्षा करें और उस गैर कानूनी कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दें। परन्तु उसके बावजूद हमारी सरकार आने के बाद हमने भारत सरकार को कहा। हालांकि भारत सरकार दो प्रांतों के विवाद में तटस्थ रहती है लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इंटरवीन किया और इंटरवीन करके पंजाब विधान सभा द्वारा पारित कानून की वैधता को प्रैजीडैंशियल रैफरैंस के तहत भेज दिया और अब अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक खण्डपीठ का निर्णय इस बारे में जल्दी आने वाला है। कैप्टन अजय सिंह लगातार इस मामले की पैरवी करते रहते हैं इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वह फैसला हमारे हक में ही आएगा। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक और तथ्यों के विपरीत गलत बात कही है। इन्होंने कहा है कि खेतीबाड़ी के दाम बहुत बढ़ गये हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आप इन बातों की रिप्लाई बाद में दे देना। अब तो ये यह कह रहे हैं कि it is not a subjudice matter. You are saying it is a subjudice matter. Presidential reference is still pending before the Bench of the Supreme Court. This is the factual position.

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : स्पीकर सर, ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो यह कहा है कि एस०वाई०एल० नहर को लेकर कोई मामला अदालत में पैंडिंग नहीं है मैं इनको बताना चाहूंगा कि इनकी यह बात तथ्यों पर आधारित नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में प्रैजीडैंशियल रैफरैन्स हमारी यू०पी०ए० की सरकार ने प्रैजीडैन्ट से आग्रह करके करवाया है और आज इस बारे में एक कांस्टीच्यूशनल बैंच कांस्टीच्यूट हो चुकी है। इसकी आगामी हीयरिंग की डेट 12 अप्रैल, 2008 है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात ऑन रिकार्ड कह सकता हूं कि हम भी उस समय विपक्ष में बैठते थे, उस समय ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे। उस समय हमने ओम प्रकाश चौटाला जी से अनुरोध किया था कि आपको भी इस मामले में पार्टी बनना चाहिए और जो हरियाणा का अहित हो रहा है उसके बारे में आपको कुछ न कुछ जरूर चैलेंज करना चाहिए लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। जब से चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार आयी है तब से हमने इस मामले में बैस्ट लॉयर इम्प्लाय कर रखे हैं। कांस्टीच्यूशन बैंच में इस मामले की हीयरिंग 12 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। आज भी इस मामले में केस पैंडिंग हैं लेकिन इन्होंने इस केस की पैरवी नहीं की जबकि मौजूदा सरकार इस मामले की पैरवी कर रही है। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, बी०एम०एल० हांसी बुटाना लिंक नहर को लेकर भी बाधाएं डालने की कोशिश की गयी इस नहर को लेकर भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 16 लोगों के द्वारा पैटीशन डलवायी गयी जिसको कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था और यह कहा कि इस तरह की

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

पैटीशन आम किसान नहीं डाल सकता। यह पैटीशन कुछ ऐसी ताकतों ने डलवायी है जो यह नहीं चाहती हैं कि हरियाणा के किसानों को पानी मिले। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों ने जानबूझकर यह पैटीशन डलवायी थी। हाई कोर्ट ने इस बारे में स्ट्रीक्चर भी पास किए हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बात हरियाणा के सब लोग जानते हैं कि कौन लोग नहीं चाहते हैं कि हरियाणा में पानी का इक्विल डिस्ट्रीब्यूशन हो।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले जरा और स्पष्ट कर दूं कि एस०वाई०एल० कैनाल की कंस्ट्रक्शन का कोई मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन नहीं है। सिर्फ केन्द्रीय सरकार द्वारा The Punjab Termination of Agreement Act, 2004 का राष्ट्रपति जी की मार्फत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने के लिए Reference सुप्रीम कोर्ट में भेजा था। सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने मांगा है कि आप बताइए कि इस पर क्या विचार है? कैप्टन साहब, आपने तो इस पर दो बार रुकावट डाली है और इस बात के बारे में तारीख लेने की चेष्टा की कि पंजाब में डेरा सच्चा सौदा का विवाद है इसलिए इस मामले को आगे लम्बा लटकाया जाए। आपके जो अटार्नी जनरल केन्द्र सरकार के हैं उन्होंने यह दर्खास्त दी है कि चूंकि पंजाब में और हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा का विवाद है। इसलिए अगली तारीख दी जाए। मैं तो यह मानता हूं कि डेरा सच्चा सौदा विवाद का इस पानी के मामले से कोई संबंध ही नहीं है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी चौटाला साहब कह रहे हैं। यह तथ्यों पर आधारित नहीं है। डेरा सच्चा सौदा वाली इस प्रकार की कोई बात रिकार्ड पर हो तो ये कहें। इनको यहां ये भी पढ़ना चाहिए। One must not either enter an Assembly Hall or he must speak there with all the righteousness, for one who does not speak or one who speaks falesly does involve himself in the equal sin. ये यहां पर लिखा हुआ है इसको ये पढ़ लें और उसके बाद ही कोई बात कहें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आप जवाब दे रहे हैं you are giving certain other facts and the Hon'ble Member is giving another facts. अगर कुछ रौंग है तो breach of privilege का मोशन आने दो। हाउस को गुमराह करने का प्रस्ताव लाया जाए। किसी को अधिकार नहीं है। No member has the authority on the floor of the House कि कोई गलत बयानबाजी करे। कोई भी गलत बयानबाजी करता है तो उसके खिलाफ प्रस्ताव लाया जाए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं और मैं औन ऑथ यह बात कह रहा हूं। केन्द्र के अटार्नी जनरल श्री बनर्जी ने यह लिखित में दिया है। उसे मंगवाकर देख लिया जाए। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया किया जाए लेकिन अगर कोई मंत्री गलत बयानबाजी करता है तो उसके खिलाफ भी प्रिविलेज मोशन लाया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : यह तो मैं कह ही रहा हूं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो उसको डिले करने की चेष्टा की

है। एस०वाई०एल० कैनाल की कंस्ट्रक्शन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन नहीं है। इसके साथ ही साथ मंत्री जी ने जिक्र किया कि जहां यमुना अकॉर्ड का मामला आया था उस वक्त हम अपोजीशन में थे और हमने इस मुद्दे पर इस्तीफे दिये थे। फैसला हुआ था कि किसाऊ, रेणुका और लखवार डैम जब बनेंगे तो उसके ऐवज में हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलेगा। सरकार ने इस बारे में कोई प्रयास ही नहीं किए हैं। यह किसका जिम्मा है। मुझे तो हैरानी इस बात की है कि जिस मुख्यमंत्री को बदनाम करने की बात सोची गई थी उस कैबिनेट में ये खुद सिंचाई मंत्री थे, ए०सी० चौधरी भी मंत्री थे, गुप्ता जी भी मंत्री थे और बहुत से लोग थे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : यमुना वाटर अकॉर्ड के बारे में इस समय हाउस की कमेटी बनी हुई है। It was discussed in the previous House. जिसमें हरियाणा प्रदेश के लोगों का पानी के बंटवारे के बारे में इंट्रस्ट अफैक्ट हुआ है, वाटर का जो शेयर था वह अफैक्ट हुआ है keeping in view the sense of the House. उस समय एक कमेटी बनी थी उस समय इंदौरा साहब भी हाउस में बैठे थे। इस बारे में कमेटी बनी थी Now, the matter is under consideration of the Committee लेकिन उसकी तीनों मीटिंग्स में आपकी पार्टी का मैंबर नहीं आया।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमने तो उस मुद्दे पर विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफे तक दिये हुए हैं तो उस मीटिंग में हम कैसे आ सकते हैं? हम तो उस समझौते को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे।

श्री अध्यक्ष : आप चाहें और लिख कर दें तो श्रीमती रेखा राणा की जगह उसमें आपकी पार्टी के किसी और मैंबर को उस कमेटी का मैंबर बना दें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : हम तो इस फैसले का शुरू से ही विरोध करते आए हैं। जब से इस कमेटी को बनाने की बात चली थी तो यह किसी पुराने मुख्यमंत्री को बदनाम करने की चेष्टा की गई थी। वैसे मैं इस मामले में जाना नहीं चाहता क्योंकि यह आपकी पार्टी का मामला है। उनकी कैबिनेट में तो कैप्टन साहब भी थे और मांगे राम गुप्ता जी और ए०सी० चौधरी व अन्य कई लोग थे तो उसमें अकेला भजन लाल कैसे दोषी हुआ?

श्री अध्यक्ष : किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसे बदनाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हरियाणा प्रदेश के लोगों का न्याय था वह काट दिया अब यह बतायें कि बदनाम होना चाहिए या नहीं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : होना चाहिए लेकिन जो प्रस्तावक थे उनको भी तो त्याग-पत्र देना चाहिए जो इस बात के लिए उकसाते थे, मांगे राम गुप्ता और ए०सी० चौधरी को भी इस्तीफा देना चाहिए था, उनको भी त्याग-पत्र देना चाहिए था अकेले भजन लाल को दोषी कैसे ठहराया जा सकता है?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब की विधान सभा ने यूनानीमैसली एस०वाई०एल० नहर के बारे में रेजोलूशन पास किया था उस वक्त हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे। हम विपक्ष में बैठते थे। हमने उनको

[श्री मांगेराम गुप्ता]

यह प्रस्ताव लाने के लिए कहा कि हम भी इसी प्रकार का प्रस्ताव यूनानीमैसली लायें। हरियाणा के 90 के 90 एम०एल०ए० इस हाउस में बैठे हैं चाहे कोई एम०एल०ए० किसी भी पार्टी का हो हम सभी अपना त्याग-पत्र देकर सैंट्रल गवर्नमैंट को पेश करें कि हरियाणा के साथ अन्याय हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इतना अन्याय हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। हम इस्तीफा देकर जा रहे हैं। उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी तैयार क्यों नहीं हुए? हमने तो 90 के 90 एम०एल०ए० के लिए कहा था उस समय इन्होंने उस बात को स्वीकार क्यों नहीं किया?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, जब इन्होंने इस्तीफा दिया था उस समय असैम्बली का केवल एक महीना बाकी रहा था।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : मांगे राम गुप्ता जी तो हमारे को उंगली लगाकर बीच में सरक गये।

श्री मांगेराम गुप्ता : आपको तो जनता ने हरा दिया आपने इस्तीफा नहीं दिया जनता ने आपको ठुकरा दिया।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : मांगे राम गुप्ता जी, यह तो रिकार्ड की बात है जब यमुना एकॉर्ड हुआ उस वक्त की बात है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से यह पूछा जाए कि यमुना एकॉर्ड कब हुआ था और इन्होंने इस्तीफा कब दिया था और विधान सभा का कार्यकाल उस समय कितना बचा हुआ था?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जिस कमेटी का आप जिक्र कर रहे हैं वह केवल मात्र लीपापोती है।

श्री अध्यक्ष : यह कमेटी तो हाउस की सैंस से सर्वसम्मति से बनाई गई है अगर हाउस ही इस बात के लिए लीपापोती करना चाहता है then you are also part of the House. आप उस कमेटी की मीटिंग में कभी नहीं आये।

श्री ओमप्रकाश चौटाला : **********

श्री अध्यक्ष : ये शब्द हाउस की कार्यवाही से निकाल दिये जायें। It is wrong to suggest these things. (Interruptions) Nothing is to be recorded whatever has been said by Shri Om Parkash Chautala without giving my permission. (Interruptions) Mr. Chautala, you may please address to the Chair.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यहां तक कि सदन के किसी सदस्य ने यह कहा था क्योंकि निश्चित रूप से यह बात रिकार्ड में भी रही होगी कि अगर इस पानी का बंटवारा हो गया तो महायुद्ध हो जायेगा। दो महायुद्ध तो मैंने सुने हैं मगर यह तीसरा महायुद्ध किस बात को लेकर हो जायेगा?

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

संसदीय सचिव (कुमारी शारदा राठौर) : माननीय स्पीकर सर, इस हाउस के माननीय सदस्य के बड़े सुपुत्र श्री अजय चौटाला का बयान आया था कि अगर इस पानी का समान बंटवारा हो जायेगा तो प्रदेश में गृह युद्ध हो जायेगा।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, वह कभी इस सदन का सदस्य नहीं रहा।

कुमारी शारदा राठौर : माननीय स्पीकर सर, मैंने यह कहा है कि इस हाउस के माननीय सदस्य के बड़े सुपुत्र ने ऐसा कहा है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आपने यह कहा है कि सदन के सदस्य ने कहा।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, शारदा राठौर जी ने यह बात कही है कि इस सदन के सम्मानित सदस्य श्री चौटाला जी के बेटे ने यह बयान दिया था। आप इनसे यह पूछ लें कि माननीय चौटाला जी हांसी बुटाना नहर के बनने के हक में हैं या नहीं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं on the floor of the House इस बात का पक्षधर हूं कि हरियाणा प्रदेश के किसानों के खेत की सिंचाई के लिए ज्यादा से ज्यादा जितनी नहरें बनें, हम उसके लिए तैयार हैं इसके लिए अगर हमें उस नहर की खुदाई के लिए खुद जाकर कस्सी चलानी पड़ी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : आपसे माननीय मंत्री जी ने एक स्पैसिफिक क्वैश्चन पूछा है। आप उसका उत्तर बतायें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : मैंने यह पूछा है कि आप इस नहर के बनने के पक्षधर हैं या नहीं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : हम इस बात के लिए तैयार हैं लेकिन सरकार यह स्पष्ट करें कि हांसी बुटाना लिंक नहर के लिए पानी कहां से आयेगा क्योंकि एस०वाई०एल० नहर के सवाल पर सरकार की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। किसाऊ, रेणुका और लखवार डैम्ज पर सरकार तवज्जो का दावा कर रही है। मुझे सरकार यह बताए कि उस नहर में पानी कहां से आएगा? सरकार जो नहर बना रही है उसको पंक्चर करने की क्या कोई व्यवस्था है? जब-जब रियासतों का कहीं भी डिस्प्यूट होता है तो उस पर सी०डब्ल्यू०सी० फैसला करती है या फिर यह फैसला अदालत के लिए विचाराधीन है। सर्वोच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, बताएं कि क्या पोजीशन है?

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको क्लैरीफाई करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि क्या दो स्टेटस का मामला है या नहीं? Central Water Commission has already cleared the project from Inter-State remification, Design, cost-aspect, irrigation planning and hydrological aspect. The Ministry of Agriculture, Ground Water Board and the Ministry of Environment and Forest has also cleared the project. हाल ही में कल 11 मार्च को सी०डब्ल्यू०सी० की मीटिंग में

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

हमने ये फैक्ट्स दिए थे । पंजाब का यह कहना था कि एक तो फ्लड्स आएंगे तो हमने कहा कि जो भी स्ट्रक्चर पंजाब के लोग कहेंगे, हम उसी स्ट्रक्चर को बनाएंगे । दूसरी उनको एप्रीहैंशन थी कि हमारे हिस्से का पानी इसमें चला जाएगा । जिस प्वायंट से हम पंक्चर कर रहे हैं उस प्वायंट पर 85 परसैंट शेयर हरियाणा का है, 5 परसैंट शेयर पंजाब का है और 10 परसैंट शेयर राजस्थान का है । हमने एफीडैविट में यह दिया है कि जहां से पंक्चर करेंगे उसका कंट्रोल भी हम बी०बी०एम०बी० को देंगे और हमारी वह बात सी०डब्ल्यू०सी० ने मान ली है । अजीमगढ़ से पंक्चर होगा, यह हमने बता दिया है । कल भी मैंने एक बात कही थी । ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये नहर बने लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हाई कोर्ट के अंदर इनके कई साथी हैं जिन्होंने पटीशन डाली हुई हैं ।

श्री अध्यक्ष : यह जो 85 परसैंट वाटर शेयर हरियाणा का है वह किसका शेयर है और हरियाणा के कौन से पार्ट का शेयर है और यह पानी कहां चल रहा है?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आप सब जानते हैं कि यह पानी साउदर्न हरियाणा का है इससे एक डिस्ट्रिक्ट को नहीं बल्कि 16 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को फायदा होगा । दूसरी बात जो इन्होंने कही कि हम इसके पक्ष में हैं, यह बात स्पष्ट है कि इनके ही साथी रामपाल माजरा जी जो पहले इरीगेशन मिनिस्टर थे, उनके द्वारा और कैथल के एरिया के लोगों की तरफ से 16 पटीशन हाई कोर्ट में डलवाई गई और 16 की 16 पटीशन हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं । जब हाई कोर्ट ने डिसमिस की थी तो यह कहा था कि ये इनोसैंट फार्मर्स का काम नहीं है and all these 16 petitions filed in the Hon'ble Punjab and Haryana High Court were dismissed. There is a judgement in C.W.P. No. 19676 of 2005 and it is written therein that—

> "Before parting, we, however, feel that it is important to unmask the petitioners, who have donned the cloak of public interest to raise such issues, which have only laid bare the fangs which do not belong to the innocent face of a farmer, but to someone else ; and the petitions, especially C.W.P. No. 19676 of 2005 are a result of an ingenuous mind with a purpose other than a public purpose. When viewed from the prism of the tests laid down by the Apex Court for a public interest litigation, we find the essential colours missing the spectrum."

अध्यक्ष महोदय, ये स्ट्रिक्चर्स हैं । ये जो काम है यह इनोसैंट केस का नहीं है इनके पीछे कोई ऐसी ताकत लगी हुई है जो यह काम पूरा नहीं होने देना चाहती जिस वजह से कोर्ट ने यह बात अपनी जजमैंट में कही है । 5 एस०एल०पी० सुप्रीम कोर्ट में भी डली हैं जो डिसमिस हो गई हैं । 2 पैटीशन अभी चल रही हैं जो पंजाब और राजस्थान ने डाल रखी हैं । इस प्रकार हमारी जितनी भी बातें हैं वे सारी सी०डब्ल्यू०सी० ने मान ली हैं ।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने कहा कि पानी कहां से लाएंगे, आपने कहा साउदर्न हरियाणा का पानी है तो आप बताएं कि यह पानी साउदर्न हरियाणा का किस एग्रीमैंट के तहत है और कैसे चल रहा है?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आप सभी जानते हैं कि जिस समय एस०वाई०एल० कैनाल का एग्रीमैंट हुआ था उस समय पंजाब सरकार को पैसा दिया गया था और उस वक्त कहा गया था कि एस०वाई०एल० कैनाल और भाखड़ा का जो पानी आयेगा वह महेन्द्रगढ़, झज्जर और गुड़गांव आदि जिलों को दिया जायेगा। इसके लिए पाकिस्तान को भी करोड़ों रुपये दिये गये थे। पिछली सरकार ने एस०वाई०एल० कैनाल का पानी लेने के लिए कोई कोशिश नहीं की। हमारी सरकार पानी का बराबर बंटवारा करना चाह रही है। केवल दक्षिणी हरियाणा की बात नहीं है बल्कि 16 जिलों को इस नहर से फायदा होगा जिसमें कैथल, झज्जर, जींद जिले भी शामिल हैं। अध्यक्ष महोदय, सी०डब्ल्यू०सी० ने हमारी कंटैंशन को माना है और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने हमारी बात को माना है। विपक्ष के साथियों का कहना कि हमने कहीं से कोई परमिशन नहीं ली, बिल्कुल गलत कहना है। हमने हर स्तर पर परमिशन ले रखी है। 29 अप्रैल की तारीख लगी हुई है उसमें हमें जरूर न्याय मिलेगा।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक बात कहना चाहता हूं। अगर चौटाला जी बोलना शुरू कर देंगे तो वे कहेंगे कि मैं बीच में इन्टरप्ट कर रहा हूं। इसलिए उनके बोलने से पहले ही मैं कहना चाहूंगा कि मंत्री जी ने सारी बातें बताई हैं। हमने दो प्रश्न स्पीकर सर, आपकी अनुमति से ओम प्रकाश चौटाला जी और उनकी पार्टी से पूछे हैं। क्या इनके बेटे ने गोहाना के अंदर यह बयान नहीं दिया कि हांसी बुटाना लिंक नहर बनने से प्रदेश में गृह युद्ध हो जायेगा और दूसरा प्रश्न यह था कि क्या चौटाला जी हांसी बुटाना लिंक नहर के हक में हैं या नहीं है? पानी लाना हमारी सरकार की जिम्मेवारी है, हम अपने आप ले आयेंगे। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में ऐसे-ऐसे केस हैं कि एक पिता के दो पुत्र हैं, उन दोनों पुत्रों की जमीन तक पानी पहुंचाने के लिए उनके पिता ने अलग-अलग रजबाहे निकाल दिए। एक की जमीन के लिए एक रजबाहा निकाल दिया और दूसरे की जमीन के लिए दूसरा रजबाहा निकाल दिया। यह काम ओम प्रकाश चौटाला जी जिस समय मुख्यमंत्री थे उस समय इन्होंने किया था। उस समय पूरा दक्षिणी हरियाणा और जींद, रोहतक तथा झज्जर जिले पानी के लिए प्यासे मरते रहे और इन्होंने एक-एक व्यक्ति के लिए रजबाहे निकाले। अब हम उन रजबाहों से पानी लेकर बाकी के हरियाणा को दे देंगे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल यही स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि हम इस बात के कतई विरोधी नहीं हैं कि हरियाणा प्रदेश के किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए नहरें न बनें। हम इसके पक्षधर हैं लेकिन सरकार दो बातें स्पष्ट करे। एक तो इसके लिए पानी की व्यवस्था कहां से की जायेगी? (विघ्न) यह बताने से क्लीयर नहीं है क्योंकि आप साथ-साथ यह भी कह रहे हैं कि मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। अध्यक्ष महोदय, यदि भाखड़ा का ही पानी इस्तेमाल करना है तो उसके लिए नई नहर बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हरियाणा प्रदेश की नहरों का सिस्टम ऐसा है कि किसी भी नहर का पानी किसी भी हिस्से में ले जाया जा सकता है। हमने तो ड्रेनों में भी पानी डालकर किसानों की सिंचाई कराने का काम किया था। यह जो नहर बन रही है इसके लिए पिछले गवर्नर अभिभाषण में 265 करोड़ रुपये खर्च होना था।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, सिरसा के अंदर वाटर लोगिंग पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। वहां वाटर लोगिंग क्यों हो रही है। वह इसलिए हो रही है

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

क्योंकि 16 जिलों का पानी का हिस्सा केवल सिरसा जिले में देते रहे। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, जो ब्यास सजलुज लिंक की रिपोर्ट है वह ज्वाइंट पंजाब के समय तैयार की गई थी। उसमें मैंशन कर रखा है कि जो रावी ब्यास का पानी है वह एरीड एरियाज के लिए है। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि एक तरफ तो वाटर लोगिंग पर करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं और दूसरी तरफ इनकी गलत नीतियों के कारण लोग प्यासे मर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) घग्गर नदी का तो पानी इनके एरिया में जाता था वहां पर ओटूवियर पर इन्होंने 32 करोड़ रुपये खर्च कर दिया लेकिन उसकी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बढ़ाई। आज हमारी सरकार 70 करोड़ रुपये खर्च करके उसको 6 फिट गहरा करके उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा रही है। ये अपने समय में सारा पानी राजस्थान की तरफ जाने देते थे क्योंकि राजस्थान से इनके पुत्र चुनाव लड़ते थे। अध्यक्ष महोदय, ये लोग या तो राजस्थान के बारे में सोचते हैं या पंजाब के बारे में सोचते हैं। ये लोग जो फालतू पानी ले रहे थे उस पर इनका अधिकार नही था। उस पानी पर झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, रिवाड़ी, गुड़गांव, मेवात, फरीदाबाद, भिवानी, महेन्द्रगढ़, कैथल, जींद, हांसी, अम्बाला, कुरुक्षेत्र और करनाल इन 16 जिलों का अधिकार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के पिता चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी जब सिंचाई मंत्री थे तो उन्होंने भी यह बात कही थी कि जो नहर आज हम बना रहे हैं। अगर इसको हमने पहले बना लिया होता तो यह एस०वाई०एल० वाला मुद्दा कभी उठना ही नहीं था। कहने का मतलब यह है कि जो हम अच्छे काम कर रहे हैं उसकी इनको सराहना करनी चाहिए। 85 प्रतिशत जो हरियाणा का शेयर है उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यह हमारा मामला है और हमारा ध्येय यह है कि हम पानी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें ताकि हर एरिया को बराबर का पानी मिले।

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, यह सवाल सदन में बार-बार उठने लगा है कि पानी कहां से आयेगा? असल में तो माननीय सदस्य चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और इनकी पार्टी ने कभी इस बारे में दिलचस्पी ही नहीं ली। मुझे इसमें आपकी रूलिंग चाहिए। एस०वाई०एल० में हरियाणा प्रदेश का हिस्सा 3.85 एम०ए०एफ० जिसमें से हम 1.7 एम०ए०एफ० नरवाना ब्रांच से ले रहे हैं। इसका बाकी हिस्सा हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमारी नहर नहीं बनी है। इसलिए यह जो कैनाल अब बनाई जा रही है उसमें जो रिमेएण्डर वाटर जितना भी होगा वह इसमें से भी आ जायेगा। पिछले 30-40 साल से यह होने लग रहा था कि चौधरी ओम प्रकाश और इनके दूसरे साथी यह सारा पानी सिरसा, फतेहाबाद और हिसार के लिए ले जा रहे थे और वहां पर इस पानी का बहुत ज्यादा दुरुपयोग करने लग रहे थे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी सिंचाई मंत्री रहे हैं और उन्हें इस बारे में मुझ से ज्यादा ज्ञान है। इनकी इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि हम भाखड़ा में से पूरा पानी नहीं ले पाये। कई मर्तबा हमारी सरकार के वक्त ऐसे अवसर आये कि हमने पंजाब की गवर्नमैंट को मैंटीनैंस के लिए पूरे पैसे दिये और हमें उस वक्त उसमें से पूरा पानी मिलता रहा है। लेकिन यह अच्छी बात है मैं एक बार फिर उस बात को दोहराता हूं कि पानी मिले और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की

सुविधा प्राप्त हो । लेकिन हम तो केवल यही जानना चाहते हैं कि सरकार यह बताये कि यह पानी आयेगा कहां से? अगर इसी पानी को डिस्ट्रीब्यूट करना है इसी पानी को तकसीम करना है तो उसके लिए नई नहर बनाने की जरूरत नहीं थी और फिर जो अन्य नहर बनाई जा रही है उसके लिए 265 करोड़ का प्रोजैक्ट था । लेकिन राज्यपाल महोदय के पिछले अभिभाषण में वह 350 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है और जब तक यह बनकर मुकम्मल होगी हो सकता है कि यह 500-600 करोड़ तक पहुंच जाये । अगर इसमें पंक्चर की इजाजत नहीं होगी तो फिर यह 600 करोड़ रुपये वेस्ट हो जायेंगे । इसकी रिकवरी कहां से होगी ये दो बातें तो सरकार को कम से कम स्पष्ट करनी ही चाहिएं? मैं सरकार की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि पानी आयेगा तो हमें उसका फायदा होगा लेकिन अगर नहीं आयेगा तो जो आशंका मैं व्यक्त करने जा रहा हूं उसके बारे में मैं सरकार से जानना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, आप इस सवाल में हाईपोथैटीकली क्यों जाते हैं ।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : नहीं अध्यक्ष महोदय, यह हाईपोथैटीकली नहीं है । इसमें हरियाणा प्रदेश के मेहनतकश लोगों का पैसा लग रहा है ।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, मंत्री जी ने on the floor of the House यह आश्वासन दिया है कि इसके लिए भाखड़ा को पंक्चर किया जायेगा ।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, उनके कहने से तो नहीं माना जा सकता क्योंकि फैसला इनके विचाराधीन नहीं है, फैसला तो अदालत के विचाराधीन है और कल को अदालत क्या फैसला करती है इसका तो किसी को भी कोई ज्ञान नहीं है । अदालत जब फैसला करेगी उसके बाद ही आप इसको पंक्चर कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, आप इसको पंक्चर करने में सहमति रखते हैं ।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत हूं क्योंकि हरियाणा प्रदेश के हितों के लिए हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और हमने इसके लिए लड़ाइयां भी लड़ी हैं । देखिए, किसान के खेत की सिंचाई के लिए जितनी ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था हो सके हम इसके पक्षधर हैं चाहे वह रेणुका डैम हो, चाहे लखवार डैम हो और चाहे किशाऊ डैम हो, चाहे कोई नई नहर बनाई जाये और चाहे नई डिस्ट्रीब्यूटरियां बनाई जायें, हमें इस बात से बहुत खुशी होगी कि किसान को लाभ मिला क्योंकि किसान के खेत की पैदावार में पानी देने के लिए केवल मात्र दो ही तो साधन हैं एक पानी है और दूसरा बिजली का है । अब बिजली के मामले को लेकर तो समूचे प्रदेश में आज कोहराम मचा हुआ है और इस बात से सभी माननीय सदस्य भी पूरी तरह से अवगत हैं । आज बिजली है ही नहीं और बिजली न होने की वजह से त्राहि-त्राहि मच रही है । नहरों में पूरा पानी नहीं है और ऊपर से भयंकर सर्दी की मार की वजह से किसान पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया है । बिजली के मामले में सरकार की तरफ से घोटाले तो जरूर किये गये लेकिन बिजली पैदा करने के साधन कोई जुटाने का काम नहीं किया गया है । मौजूदा सरकार बयान बड़े देती है कि अतीत की सरकारों की वजह से यह नुकसान हो रहा है । अतीत की सरकारों के वक्त में तो बिजली पैदा हुई । मौजूदा सरकार यह तो बतायें कि

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

उन्होंने कौन सी ऐसी बिजली पैदा करके दी है। इन्होंने गैस बेस्ड जो फरीदाबाद में पावर प्लांट है 1032 मैगावाट का गैस आधारित थर्मल प्लांट जिसकी मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने 25 अगस्त, 2005 को आधारशिला रखी। अध्यक्ष महोदय, 31 महीने हो गये आधारशिला रखे लेकिन अब तक उस पर एक ईंट भी नहीं रखी गई है।

12.00 बजे

श्री अध्यक्ष : यह सब तो गैस की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह बात तो आधारशिला रखने से पहले सोचनी चाहिए थी।

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, यह गैस का एग्रीमैंट झज्जर में एक पब्लिक मीटिंग में हुआ था मैं भी उस मीटिंग में शामिल था। गेल के साथ यह समझौता हुआ था और उस समय गेल ने कहा था कि हम गैस उपलब्ध करवायेंगे लेकिन उसमें उसको गैस नहीं मिल पाई।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपको तो पता है लेकिन हमें इस बात का ज्ञान नहीं है। आधारशिला रखी 25 अगस्त, 2005 को लेकिन उस पर आज तक कोई काम नहीं हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जो फैक्व्यूवल पोजीशन है वह मैं बताना चाहता हूं। शायद चौटाला जी को यह मालूम नहीं है कि हिन्दुस्तान में जो गैस है वह प्रान्त की मलकीयत नहीं है, राज्य सरकारों की मलकीयत नहीं है। It is treated as a national assets. और उसकी एक्सपलोरेशन के राईट्स हमारे पास सरकार की कम्पनियों के पास भी हैं और कुछ प्राइवेट कम्पनियों को ऑक्शन करके ऑयल ब्लॉक्स जो दिये गये हैं, उनको भी गैस मिली है। दूसरी बात है गैस की उपलब्धता तथा साथ-साथ गैस के रेट का निर्धारण। हम सरकार से हरियाणा के लिए जो गैस मांग रहे हैं ताकि सस्ती बिजली दे सकें, वह सरकार के द्वारा निर्धारित रेट पर गैस मांग रहे हैं उसके लिए भारत सरकार के बहुत सारे इश्यू हैं सर। Empowered Group of Ministers, External Affairs Ministers श्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में बना हुआ है जो सभी कंपनियों से प्राईवेट सैक्टर और सरकारी कम्पनियों से बात करके एक रेट को नोटीफाई करेंगे। उसके बाद गैस उपलब्ध होनी शुरू होगी। अध्यक्ष महोदय, एक प्लांट ही नहीं हमने तो गैस बेस्ड प्लांट के और भी कई अनुबन्ध किये हैं। जब गैस उपलब्ध हो जायेगी तो वे सारे प्लांट भी हम चालू करेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और तथ्यों के आधार पर क्लैरीफाई करना चाहता हूं कि हरियाणा के गठन के बाद जो केवल 1587.4 मैगावाट के कोयले पर आधारित थर्मल प्लांट हरियाणा में लगे हुए हैं उनमें से अधिकतर कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में लगे हैं। इस सरकार ने पहली बार 5 हजार मैगावाट बिजली पैदा करने के लिए 24 हजार करोड़ रुपये का निवेश करने का निर्णय किया है। अध्यक्ष महोदय, जिस सरकार का प्लांड बजट केवल 5 हजार करोड़ से कम हो और आज वह सरकार 24 हजार करोड़ रुपये का निवेश केवल बिजली उत्पादन के अन्दर कर रही है। यह सारी बिजली 2009 के आखिर और 2010 के शुरू तक मिलनी शुरू हो जायेगी।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सरकार की सक्रियता का अन्दाजा इसी बात से लग रहा है कि हमारी सरकार के समय में यमुनानगर में दीन बन्धु सर छोटूराम के नाम पर एक थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखी गई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने एक नई आधारशिला तो जरूर रखी लेकिन उसके ऊपर 3 सालों के दौरान एक यूनिट बिजली की भी पैदावार नहीं हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह बात तथ्यों से परे है। वहां पर मार्च, 2005 में जब हम गये तो स्पाट मैदान पड़ा था। पत्थर तो इनके पिताजी ने भी रखा था लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ। 12 साल तक वह इसी प्रकार पड़ा रहा। आखिर में आकर चौ० भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार ने उसको शुरू किया। आज वह प्लांट इस समय बिजली प्रोडक्शन कर रहा है। उसकी पहली यूनिट 300 मेगावाट की चली हुई है और अब तक 850 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन कर चुका है और चौटाला जी कह रहे हैं कि एक यूनिट भी बिजली पैदा नहीं हुई है। यह बात तथ्यों से परे है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इसको क्वैश्चन आवर न बनायें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मुझे अपनी बात कहने दें।

श्री अध्यक्ष : जो फैक्च्यूअल पोजीशन है वह तो पता चलनी ही चाहिए ताकि हरियाणा प्रदेश के लोग भी इस बात को जान सकें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ठीक है आप फैक्चयूअल पोजीशन सुनें तो सही, मैं फैक्च्यूअल पोजीशन आपको बताने जा रहा हूं। हमारी सरकार के वक्त उसकी आधारशिला रखी गई थी। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा साहब, आप यह देखें कि इस वक्त आपके लीडर बोल रहे हैं। इसलिए आप उनको सुनें। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप यह बात दूसरे लोगों को भी बोलें।

श्री अध्यक्ष : दूसरे तो बंद ही हैं। No running commentary please.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, मैं यह कह रहा था कि जिस कम्पनी को यह काम दिया गया था उस कम्पनी ने हमारी सरकार के वक्त एक दरख्वास्त दी थी कि उसे अपनी एक सहयोगी कम्पनी को बदलने की इजाजत दी जाए। कायदे के मुताबिक उस वक्त हमारी सरकार का एक निर्णय था कि जो फैसला पहले लिया गया है उसको बदला नहीं जाएगा। हमने उनकी उस दरख्वास्त को रिजैक्ट कर दिया था क्योंकि उसकी वजह से सरकार को नुकसान होना था। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार के वक्त 13 जून, 2005 को नई सरकार बनने के बाद उस कम्पनी ने सरकार को एक दरख्वास्त दी थी कि हमें अपनी नई कम्पनी जो डांग फोंग इलैक्ट्रिक कारपोरेशन है, उसकी बजाए हमें नई कम्पनी को साईन करने की इजाजत दी जाए क्योंकि वह हमें मशीनें सप्लाई करेगी। उस सरकार ने 13 जून, 2005 को उनकी उस दरख्वास्त को रद्द कर दिया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि 15 तारीख, 2005 को ही उस कम्पनी से एक नई दरख्वास्त लेकर उसको मान लिया गया और उसकी वजह से सरकार को कम से कम 400 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। जो पैनल्टी सरकार को मिलनी चाहिए थी सरकार को उसका नुकसान हुआ। उसके बाद बड़ी

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

जल्दबाजी में अप्रैल, 2007 से पहले कम्प्रोमाईज किया जाना चाहिए था लेकिन उसके लिए सरकार ने उनको फिर अनुमति प्रदान की कि एक नवम्बर, 2007 तक उसको मुकम्मल कर दें। एक नवम्बर को बड़ी जल्दबाजी में मुख्यमंत्री जी ने उसको फायदा पहुंचाने के हिसाब से उसको कोयले से फायर करने की बजाए तेल से करवाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, चार महीने के बाद अब तक भी उस यूनिट से जो 300 मैगावाट बिजली का उत्पादन होना चाहिए था वह अब तक नहीं हो पा रहा है।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आपके मुताबिक कितना उत्पादन हो रहा है?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अभी तक यह 300 मैगावाट से कम हो रहा है। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पहले यह कहा था कि एक यूनिट बिजली का उत्पादन भी वहां से नहीं हो रहा है। (विघ्न) सर, इस बारे में आप रिकार्ड निकाल कर देख सकते हैं कि इनकी कौन सी बात सच है?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : वह कमर्शियल के हिसाब से नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इसकी वजह से उस कम्पनी पर जुर्माना लगना चाहिए था। उस जुर्माने से छूट देने का काम भी इस सरकार ने किया जिसकी वजह से स्टेट को कम से कम 200 करोड़ रुपये का नुकसान और हुआ है। अध्यक्ष महोदय, बिजली की कमी के दृष्टिगत इन्होंने कैबिनेट मीटिंग में एक निर्णय लिया। उस कैबिनेट मीटिंग में शायद चट्ठा साहब भी उस वक्त मंत्री थे, उस वक्त एक फैसला हुआ था कि क्योंकि हरियाणा प्रदेश में बिजली की कमी है, उस बिजली की कमी को पूरा करने के लिए कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई थी उस मीटिंग में एक ऐसी कम्पनी जो किसी कांग्रेसी सांसद के भाई की कम्पनी है उससे बिजली का एग्रीमैंट किया गया और 13450 करोड़ रुपये का यह सौदा किया गया। स्पीकर साहब, होना तो यह चाहिए था कि उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाता लेकिन उस कम्पनी का उत्पादन 2009 में होना है। कैबिनेट मीटिंग की अप्रूवल के बाद चूंकि बिजली की कमी है इसलिए उसको जल्दी से जल्दी लेने के लिए एग्रीमैंट करके उनको पैसा दिया गया। वह कम्पनी उत्तर प्रदेश सरकार को एक रुपये 90 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देने की पेशकश करती है। (विघ्न) एक तरफ जहां वह एक रुपये 90 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देने की पेशकश करती है वहीं हमारी सरकार ने उनसे एग्रीमैंट किया था कि वह पौने तीन रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देंगे। स्पीकर साहब, इसकी वजह से कितना बड़ा घोटाला हुआ है, इस घोटाले के लिए कौन दोषी है यह तो समय आने पर अपने आप तय होगा लेकिन यहां पर बिजली की तरफ तो कोई तवज्जो ही नहीं है। स्पीकर सर, आज शिलान्यास तो रखे जा रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है। झाड़ली में जिस रोज आधारशिला रखी उसके बाद तो बिजली ही कहीं झड़ गई और लोगों को कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है। लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं कि बिजली कहां चली गई है। ये लोग कहते हैं कि 4.5 हजार मैगावाट बिजली पैदा करेंगे, यह बहुत अच्छी बात है। बिजली आज हर आदमी की नसैस्टी है, उद्योग की धुरी है। किसान को बिजली चाहिए, व्यापारी को बिजली

चाहिए लेकिन बिजली कहां है, सरकार बिजली का उत्पादन करके बताए तो अच्छी बात होगी। अभी ये कह रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ गया है लेकिन वह बिजली है कहां। हरियाणा प्रदेश में तो बिजली है नहीं। यह बिजली कहां जा रही है यह अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। लोग हमसे पूछते हैं कि हमारी सरकार के वक्त में बिजली कहां से आती थी यह बात तो लोगों को इनसे पूछनी चाहिए। स्पीकर सर, हमारी सरकार के वक्त में हम हरियाणा प्रदेश को बिजली देते थे। क्योंकि कांग्रेस की सरकार दिल्ली से चलती है इसलिए दिल्ली के लोगों को राजी करने के लिए बिजली दिल्ली भेजी जा रही है जबकि हरियाणा प्रदेश में बिजली न होने के कारण त्राहि-त्राहि मची हुई है। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ये फिर उसी प्रकार का माहौल पैदा कर रहे हैं। क्या चौटाला साहब के पास बोलने के लिए मसाला खत्म हो गया है? (शोर एवं व्यवधान) अब इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहा है। अब ये यहां से जाएंगे। (शोर एवं व्यवधान) इन्होंने यहां से जाने का मन बना लिया है। अब ये सदन से भागने की भूमिका तैयार कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : * * * * * * *

Mr. Speaker : Nothing to be recorded. चौटाला साहब, मंत्री जी बोल रहे हैं आप उनको बोलने दें। (शोर एवं व्यवधान) Nothing to be recorded.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, 40 हजार करोड़ रुपए का निवेश चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के सरकार के वक्त में हरियाणा में आया है। नए उद्योग धन्धे हरियाणा में आए हैं। एक लाख करोड़ रुपए के निवेश के उद्योग धंधों का मामला इस समय हरियाणा में पाईप लाइन में है। (शोर एवं व्यवधान) इस सरकार के आने के बाद 28 प्रतिशत बिजली की खपत हरियाणा में बढ़ी है। Sir, on record I want to say on oath, let Sh. Om Parkash Chautala bring a breach of privilege against me. कि एक यूनिट बिजली भी हरियाणा में से किसी को नहीं दी गई है। उल्टा चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा दूसरे प्रान्तों से बिजली हरियाणा में लेकर आए हैं। If I am wrong, I challenge him to bring a breach of privilege against me. (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, पिछले अधिवेशन में क्वैश्चन ऑवर में स्वयं मुख्यमंत्री जी ने इस बात को माना है कि हरियाणा प्रदेश की बिजली उत्तरांचल में, हिमाचल में और महाराष्ट्र में जा रही है। (शोर एवं व्यवधान) मैं यह रिकार्ड की बात बता रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह सरासर झूठ है। ओम प्रकाश चौटाला जी ने यह आदत बना ली है कि ये हर बात को तोड़-मरोड़ कर पेश करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप यह हाउस की प्रोसिडिंग में देख लें।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : कौन सी प्रोसिडिंग में है?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप वह पिछले बजट सैशन की प्रोसिडिंग में देख लें।

श्री अध्यक्ष : आप उसकी डेट बताएं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : मैं आपको डेट देखकर बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : चलो ठीक है, ये डेट देखकर बता देंगे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इनको कम से कम सदन में आकर सत्य बोलना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) इनके वक्त में उद्योग धन्धे हरियाणा से पलायन करके चले गए थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने कहा है कि हमारी सरकार के वक्त में उद्योग पलायन कर गए थे। अध्यक्ष महोदय, इस समय इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर सदन में नहीं हैं लेकिन जब मुख्यमंत्री जी आज जाएं तो ये व्हाईट पेपर जारी करें कि हमारे समय में हरियाणा में से कौन-कौन से उद्योग पलायन कर गए थे। (शोर एवं व्यवधान)

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : चौटाला जी, आपके समय में लिबर्टी पलायन कर गई थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : कोई इंडस्ट्री पलायन नहीं करी है। (शोर एवं व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री (श्री ए०सी० चौधरी) : चौटाला जी, मैं आपको बताता हूं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं अदब से नाम लेकर बताता हूं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद हरियाणा में सबसे बड़ा औद्योगिक सैन्टर रहा है। चौटाला साहब का राज आने के बाद आम बच्चे के जुबान पर यह आ गया था कि चौटाला साहब आए और फरीदाबाद का फकीराबाद बना दिया। उस वक्त फरीदाबाद में न्यू इन्डस्ट्रीयल टाऊन के नाम पर 200 के करीब उद्योग थे। लेकिन इनके वक्त में वहां पर 4 या 5 उद्योग रह गए थे, बाकी सारे के सारे उद्योग वहां से इनके राज के वक्त में पलायन करके राजस्थान और नोएडा में चले गए थे। अध्यक्ष महोदय, मैं खुद इण्डस्ट्री मिनिस्टर रहा हूं इसलिए यह बात पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। मैं इनको याद दिलवाना चाहता हूं कि इनके राज में हमारा पूरा का पूरा शहर उजड़ गया था। अध्यक्ष महोदय, आज ये बिजली के मामले में भी पूरे का पूरा श्रेय लेना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बिजली मंत्री भी रहा हूं इन्होंने अपने समय में बिजली की खपत इस तरह से की जिस तरह से गाड़ियों में स्पीडो मीटर लगे होते हैं और उसमें स्पीड 0 से 180 दिखाई होती है। इन्होंने लगे लगाए प्लांट्स को जहां 100, 80-90 में आना चाहिए वहां उनको ये 140 और 160 पर ले गए। जो भी प्लांट एक बार बिगड़ा वह महीनों नहीं खड़ा हो सका। आज ये उद्योगों का नाम लेते हैं लेकिन जब उद्योग रहे ही नहीं तो नाम क्या लेंगे? अगर ऐसी बात नहीं है तो ये भी चुनौती दे दें और मैं भी चुनौती दे देता हूं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, इनकी वजह से ही करनाल में लिबर्टी वाला भाग गया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुशार प्रधान : स्पीकर सर, इन्होंने बहादुरगढ़ में बिस्कुट की पारले फैक्ट्री के सामने नींव खुदवाकर दीवार बनवा दी थी जिसके बाद वह भागकर राजस्थान चला गया था। उससे इनके लड़के और इनके एम०एल०ए० उगाही मांगते थे। उससे दस करोड़ रुपये मांगे थे। (शोर एवं व्यवधान) इन्होंने लिबर्टी फैक्ट्री भी करनाल में बंद करवा दी थी। रेहड़ी वालों से इनके एम०एल०एज० के गुण्डे थैला लेकर दस-दस रुपये मांगते थे। इन्होंने धारूहेड़ा में भी एक फैक्ट्री बंद करवा दी थी।

श्री अध्यक्ष : ये जो भी बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, ******* (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह सढौरा : स्पीकर सर, ******* (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के कई सदस्य हाउस की वैल के नजदीक आ गए और जोर-जोर से बोलने लगे।)

श्री नरेश कुमार प्रधान : स्पीकर साहब, ये गांव-गांव में जाकर कहते थे कि मुझे एक बार सत्ता की सीढ़ी चढ़ा दो मैं तुम्हारी चार पीढ़ी का जुगाड़ कर दूंगा लेकिन इनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। ये तो अपने विधायकों को जहाज के अंदर पीटते हैं जबकि आज ये इतराते हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जो पाप इन्होंने किए हैं वह पाप तो अब खुलेंगे ही। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Please take your seat. (शोर एवं व्यवधान) आप सभी बैठें, आप सबको बुलवाएंगे। चौटाला साहब, आज आपको बुलाया गया है (Interruptions) Please take you seat. पण्डित जी, आप पर इल्जाम लगाया है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं आप बताएं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं?

श्री नरेश कुमार प्रधान : स्पीकर सर, दसवीं फेल।

श्री अध्यक्ष : अब चिढ़ाना साहब, आप बताएं कि आप कितने पढ़े हैं और आपका लीडर कितना पढ़ा है? आप इल्जाम लगा रहे हैं तो आप बताएं। (शोर एवं व्यवधान) ये सदन का सम्मानित साथी है। (शोर एवं व्यवधान) Nothing to be recorded.

श्री बलवन्त सिंह सढौरा : स्पीकर ******* (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठें। दलाल साहब, ओम प्रकाश चौटाला जी एक घंटा चार मिनट बोले हैं। चौटाला साहब, अब आप वाईंड अप करें। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० छत्रपाल सिंह : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। स्पीकर सर, खेदड़ गांव जो कि मेरी कांस्टीच्यूएंसी में पड़ता है वहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने वहां पर 1200 मैगावाट के थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखी थी। अभी ओम प्रकाश चौटाला जी बिजली के ऊपर बहुत लम्बा भाषण

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[प्रो० छत्तरपाल सिंह]

कर रहे थे खुद वाहवाही लूटने के लिए और सरकार पर क्लैम करने के लिए। यह तथ्यों पर आधारित है कि साढ़े पांच साल में इन्होंने हरियाणा के अंदर राज किया है जब कांग्रेस की सरकार 1991 से लेकर 1996 के बीच में थी जिसमें मैं भी वजीर था और उस कांस्टीच्यूएंसी को रिप्रैजैंट करता था तो उस समय 1065 मैगावाट का थर्मल प्लांट खेदड़ में लगना निश्चित हुआ था, उसकी जमीन भी ऐक्वायर कर दी गयी थी और किसानों को उसका पैसा भी दे दिया गया था। स्पीकर सर, 1996 तक ये फार्मेलिटीज पूरी हो चुकी थी लेकिन उसके बाद साढ़े पांच साल तक ये श्रीमान जी मुख्यमंत्री रहकर चले गए लेकिन इन्होंने उस पावर प्लांट के ऊपर एक ईंट भी रखने का कभी काम नहीं किया। स्पीकर सर, क्या उस कांस्टीच्यूएंसी का कसूर यह था कि वहां से माननीय चौधरी देवी लाल ने चुनाव लड़कर शिकस्त ले ली थी। हरियाणा प्रदेश के इंट्रस्ट को वाच करना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है। यह तो ठीक नहीं है कि इन बातों को सोचकर हरियाणा प्रदेश के विकास पर रोक लगा दी जाए। इस किस्म की नीयत से इन्होंने भाषण देते हुए कहा कि हमने 10 हजार रुपये तक कर्ज माफ कर दिए। आपको याद होगा कि इन्होंने सरकार ही इस आधार पर बनाई कि सभी लोगों का हम कर्जा माफ करेंगे। कांग्रेस की सरकार ने कभी कोई वादा नहीं किया। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने बिजली के बिलों की पैनल्टी और ब्याज माफ किए। हमारी सरकार ने 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बकाया बिल माफ किए और बिजली यदि पैदा की है तो कांग्रेस की सरकार ने की है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : इस सदन के हर सदस्य को बोलने का अवसर आप देंगे ही। अभी उद्योग धंधों के पलायन का जिक्र शायद सदन में चल रहा था।

श्री अध्यक्ष : आप ये 'शायद' वर्ड बहुत लगाते हैं। यह आपका तकिया कलाम लगता है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अभी कहा जा रहा था कि हमारी सरकार के वक्त में बहुत ज्यादा उद्योग धंधे पलायन कर गये थे लेकिन हमारी सरकार के वक्त में किसी उद्योग धंधे ने पलायन नहीं किया बल्कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी तो इंडस्ट्रियल ग्रुप लेकर विदेश गए थे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आपने 11 बजकर 14 मिनट पर बोलना शुरू किया था।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : मेरा टाइम तो आप खराब करते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको ऐडवाइज करता हूं कि प्लीज, आप अपने दायरे में रहें। It is my duty to put the record straight. Mr. Chuatala, please carry on your speech and conclude it.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप हरेक को चाहे जिसको बीच में बोलने के लिए खड़ा कर देते हो।

श्री अध्यक्ष : आप भी प्वायंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने के लिए खड़े हो सकते हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : इससे ज्यादा गलत बात क्या होगी कि मुख्यमंत्री के साथ

जो उद्योग का डैलीगेशन गया था उसमें एक उद्योगपति के साथ एम०ओ०यू० साइन किया गया जिसकी वजह से उनका उद्योग उत्तरांचल और हिमाचल के लिए था, न कि हरियाणा के लिए था।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। जब चौटाला जी मुख्यमंत्री थे तो ये अपने साथ प्रोक्लेम्ड औफैंडर्स को अपने साथ विदेशी दौरों पर ले कर जाया करते थे।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आप कंक्लूड करें। आपको बोलते हुए 1 घंटा 8 मिनट का समय हो गया है। आपको पांच मिनट का समय और दिया जाता है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : मेरा अधिकार है और मैं पूरा समय लूंगा।

श्री अध्यक्ष : आपका अधिकार है। सरटेनली आपका अधिकार है लेकिन दूसरे सम्मानित सदस्यों के अधिकार छीनने का आपका अधिकार नहीं है। (Interruption) I am performing my duty.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : यह अधिकार किसी को नहीं है कि वह प्वायंट ऑफ आर्डर के नाम पर भाषण झाड़ें।

Mr. Speaker : Mr. Chautala, please carry on your speech. Please, no interruption from any side.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आज यहां उद्योगों की बात हो रही है। इस सरकार के बनने के बाद मजदूरों पर लाठी चार्ज किया गया। किसी भी डैमोक्रेटिक सिस्टम में किसान धरने भी देते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के हाथ तो दर्जनों किसानों के खून से सने हुए हैं। छाज तो बोले, छलनी भी बोले। इनके हाथ तो दर्जनों किसानों के खून से सने हुए हैं। हमारे जिले में कंडेला की धरती है जो कि गुप्ता जी की कांस्टीच्यूएंसी के गांव में पड़ती है। आज भी कंडेला की धरती इनके द्वारा किए गए अत्याचारों की कहानी कहती है। आज भी हजारों-हजारों गोलियां कण्डेला गांव की दीवारों पर लगी हुई हैं जो इनके अत्याचार की कहानी कह रही हैं। एक अंहकारी ऐसा मुख्यमंत्री जिसने घोड़ों की टापों के नीचे लोगों को रौंद दिया हो क्या वह आज बात करेंगे?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : * * * * * * * * *

Mr. Speaker : Don't cast aspersions on the chair. इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : * * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : आप उलूल-जलूल बात करते हैं इसलिए आपकी बात रिकार्ड नहीं हो रही है। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : * * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, ये तो आपकी सारी बातें पहले ही आ चुकी हैं अब आप बैठ जाइये। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : * * * * * * * * *

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

हूं कि एस०ई०जैड० के नाम पर किसानों की एक इंच भी नाजायज भूमि को एक्वायर नहीं किया गया। जब ये हाउस को बरगलाने की कोशिश करेंगे तो स्पीकर सर, मुझे यह बात कहनी पड़ेगी। यह इनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की तरफ से चुनौती देता हूं कि आप इस बारे में हाउस की एक कमेटी बना दीजिए। किसानों की एक भी इंच भूमि का अधिग्रहण एस०ई०जैड के लिए नहीं हुआ। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Chaudhary Sahib, please address the chair. Nothing to be recorded (Interruption).

श्री ओम प्रकाश चौटाला : * * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : इनकी बात रिकार्ड न की जाए। ये तो अनर्गल बातें करने का आदि हो गया है। (शोर एवं व्यवधान) सदन में किसी पार्टी की कोई राजनीति नहीं चलेगी। राजनीति चलेगी तो चौक पे, बाजारों में और ग्राउंड में यहां पर राजनीति नहीं चलेगी। No, No यहां केवल फैक्ट्स की बात होगी। Nothing to be recorded (Interruption)

श्री नरेश कुमार प्रधान : अध्यक्ष महोदय, आज जो लोग कानून-व्यवस्था की बात करते हैं उन लोगों ने कण्डेला में 9 किसानों की हत्या करवा दी थी इसलिए इनके खून से हाथ रंगे हुए हैं। स्पीकर सर, दुलीना में 4 हरिजन भाइयों को इन्होंने जिन्दा जला दिया था। महम में इन लोगों ने अपने एक साथी अमीर सिंह की हत्या करवा दी और उसकी लाश को खेतों में फैंक दिया था जबकि आज ये सौहार्दपूर्ण की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Mr. Chautala, I allow to speak you. You may carry on your speech. No body will interrupt you. (Interruptions)

वाक-आउट

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, मुझे बार-बार इंट्रप्ट किया जा रहा है और मुझे मेरी बात को स्पष्ट करने का मौका नहीं दिया जा रहा है इसलिए एज ए प्रोटैस्ट हम सदन से वाक-आउट करते हैं।

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के सदन में सभी उपस्थित सदस्य एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक-आउट कर गए।)

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, आपने ओम प्रकाश चौटाला को पूरा मौका दिया और आपने तो उनको जाते जाते भी कह दिया कि आप बोलें लेकिन सच्ची बात यह है कि आप चाहें उन्हें एक घण्टे का समय दीजिए, डेढ़ घंटे बोलने का समय दीजिए लेकिन उनके पास मसाला 5 मिनट का होता है। 5 मिनट बाद उनका मसाला खत्म हो जाता है और उसके बाद वे कोशिश करते हैं कि किस तरह से चेयर को अस्पर्शन कास्ट करें और किस तरह से दूसरे सम्मानित साथियों की तरफ़ अस्पर्शन कास्ट करें। यहां तक कि इन्होंने अपने ही साथी डा० सीताराम तक के लिए कह दिया कि वे क्या

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

बोलेगा । वह जो मानसिकता है जिसमें विधायकों के हाथ तोड़े जाते थे, खुद की पार्टी के विधायकों को जहाज में ले जाकर पीटा जाता था, खुद की पार्टी के विधायकों को तेजाखेड़ा फार्म पर ले जाकर बेइज्जत करके कमरों में बंद करके पीटा जाता था, इनकी ऐसी मानसिकता गई नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी कहा था कि रस्सी जल गई, हरियाणा के लोगों ने जला दी लेकिन बल नहीं टूटा और वह बल भी हरियाणा के लोगों को एक बार फिर निकालना पड़ेगा । अध्यक्ष महोदय, ये खुद के ही मैम्बर को कहते हैं कि ये क्या बोलेगा । सीताराम जी भी चुनकर आए हैं और इतने ही सम्मानित सदस्य हैं जितने कि ओम प्रकाश चौटाला जी हैं । कप्तान साहब भी उतने ही सीनियर मैम्बर हैं जितने सीनियर ओम प्रकाश चौटाला जी हैं और उतना ही राजनीतिक तजुर्बा रखते हैं जितना ओम प्रकाश चौटाला जी रखते हैं । कप्तान साहब 5 बार जीत कर आए हैं लेकिन ये तो मुख्यमंत्री होते हुए चुनाव हार गए थे । कैप्टन साहब कभी चुनाव नहीं हारे और लगातार 5 बार जीत कर आए हैं । ओम प्रकाश चौटाला जी कैप्टन साहब की तरफ हाथ करके कहते हैं कि तू कौन है मुझे रोकने वाला । अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि लोकदल के साथियों के लिए कम से कम पार्लियामैंट्री प्रैक्टिस समझाने के लिए अलग से क्लास लगाई जाए क्योंकि ये बाकी पार्टियों के सदस्यों के साथ संसदीय व्यवहार करना नहीं सीख पाए ।

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आप और मैं कई सालों तक विपक्ष में बैठे हैं । जब कभी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री रहे हैं ये किसी मैम्बर को रिमेनिंग पीरियड के लिए हाउस से निकालते थे तो उसको कभी वापिस नहीं बुलाते थे । लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये आपकी फिराखदिली है कि आपने पार्टी मीटिंग करके इनको बुलाया और इनको बोलने के लिए पूरा समय दिया गया, उसके बाद भी इनमें कोई सुधार नहीं आया । इनके पास बोलने के लिए कोई मैटीरियल नहीं था, आपने इनको आखिर तक बोलने के लिए कहा । मैं इतने सालों तक विपक्ष में बैठता रहा हूं लेकिन कभी बोलने के लिए मौका नहीं दिया जाता था लेकिन आप इनके मैम्बर्ज को पूरा समय दे रहे हैं । आप इस बार बहुत लम्बा सैशन चला रहे हैं जबकि इनके समय में कभी 8-10 सीटिंग से ज्यादा सैशन नहीं चला । आप चाहे तो रिकार्ड दिखवा लें, आप इतनी फिराखदिली दिखा रहे हैं फिर भी ये सुधर नहीं सकते । जैसे कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी रहती है उसी प्रकार ये सुधरने वाले नहीं हैं और ये ऐसे ही रहेंगे ।

सुखबीर सिंह जौनपुरिया : अध्यक्ष महोदय, एस०ई०जैड० का मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने भारी विरोध किया । 1700 एकड़ जमीन ऐसी थी जिस पर ओम प्रकाश चौटाला ने मुख्यमंत्री होते हुए 17 बी०पोलिसी लगा दी थी ताकि जमींदार अपील ही न कर सकें । उन्होंने उसका 5 या साढे 5 लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया था लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने वहीं मुआवजा 24 लाख 90 हजार रुपये प्रति एकड़ दिया है । ये कहते हैं कि इन्होंने झज्जर में रिलायंस वालों को फ्री जमीन दी हैं लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आज तक एक बिसवा भी जमीन कहीं ऐसी नहीं है जो गुड़गांव या झज्जर के एरिया में एक्वायर करके दी गई हो, ये जो तथ्य दे रहे थे इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है । झज्जर में जहां इनके समय में जमीन का रेट 4 या 5 लाख रुपये प्रति एकड़ था वह आज 22 या 25 लाख रुपये एकड़ हो गया है इसलिए एस०ई०जैड० का तो मुद्दा ही नहीं था ।

शहरी विकास मंत्री (श्री ए०सी०चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। चौटाला जी ने दो बार कहा कि उनके समय में कोई भी उद्योग पलायन करके नहीं गया। मैं सदन के सामने रिकार्ड प्रस्तुत करना चाहूंगा कि मैटल बोक्स ऑफ इण्डिया, फरीदाबाद में बहुत बड़ी कंपनी थी जो कि बैस्ट पे मास्टर थी, इण्डियन हार्ड वेयर इण्डस्ट्री, हीतानी इण्डस्ट्री, भास्कर इण्डस्ट्री, ईस्ट इण्डिया कोटन कंपनी और आईशर कंपनी चौटाला जी के मुख्यमंत्री काल में हरियाणा से पलायन कर गई थी। इसके अतिरिक्त लखानी और बाटा की एक्सटैंशन यूनिट्स दूसरी जगहों पर चली गई। इसके अतिरिक्त जेडोर टूल्ज के चार यूनिट्स और प्रसटोलाईट कंपनीज बंद होकर इनके कार्यकाल में अपनी जमीन बेचकर हरियाणा से चली गई। इससे बड़ा और कौन सा सबूत इनको चाहिए। ये सभी कंपनीज चौटाला जी जैसे भले मानस के कारण हरियाणा छोड़कर चली गई।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे उस समय बोलने के लिए समय दें जिस समय ओम प्रकाश चौटाला जी सदन में उपस्थित हों क्योंकि जिस समय श्रीमान जी बोल रहे थे उस समय मैंने अपना पूरा सब्र रखा है।

श्री अध्यक्ष : इस बात की आप गारंटी देंगे कि वे आपकी बात सुनेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : सर चौटाला जी की गारंटी तो इनके बाप ने भी नहीं ली, मैं कैसे ले सकता हूं।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, आपके पीछे जो पिलर है पहले उस पर लिखा हुआ था और अब पट्टी पर लिखा हुआ है। यदि चौटाला जी को सदन में बुलाना है तो वह पट्टी सदन से हटवा देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने तो झूठ के अलावा और कुछ नहीं कहना। वे झूठ बोलने में पूरे एक्सपर्ट हैं। उन्होंने झूठ बोलने की लैबोरेटरी लगा रखी है। चौटाला जी समझते हैं कि लोगों को झूठ बोलकर ही बेवकूफ बनाया जा सकता है। एक बार झूठ बोलकर उन्होंने लोगों को बेवकूफ बना भी दिया था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण दिया गया है उसका अनुमोदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण बहुत ही उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं से परिपूर्ण है। इसमें प्रदेश की नीतियों और विकास के साथ-साथ सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है जिसके लिए मैं चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली सरकार को बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश की नीति का मूल आधार कृषि और किसान हैं। **(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य आई०जी० शैर सिंह चेयर पर पदासीन हुए)** केन्द्र की सरकार ने किसानों के 60 हजार करोड़ रुपये के कर्जे माफ करके अपोजीशन के मुंह पर एक तरह से ताला लगा दिया है। सभापति महोदय, कर्ज माफी की प्रशंसा पूरे देश के किसान कर रहे हैं। सभापति महोदय, इसके साथ-साथ इसमें मुख्यमंत्री जी से मेरा एक सुझाव है कि प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत बैकवर्ड हरिजन कल्याण निगम के तहत जो नौजवान लोन लेते हैं और यूनिट न लगाने के कारण कर्जदार हो जाते हैं तथा लोन वापिस नहीं कर पाते,

वे लोग भी आज बहुत परेशान हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी उन नौजवानों की तरफ भी ध्यान दें। भारत सरकार के फैसले से पहले ही हरियाणा सरकार ने बैंकों के लोन का ब्याज माफ करके बहुत बड़ी राहत किसानों को पहले ही प्रदान कर दी थी। लेकिन इसके लिए भी मैं सुझाव दूंगा कि इसके ऊपर भी मुख्यमंत्री जी ध्यान दें कि जो बेरोजगार नौजवान कर्जे में डूबे हुए हैं जिनकी यूनिट उसमें नहीं आई और जो चिन्तित हैं तो उनको भी हरियाणा सरकार इसमें कवर कर ले। सभापति महोदय, हमारा संगठन 'हरियाणा युवा किसान संघर्ष समिति' एक गैर राजनीतिक प्लेटफार्म पिछले 20 सालों से दक्षिणी हरियाणा में काम कर रहा है। सबसे पहले हमने एस०ई०जैड० के मुद्दे पर आवाज भी उठाई थी और विधान सभा में भी हमने यह मुद्दा उठाया था। हमने यह मांग रखी थी कि किसान को उसकी जमीन का मालिकाना हक दिया जाये। अगर किसान की खेती की जमीन जाती है तो उसका मालिकाना हक कम से कम किसान के पास रहे क्योंकि उसके पास यही एकमात्र दादालाई सम्पत्ति होती है जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी उसका गुजारा चलाती है। अगर जमीन किसानों की चली जाती है तो उसके पास और उसके बच्चों के पास कोई भी दूसरा रोजगार का साधन नहीं रहेगा क्योंकि उसके पूरे परिवार का गुजारा उस खेती के ऊपर ही चलता है। हमारी यह मांग थी। माननीय मुख्यमंत्री जी और हरियाणा सरकार ने यह काम किया जिससे हिन्दुस्तान में यह पहली सरकार साबित हुई है जिसने किसानों द्वारा उठाई गई मांग पर जो हमने डिमाण्ड भी नहीं की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह फैसला लिया कि अगर किसी किसान की एक एकड़ जमीन एस०ई०जैड० में एच०एस०आई०डी०सी० में या दूसरे उद्योगों के लिए ली जायेगी तो 33 साल तक 30 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष उसको मिलेंगे और इसमें 1000 रुपये प्रति वर्ष बढ़ोतरी होती रहेगी। पिछले दिनों नीमराना में एक किसान सम्मेलन हुआ था उसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी वहां बुलाया था। इससे राजस्थान के लोग बड़े अचम्भे में थे कि हरियाणा सरकार ने इतना बड़ा फैसला कर दिया है जबकि वहां पर किसानों को केवल 2 लाख रुपये ही मिले कोई रोजगार भी नहीं मिला और लगभग 40-50 हजार एकड़ जमीन वहां शहरोड़, नीमराना और कोटपुतली आदि क्षेत्रों की ली गई। इसके अलावा 15 हजार एकड़ जमीन तो बिड़ला सीमेंट फैक्ट्री में चली गई जबकि उससे उस पूरे एरिया में धुआं और धूल का बहुत ही बुरा माहौल हो गया है लेकिन वहां भी किसान को कभी भी कुछ नहीं मिला। यह जो शुरूआत हुई है हरियाणा से, हरियाणा की इस विधान सभा से, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से तो इस बारे में पूरे देश में एस०ई०जैड० के बारे में चर्चा चल रही थी, बहस चल रही थी।

श्री फूल चन्द मुलाना : सभापति महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। सभापति महोदय, माननीय सदस्य बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं पर ये यह चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं कि जो साथी उठकर चले गये उन्होंने इस प्रदेश की पंचायतों की और सोसायटीज की कितनी जमीन हथियाई थी किसी ट्रस्ट के नाम पर उसकी चर्चा ये क्यों नहीं करते कि हरियाणा प्रदेश में श्री ओम प्रकाश चौटाला के राज में हरिजनों का इतना दमन किया गया। आपको पता है हरसौला से हरिजनों के 200 परिवार बाहर निकाल दिये गए जिन्हें इस सरकार ने बसाया है। दुलीना में 8 हरिजनों को मार दिया गया और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। सभापति महोदय, इनको इस बात का भी जिक्र करना चाहिए कि उनके दिल में हरिजनों के लिए कितना प्रेम है। उनके राज में नौकरी के लिए लिए जाने वाले रिटन टैस्ट

[श्री फूल चन्द मुलाना]

में हरिजन उम्मीदवार टॉप पर रहते थे लेकिन उनको इंटरव्यू में 0 से 3 तक नम्बर दिये जाते थे, उसका जिक्र भी इनको करना चाहिए। उनको तो एक मुद्दा चाहिए था बाहर जाकर मेरे प्रैस के बंधुओं को बोलने का कि हमें तो बोलने ही नहीं दिया जाता इसलिए वे उठकर चले गये हैं। उसकी भी इनको चर्चा करनी चाहिए।

श्री नरेश यादव : सभापति महोदय, आदरणीय श्री मुलाना जी ने जो सुझाव दिए हैं वे बहुत ही सही सुझाव हैं और यह बात बिल्कुल सही है। आज हम देखते हैं कि शराब के ठेके के माध्यम से कई हजार नौजवानों को लॉटरी के जरिए रोजगार मिल गया है वर्ना चौटाला जी की सरकार जब 2005 में आई थी तो ठेकों की बोली के समय कह दिया जाता था कि 300 करोड़ की इकट्ठी बोली छोड़ी जायेगी। सीधे एक ही ग्रुप को पूरे 4-5 जिले इकट्ठे करके दे दिये गये और बोलीदाता बेचारे वहां पर बैठे देखते ही रह गये और ऊपर से अजय भाई साहब का इशारा हो गया कि भाई साहब का मैसेज आ गया है। ऐसे ही गुड़गांव में हुआ, बाहर के टैण्डर हुए, रेवाड़ी के अन्दर भी बाहर का टैण्डर हुआ। यह जो हमारे यहां स्लेट पत्थर होता है उसका रेवाड़ी में टैण्डर था और बहुत से नौजवान जिनके खेत वहां पर लगते थे वहां पहुंच गये। हम भी वहां गये हुए थे। बोली हो गई लेकिन प्रशासन की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि कुछ ताकतवर लोग वहां पर पहुंच गये। अजय चौटाला खुद प्रैजैन्ट थे नहीं। बोली हो गई, बोलीदाताओं ने फैसला किया कि जो लोकल लोग हैं उनको भी कुछ हिस्सा दे दिया जाये। बाद में वह बोली कैंसिल हो गई और फिर दोबारा चुपचाप बोली लगवाई गई। सभापति महोदय, ये सारी चीजें मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा क्योंकि कुछ नेशनल इश्यू भी हैं। सेज के मामले में पश्चिम बंगाल में न जाने कितने किसान मारे गये लेकिन वहां की सरकार कोई फैसला नही कर पाई। सेज पर कम्पनी इस बात पर अड़ी हुई है कि फैक्ट्री वहीं पर लगेगी। उत्तर प्रदेश में भी खूब आन्दोलन चले। राष्ट्रीय स्तर के बहुत से नेताओं ने भी इसका विरोध किया, धरने पर भी बैठे। वी०पी० सिंह भी उत्तर प्रदेश में सेज के विरोध में धरने पर बैठे थे, राज बब्बर भी गये थे। खूब लड़ाईयां लड़ी लेकिन सरकार ने कोई फैसला नहीं किया कि किसान की अगर जमीन ली जायेगी तो उस किसान के परिवार को बसाने के लिए क्या मिलेगा लेकिन हमारी सरकार ने एक अभूतपूर्व फैसला किया जिसका हमने स्वागत किया और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया क्योंकि पूर्व की सरकारें केवल लूट खसोट का कार्य करती थी, केवल अपने परिवार के लोगों के लिए जमीन अधिग्रहण करती थी। गुड़गांव में जो भी जमीन खाली मिली उसको नोटिस भिजवाकर वे अपने कब्जे में ले लेते थे। आज जो भी उद्योग यहां लगे, जिन कम्पनियों को यहां बुलाया गया, अल्टीमेटली यह फैसला हुआ कि सभी कम्पनियां चाहे वह रिलायन्स हो या दूसरी कम्पनियां हों, उनको किसान से मार्केट रेट पर सीधी जमीन खरीदनी पड़ेगी। अगर मुख्यमंत्री जी इस मसले में ईमानदार नहीं होते, उनकी सोच ठीक नहीं होती तो वे कम्पनियों की ओर ही खड़े होते। लेकिन अंत में यही फैसला हुआ कि जो भी कम्पनी हो किसान के पास जाये और उनसे भाव तय करे। अगर सरकार जमीन दिलवायेगी तो 33 साल तक 30 हजार रुपये प्रति एकड़ किसान को देने पड़ेंगे और अगर एच०एस०आई०डी०सी० यूनिट लगायेगी तो उसको भी देने पड़ेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सरकार ने किया है, मैं मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बधाई देता हूं। 15 हजार रुपये सरकारी कार्य के लिए

और जो सेज के लिए जमीन उपयोग होगी उसके लिए 30 हजार रुपये देने होंगे। इसमें हर साल बढ़ोतरी भी होगी। 500 रुपये प्रति वर्ष सरकारी कार्य के लिए और एक हजार रुपये प्रति वर्ष सेज के लिए बढ़ोतरी होगी। जहां तक कृषि का सवाल है 24 जून, 2002 का वह दिन मुझे आज भी याद है। चौ० ओम प्रकाश चौटाला उस समय पंजाब में फंक्शन कर रहे थे। बादल जी, चौधरी देवी लाल जी की मूर्ति का अनावरण कर रहे थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी वहां पहुंचना था। हमने इस मौके पर तय किया कि नारनौल के अन्दर एस०वाई०एल० कैनाल के मुद्दे पर प्रदर्शन करना है। पंजाब में भी उस समय बादल की सरकार थी, हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी और केन्द्र में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री थें सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका था कि तुरन्त प्रभाव से एस०वाई०एल० कैनाल का निर्माण करवाया जाये और यह कार्य सालों व महीनों में नहीं बल्कि हफ्तों में शुरू किया जाये। यह फैसला आने के बावजूद भी चौटाला जी को कोई चिन्ता नहीं हुई। इसके बाद हमने नारनौल में प्रदर्शन किया और पंजाब की गाड़ियों को रोकना शुरू किया क्योंकि बादल साहब ने कह दिया था कि हम एक बूंद पानी भी हरियाणा को नहीं देंगे। हमारी किसान संघर्ष समिति ने भी तय किया कि हम एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ेंगे। नारनौल में पंजाब की गाड़ियां रास्ते में रोक दी गई। हम जब प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन देने के लिए जाने लगे तो चौटाला साहब ने पंजाब से ही उस समय के एस०एस०पी० को और डी०सी० को कहा कि इनको रास्ते में ही रोक दो। एक तरफ तो कंडेला कांड हो रहा है दूसरी और ये खड़े हो गये हैं तो पानी के ऊपर हमें कुछ बोलना पड़ेगा। बोलने के बजाय बादल का साथ देते हुए हमारे ऊपर लाठीचार्ज किये गये, 307 के मुकदमे बनाये गये। हमारे किसानों को जेलों में डाल दिया गया। जेलों के अन्दर भी हम अनशन पर बैठे रहे। किसी को मिलने तक नहीं दिया गया। इस तरह के अत्याचार इनके शासनकाल में किसानों के साथ, मजदूरों के साथ हुए।

श्री सभापति : क्या आपके साथ भी हुआ?

श्री नरेश यादव : हां सर, मैं खुद जेल में था। खुद मेरे ऊपर 307 का मुकदमा था। सभापति महोदय, पिछली बार जब विधानसभा का सैशन चल रहा था और उस समय ओलावृष्टि हो गई थी तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी खुद महेन्द्रगढ़ जिले में गए थे। पलवल और मेवात 2-3 जगहों पर सैशन से जाकर उन्होंने अपना हैलीकॉप्टर उतारा। उस समय हमारे माननीय चौटाला साहब मण्डलाना गांव में बैठे हुए थे और मुख्यमंत्री जी महेन्द्रगढ़ जिले में उतर रहे थे। मुख्यमंत्री जी यहां से तय करके गए थे और वहां जाते ही उन्होंने पांच हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से किसानों को मुआवजा देने की घोषणा की थी। जबकि ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपने शासनकाल में 2 रुपये, 5 रुपये और 11 रुपये का मुआवजा किसानों को दिया। सभापति महोदय, यहां तक कि सिरसा में जहां इनका अपना हल्का है, 25 पैसे का मुआवजा देकर किसानों के साथ भद्दा मजाक किया था। चेयरमैन सर, जिस प्रकार से किसानों को ओलावृष्टि का मुआवजा दिया गया है उसी तर्ज पर पाले के कारण हुए नुकसान का मुआवजा भी किसानों को दिया जाना चाहिए। पाले के कारण वहां पर किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब अटेली मण्डी आए थे तो उस समय भी हमने उनसे यह निवेदन किया था कि पाले के कारण वास्तव में किसानों का बहुत नुकसान हुआ है इसलिए किसानों को हुए नुकसान का कुछ न कुछ

[श्री नरेश यादव]

समाधान निकाल कर किसानों को कुछ राहत जरूर दें। जो किसान कर्जे में डूबा हुआ था उसका कर्जा मुआफ करके उसको कुछ राहत दी गई है लेकिन पाले के कारण जो नुकसान हुआ है उससे किसान भाई दबा हुआ है। फसल बीमा योजना से भी किसानों को ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। कैप्टन साहब ने कहा था कि फसल बीमा योजना लागू करेंगे लेकिन इसके बारे में कैप्टन साहब को जानकारी होगी कि पिछली बार फसल बीमा योजना के तहत किसानों को कुछ ज्यादा राहत नहीं मिली थी। इसको किसी भी तरीके से कवर कर के किसानों को उसका फायदा पहुंचाया जाए जिससे किसान दोबारा खड़ा हो सके। चेयरमैन सर, यहां पर पशुधन की बात चल रही थी और भाई रणधीर सिंह जी ने बहुत अच्छी बात उठाई थी। पशुधन के बारे में मेरी भी मांग है कि काफी गांव ऐसे हैं जिनमें वेटरीनरी डिसपैंसरीज की बिल्डिंग तो बनी हुई हैं लेकिन वहां वेटरीनरी चिकित्सक नहीं हैं। गांवों में पशु अस्पताल बनाए जाने जरूरी हैं। पिछले तीन साल से हम मांग कर रहे हैं और हमने 4-5 गांवों की लिस्ट भी दी हुई है। इन गांवों में पशु चिकित्सालय खुलवाना और डॉक्टर्ज पहुंचाना जरूरी है इसलिए इस पर सरकार ध्यान दे। चेयरमैन सर, सिंचाई के बारे में कैप्टन साहब हमको आश्वासन दे रहे हैं कि हमें पानी मिलेगा। एच०वी०एल० कैनाल के लिए बी०एम०एल० में पंचर होगा और पानी आएगा। कैप्टन साहब अभी हमारे यहां पर जाकर आए हैं। नहरों की सफाई पर भी उन्होंने खूब पैसा लगाया है इसमें कोई शक नहीं है। पिछले सैशन से इस सैशन के बीच लगभग सभी डिस्ट्रीब्यूट्रीज की सफाई का कार्य हुआ है लेकिन पानी वहां तक नहीं पहुंच पाया है। इस बारे में मुझे विभाग के बारे में भी शिकायत है। जब हम चण्डीगढ़ में अधिकारियों से पूछते हैं कि हमारे एरिया के लिए कितना पानी चल रहा है तो यहां के ऑफिस वाले कहते हैं कि हम आपके एरिया के लिए 650 क्यूसिक फिट पानी चला रहे हैं लेकिन जब यह पानी महेन्द्रगढ़ कैनाल में पहुंचता है तो यह बहुत ही थोड़ा रह जाता है। लास्ट बार्डर पर नांगल चौधरी बहुत बड़ा गांव है जो राधे श्याम जी के हल्के में आता है। हमारा एक ही ब्लॉक नांगल चौधरी है और वहां तक पहुंचते-पहुंचते वह पानी 400 क्यूसिक फुट भी नहीं रहता है। वहां पर एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि सिंचाई की बात तो दूर पीने के पानी के भी हमें लाले पड़ जाते हैं। जो लोग इंजन वगैरा चलाते हैं तो उन पर तावान लगाते हैं। वहां के लोगों के लिए एक ही मुद्दा रह जाता है कि पानी मिले या नहीं मिले कम से कम जुर्माना मुआफ कर दिया जाए।

श्री सभापति : इस विषय पर प्रश्नकाल में बात हो चुकी है इसलिए अब आप further carry on करें।

श्री नरेश यादव : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि झांसी बुटाना लिंक नहर, एस०वाई०एल० नहर के मुद्दे तो कोर्ट में चल रहे हैं। एस०वाई०एल० नहर पर जैसे पंजाब के हाउस में एक सहमति बनी है वैसी ही सहमति यहां पर भी हाउस में बननी चाहिए। अभी यह मामला कोर्ट के विचाराधीन है लेकिन अगर यह मामला कोर्ट से निकल आता है तो हाउस में इस बारे में एक परिचर्चा करवा लीजिए ताकि सब लोगों के विचार सामने आएं और इसके लिए एक सहमति बन सके। झांसी बुटाना लिंक नहर के ऊपर भी हमने आज हाउस में कार्यवाही देखी है।

सभापति महोदय, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने ओम प्रकाश चौटाला जी से पूछा था कि आप हांसी-बुटाना लिंक नहर के पक्ष में है कि नहीं है। सभापति महोदय, उन्होंने सदन का सवा घंटा खराब कर दिया लेकिन चौटाला जी ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि वे इसके पक्ष में हैं कि नहीं हैं। इसका मतलब है कि वे हांसी बुटाना लिंक नहर को नहीं चाहते हैं। सभापति महोदय, हमने काफी लोगों को बताया कि हमारे हरियाणा के अन्दर काफी लोग ऐसे बैठे हैं जो हरियाणा की तरक्की करता नहीं देखना चाहते हैं। सभापति महोदय, 1994-95 में इसी हाउस की चार सदस्यों की कमेटी बनी थी उसमें ओम प्रकाश बेरी तथा तीन और सदस्य मैम्बर थे। उन्होंने ही इस चोरी को पकड़ा था कि 1977 में 18 लाख हैक्टेयर पानी केवल दो जिलों को जा रहा था। सभापति महोदय, मैं हिसार कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ हूं और वहां का वैज्ञानिक भी रहा हूं। वहां पर अभी कृषि मंत्री जी एक मेले में आए थे। वहां पर आज भी केवल एक ही मुद्दा है कि सेम की प्रोब्लम से निजात दिलाई जाए। हमारे सदन के साथी सीता राम जी भी यही बात कह रहे थे कि उनके यहां सेम की समस्या का समाधान किया जाए।

श्री सभापति : यादव जी, उस समस्या का समाधान होने जा रहा है।

श्री नरेश यादव : सभापति महोदय, वहां पर हजारों एकड़ जमीन पानी की बहुतायत की वजह से खराब हो गई है। वाटर लैवल बहुत ही ऊपर आ चुका है। लेकिन वे लोग यह मानने को तैयार नहीं है। उनकी सरकार के वक्त में उनकी सोच इतनी बेकार रही कि वहां पर वाटर लैवल बहुत ऊपर आने की वजह से वहां पर दलदल बन गया है। जबकि दक्षिणी हरियाणा में महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी जिले के गोदबलावा, पलथल, गढानिया के 4-5 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर 1400 फुट तक पानी नहीं मिलता है। इसी तरह से राव श्याम शर्मा जी के हल्के के दोस्तपुर गांव में भी 1400 फुट तक पानी नहीं मिलता है। सभापति जी, जो इस प्रकार की सोच के लोग यहां पर बैठे हुए हैं, जब वे सत्ता में होते हैं तो केवल एक जिले की ही बात करते हैं और जब विपक्ष में होते हैं तो कहते हैं हम हरियाणा प्रदेश का विकास करेंगे। जब सत्ता में होते हैं तो चाहे विश्वविद्यालय हो, यूनिवर्सिटी हो, नहर का पानी हो या रोजगार की बात हो सब कुछ एक ही जिले में दे दिया जाता है आज इस सरकार ने एक अच्छी कोशिश की है, एक अच्छी शुरूआत की है। इस सरकार की नियत है कि हरियाणा में पानी का समान बंटवारा हो। यह एक बहुत ही अहम् फैसला है और यह फैसला लेना किसी भी मुख्यमंत्री के लिए बहुत ही मुश्किल कार्य था। सभापति महोदय, मैं चौधरी बंसी लाल जी की पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि 1994 में भजन लाल जी की सरकार के वक्त में एक मर्तबा नारनौल में किसानों पर लाठियां चलवाई गयी थीं और वहां पर हमारे नौजवान साथी की पुलिस की गोली लगने से मौत भी हो गई थी तथा सैंकड़ों किसान घायल हो गए थे। उस वक्त भजन लाल जी ने किसानों पर मुकदमे बनवाए थे। उस वक्त सरकार ने पानी मांगने वालों पर तानाशाही की थी। उसके बाद चौधरी बंसी लाल जी सरकार में आए थे, हमने उनसे कहा था कि दक्षिणी हरियाणा में पानी के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का रौला चल रहा है इसलिए आप इसकी घोषणा हरियाणा में कर दें। हमने उनसे कहा था कि अभी मुद्दा गर्म है, आप इस बारे में घोषणा कर दें। चौधरी बंसी लाल जी कहने लगे कि भई नहीं, यह बहुत मुश्किल काम है, मेरे से दो बड़े

[श्री नरेश यादव]

जिले नाराज हो जाएंगे। सभापति महोदय, इस सरकार में मुख्यमंत्री जी ने जो समान पानी के बंटवारे के बारे में निर्णय लिया है उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। सभापति महोदय, हमारी हाउस में कामों को लेकर काफी नोंक-झोंक होती रहती है लेकिन हमने समान पानी के बंटवारे और एस०ई०जैड० के मामले को लेकर अटेली में मुख्यमंत्री जी का सम्मान किया था और कहा था कि आपने यह बहुत ही स्ट्रांग कदम उठाया है। सभापति महोदय, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बहुत ही स्ट्रांग स्टैप लेकर यह निर्णय लिया है। कैप्टन साहब, मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा कि कई स्टेटस में बहुत ही दूर-दूर से पाईप लाईन बिछाकर पानी दिया जा रहा है। कैप्टन साहब, ये जो हमारा महेन्द्रगढ़ जिला है, रिवाड़ी जिला है इनके धलयल और गढानिया में भी पानी नहीं है इसलिए वहां पर आप पाईप लाईन बिछा कर पानी पहुंचाने का कष्ट करें। नहर बेस्ड स्कीम के तहत जो आपने वाटर टैंक बनाए हैं और उन पर 200-200 लाख रुपये खर्च कर दिए हैं लेकिन फिर भी पानी नहीं पहुंच रहा है। कैप्टन साहब, मेरा सुझाव है कि जो मेन महेन्द्रगढ़ कैनाल लहरौदा के पास है जहां पर हमेशा पानी रहता है वहां से पाईप लाईन बिछाकर उन जगहों पर पानी दिया जाए। सर, अभी गर्मियों का मौसम आने वाला है और वहां पर पानी की बहुत भारी किल्लत होने वाली है इसलिए इससे पहले कि वहां पर पानी की किल्लत आए आप उसका इलाज कर दें। यह बात ठीक है कि वहां पर पीने का पानी टैंकरों से दिया जा रहा है इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं पिछली बार विधान सभा के सैशन में ही तय हो गया था कि जिस गांव में वाटर लैवल नीचे चला गया है वहां पर जन स्वास्थ्य विभाग टैंकर से पानी पिलाएगा। पूरे हरियाणा और खासतौर से अटेली और नारनौल के एरिया में यह काम आज भी यथावत जारी है। लेकिन मेरा कहना यह है कि गांवों में मेन नहर से एक पाईप लाईन के द्वारा पीने का पानी पहुंचाया जाए या ऐसा कोई चैनल बनाया जाए, ऐसी कोई स्कीम बनायी जाए जिससे लोगों को पीने के पानी की दिक्कत न हो।

13.00 बजे

श्री सभापति : नरेश जी, अब आप वाईंड अप करें। आपने बोलने के लिए 25 मिनट मांगे थे और अब आपको 25 मिनट हो चुके हैं।

श्री नरेश यादव : चेयरमैन सर, जहां तक पावर की बात है यह बात ठीक है कि बिजली की किल्लत रही है हम भी जब गांव-गांव में जाते थे तो हमें पता चलता था कि बिजली की प्रोब्लम थी क्योंकि बिजली की खपत बढ़ गयी थी। लेकिन पिछले बीस पच्चीस दिनों से यह महसूस किया जा रहा है कि बिजली में काफी सुधार हुआ है खास तौर से स्टुडैंटस की पढ़ाई के समय जो पहले बिजली की दिक्कत थी, वह पिछले महीने से सुधर गयी है। कैप्टन साहब के सामने ही मैंने विद्यार्थियों की एक मीटिंग में उनसे पूछा था तो उन्होंने स्वीकार किया कि अब पढ़ने के टाईम में बिजली मिल रही है। चेयरमैन सर, सरकार अब पावर प्लांट्स लगा रही है लेकिन माननीय मंत्री जी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं हालांकि यह क्वैश्चन ऑवर नहीं है कि आप जो पावर प्लांट झाड़ली में या दूसरी जगहों में बनाएंगे तो उनके लिए आपको पानी की जरूरत भी होगी। क्या आपने इसके लिए कोई पानी का अरेंजमैंट किया है? अभी तक तो दो सौ या तीन सौ क्यूसिक ही पानी हमें मिल

रहा है और असल में वहां तक 50 क्यूसिक पानी ही पहुंच रहा है तो रास्ते में झाड़ली में हमारा वह पानी रुक तो नहीं जाएगा? आपने कोई ऐसी व्यवस्था जरूर की होगी कि जब इन प्लांट्स में पानी की जरूरत पड़ेगी तो जो सुचारू रूप से पहले से व्यवस्था चल रही है वह रुक न पाए। चेयरमैन सर, जहां तक मेरे हल्के की छोटी-छोटी मांगों की बात है।

श्री सभापति : नरेश जी, आप दो मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए। आपकी जो मांगे हैं आप उनको लिखकर दे देना।

श्री नरेश यादव : चेयरमैन सर, आपने ओम प्रकाश चौटाला जी को तो एक घंटे का समय बोलने के लिए दे दिया जबकि वे तो हाउस का समय खराब कर रहे थे। मैं तो काम की बात बता रहा हूं, स्टेट के हित की बात बता रहा हूं फिर भी आप मुझे बोलने का टाईम नहीं दे रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि हमारे यहां की जो सड़कें हैं उनमें से मार्किटिंग बोर्ड की सड़कें आपके आशीर्वाद से अभी बननी शुरू नहीं हुई हैं। मंत्री जी हमारे हल्के में गए थे। पी०डब्ल्यू०डी० की सड़कें भी अभी ही बननी शुरू हुई हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत चार सड़कों का काम तीस करोड़ रूपये की लागत से आलरेडी शुरू करवा दिया गया है। मैंने क्वैश्चन ऑवर में भी कहा था कि जो हमारी सड़कों के टुकड़े राजस्थान बोर्डर तक जुड़े हुए हैं वह अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। हमारी इस तरह की पांच सात सड़कें हैं जिनके बारे में मैंने मंत्री महोदय को पहले भी लिखकर दिया है और अब जब चेयरमैन साहब आप कह रहे हैं तो मैं फिर से इनके बारे में लिखकर मंत्री जी को दे दूंगा। राजस्थान में चुनाव आ रहे हैं हो सकता है कि ये भी राजस्थान में चुनावों में अपना भाषण देने के लिए जाएं। अगर मंत्री महोदय हमारी ये सड़कें बनवा देंगे तो हो सकता है कि दूसरा फायदा इनको भी मिल जाए क्योंकि हमारी दस पन्द्रह सड़कें राजस्थान बोर्डर से जुड़ी हुई हैं। मुख्यमंत्री जी अभी नीमराणा गए थे।

श्री सभापति : यादव जी, आप इनके बारे में मंत्री जी को लिखकर दे देना उनकी तरफ से कार्यवाही हो जाएगी।

श्री नरेश यादव : जी हां, मैं लिखकर दे दूंगा। चेयरमैन साहब, नीमराणा से खातीखेड़ी रोड है, नीमराणा से अटेली रोड है इनकी तरफ ध्यान दिया जाए। मैं यह भी मांग करता हूं कि वहां के उस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र डिक्लेयर करवा दें क्योंकि एशिया लैवल पर नीमराणा आज काफी डिवैल्प हो गया है। अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। इसी तरह से पर्यटन विभाग की बात है। पर्यटन मंत्री जी इस समय बैठी नहीं हैं। हमारे यहां नारनौल अटेली रोड पर राजस्थान बोर्डर तक कोई भी पर्यटक स्थल नहीं है और न ही वहां पर कोई झील है। अब झील की बात करेंगे तो फिर पानी की बात आ जाएगी। मैं चाहूंगा कि वहां पर जो एक प्राचीन जल महल है इसको सरकार पर्यटक स्थल बना सकती है।

श्री सभापति : यादव जी, हारवैस्टिंग वगैरा बन जाएगा। आपने इस बारे में पढ़ा भी होगा।

श्री नरेश यादव : चेयरमैन सर, पीने का पानी मिलेगा तभी तो उसको भी सरवाएंगे। इसके अलावा सरकार ने म्यूनिसिपल कमेटीज भी बहाल की हैं। चौटाला साहब ने तो

[श्री नरेश यादव]
कनीना म्यूनिसिपल कमेटी की मांग करने वालों को जेल में डाल दिया था क्योंकि वे लोग इसका चुनाव न चाहकर अनअपोज जिताना चाहते थे। म्यूनिसिपल कमेटी तो बहाल हो गई हैं लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि अभी तक एक पैसा भी उनको नहीं मिला है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उनके लिए भी कुछ राशि दें ताकि विकास के काम हो सकें।

श्री सभापति : नरेश जी, आप वाईंडअप करें। पैसा आपको मिलेगा। कंसीडर हो रहा है।

श्री नरेश यादव : सर, मैं अपने एरिया में वाटर लैवल जो नीचे जा रहा है उसके बारे में भी कहना चाहता हूं। वाटर रिचार्जिंग हमारे एरिया की सबसे बड़ी प्रोब्लम है। पानी का लैवल किस तरह से ऊपर लाया जाए, इसके लिए जरूर सरकार को विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें एल०ए०डी०टी० के तहत भी पैसा नहीं मिला है।

श्री सभापति : नरेश जी, आपको एक मिनट का और समय दिया जाता है। उसके बाद आप बैठ जाएं क्योंकि फिर बहन प्रसन्नी देवी बोलेंगी।

श्री नरेश यादव : ठीक है सर, सभापति महोदय, नरेगा स्कीम में जौहड़ खोदने का कार्य चलता है। इसके बारे में मेरा सुझाव था कि इसमें पैसा वेस्ट जा रहा है। हम एम०एल०एज० जो लिस्ट बनाकर देते हैं उसके मुताबिक काम होना चाहिए। उसकी व्यवस्था बनाई जाए। इस मामले में संबंधित एम०एल०ए० को साथ रखा जाए ताकि विकास के काम कराए जा सकें। जिला महेन्द्रगढ़ में हमारे यहां कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आपके यहां यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। अब कह दिया गया है कि रिवाड़ी-गुड़गांव में बनाएंगे। हम चाहते हैं कि सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी के लिए बाछौद में 200 एकड़ जमीन भी है इसलिए इस तरफ ध्यान दिया जाए। इसके अलावा कनीना में सरकारी कॉलेज डिक्लेयर किया जाए।

श्री सभापति : अब आप बैठ जाएं।

श्री नरेश यादव : सभापति महोदय, मुझे सिर्फ एक मिनट का समय और दे दीजिए।

श्री सभापति : एक-एक मिनट कहकर आप दस मिनट ले चुके हैं। अब आप बैठिए।

श्रीमती प्रसन्नी देवी (नौलथा) : सभापति महोदय, आपने जो मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं। प्रधानमंत्री जी और सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में केन्द्र सरकार ने जो 60 हजार करोड़ रुपये किसान के कर्ज के माफ कर दिये वह एक बहुत ही ऐतिहासिक, सराहनीय और अनूठा कदम है। इसके साथ ही साथ एक प्रार्थना मैं यह भी करना चाहती हूं कि जो आदमी खेती से जुड़े हुए हैं लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है और उनके छोटे मोटे कर्ज भी हैं। ऐसे आदमियों के लिए जैसे भी सरकार ठीक समझे और उनको जितना

भी रिलीफ दे सके, उनको कुछ न कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। जैसे किसी ने कर्ज लेकर भैंस ली हुई है या छोटी-मोटी आटा पीसने की चक्की लगाई हुई है।

श्री सभापति : हरियाणा सरकार ने भी राहतें दी हैं।

श्रीमती प्रसन्नी देवी : मैं तो यह कहना चाहती हूं कि जितना भी रिलीफ सरकार द्वारा दिया जा सके, देना चाहिए। पिछले तीन वर्षों के शासन काल में हरियाणा की सरकार ने चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बहुत से विकास के कार्य किए हैं। उनको यदि गिनती में गिनाया जाए तो सुबह से शाम हो जाएगी लेकिन गिनाया नहीं जा सकता। लोग बाद में समझते हैं उनसे पहले ही ऐनाउंसमैंट भी हो जाती हैं और काम भी हो जाते हैं। अपोजीशन की सरकार 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बकाया बिल छोड़ गई थी। पीने के पानी की व्यवस्था तो बनाई गई थी लेकिन पीने का पानी लाया नहीं गया था। सरकार ने हरिजनों को जो टंकियां और टूटियां लगा कर दी हैं यह भी एक सराहनीय कदम है। गरीब आदमियों को 100-100 गज के प्लॉट भी दिये गये हैं। जिस आदमी के पास रहने के लिए जगह नहीं है, खाट बिछाने की जगह नहीं है। उस गरीब आदमी को सरकार ने 100 गज के प्लाट फ्री दिए, यह बहुत ही अच्छी बात है। हाउस टैक्स के लिए लोगों ने बड़ा भारी बोझा इकट्ठा कर लिया था, सरकार ने पहले तो उसका सरचार्ज माफ किया उसके बाद हाउस टैक्स को भी माफ किया। उसके बाद चूल्हा टैक्स माफ होने से भी लोगों को काफी राहत मिली है। गेहूं का भाव बढ़ने के कारण हमारी सरकार ने जो गरीब आदमी को राशन का 35 किलो अनाज देना शुरू किया हुआ है इसको 50 किलो किया जाये ताकि गरीब आदमी को इससे ज्यादा लाभ हो। इसी प्रकार से मिट्टी का तेल जो पहले 5 लीटर राशन का मिलता था उसको अब 3 लीटर कर दिया गया है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि उसको फिर से 5 लीटर कर दिया जाए। वैसे तो हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए अच्छे-अच्छे कदम उठाये हैं। खानपुर कलां में एक महिला विश्वविद्यालय खोला है, सर्विसिज में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया है। हाउसिंग बोर्ड के मकानों में 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण दिया हुआ है। बिजली कनैक्शन अगर महिला के नाम है तो उसमें भी बिल में कुछ रिलीफ दिया गया है। इसके साथ ही सभापति महोदय मैं एक प्रार्थना आपके माध्यम से सरकार को करना चाहती हूं कि हरियाणा के प्रत्येक जिले में एक महिला कालेज जरूर खोलना चाहिए जिससे हमारी बच्चियां आराम से पढ़ाई कर सकें क्योंकि सभी जिलों में महिलाओं के लिए अलग से कॉलेज नहीं है। सरकार के लिए यह कोई मुश्किल चीज नहीं है। वैसे तो सरकार ने प्रत्येक जिले में काफी काम किए हैं लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा समस्याएं हैं कि कोई न कोई तो कमी रह ही जाती है। अब मैं अपने हल्के की कुछ समस्याओं के बारे में कहना चाहूंगी। दो साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे गांव में गये थे मेरा गांव सींक जो पानीपत जिले के आखिरी में जींद जिले के साथ लगता हुआ पड़ता है। वहां पर बिजली की बड़ी भारी समस्या रही है। उस समय वहां पर लोगों ने एक 33 के०वी० का सब-स्टेशन लगाने की मांग की थी और पंचायत ने इसके लिए जमीन देने का रैजोल्यूशन भी पास करके भेज दिया है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा करा दें। इसी तरह से उलाना गांव का सब-स्टेशन जो 33 के०वी० का था उसको बढ़ाकर 66 के०वी० का कर दिया जाए। सर, अब मैं अपने हल्के की सड़कों के बारे में बात

[श्रीमती प्रसन्नी देवी]

करना चाहूंगी। पुठर से बांध तक की सड़क का दो किलोमीटर का टुकड़ा है अगर इस सड़क को बना दिया जाए तो मण्डी जाने का रास्ता छोटा हो जायेगा। पालड़ी से इसराना की दो-तीन किलोमीटर की सड़क ईंटों की बनी हुई है इसको आगे मिलाने की जरूरत है। इसी प्रकार से उलाना कलां से कैनाल पुलिस पोस्ट की सड़क जो कुराना गांव के पास मिलती है और जो कई डेरों के अन्दर की सड़क है इसको भी बनाया जाये क्योंकि बरसात के दिनों में यहां पर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता यह चार-पांच किलोमीटर का सड़क का टुकड़ा है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस सड़क को टॉप प्रियोरिटी से बनाया जाए क्योंकि उन लोगों के लिए आने-जाने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा शिवाड़ गांव के साथ-साथ मार्केट कमेटी ने सड़क बनाई हुई है। इसके बारे में एक साल से कह भी रहे हैं और इस बारे में लिख कर भी दिया है लेकिन इसको बनाया नहीं गया है सरकार की अगर मेहरबानी हो जाये तो इस सड़क के बनने से यह थर्मल प्लांट के पास जो बाई-पास बन रहा है, वहां पर यह मिलेगी इससे वहां के लोगों को काफी लाभ होगा। मेरी प्रार्थना है कि इन सड़कों को जल्दी से जल्दी रिपेयर करवाया जाए। इसी तरह से जीतगढ़ से नौहरा गांव की सड़क है, इस सड़क को बनाने की बहुत पुरानी मांग है उसके बन जाने से मतलौडा जाने का रास्ता साफ हो जाएगा और रास्ता छोटा हो जाएगा। छोटे रास्ते के कारण लोगों को आने जाने की सहूलियत हो जाएगी। सभापति महोदय, मेरी प्रार्थना है कि जिन सड़कों का मैंने जिक्र किया है इन सारी सड़कों की तरफ ध्यान दिया जाए। सभापति महोदय, मैं अब शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहूंगी, सरकार ने वैसे तो पिछले 3 सालों में काफी स्कूल बनाए हैं और हमारे यहां भी काफी स्कूल बनाए हैं। पिछले काफी अर्से से कोई स्कूल नहीं बना था। गांव कुटानी, सिमला, पुठाल, बड़शाम, काबड़ी और चंदौली गांव ऐसे गांव हैं जिनकी आबादी 10, 15 या 20 हजार के आसपास है और वहां प्राइमरी, मिडल और हाई स्कूल हैं उन स्कूलों को जहां प्राइमरी स्कूल है तो मिडल स्कूल और मिडल स्कूल है तो हाई स्कूल और हाई स्कूल है तो 10+2 का स्कूल करने की जरूरत है ताकि इन गांवों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। इसी तरह लड़कियों के स्कूलों की बहुत कमी है। गांव मांडी में लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल से मिडल स्कूल बनना है जिसके लिए लोगों ने बिल्डिंग खड़ी कर रखी है इसके अलावा मैंने जिन गांवों के नाम लिए हैं इन सबमें बिल्डिंग बनी हुई हैं। गांव सीख में लड़कियों के लिए मिडल स्कूल से हाई स्कूल, उरलाना में हाई स्कूल से 10+2 का स्कूल, इसराना हाई स्कूल को 10+2 का स्कूल और नौलथा के हाई स्कूल को 10+2 का स्कूल बनवाया जाए क्योंकि ये बहुत जरूरी हैं जिनके बने बगैर काम नहीं चलेगा। सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं एक बात कहना चाहती हूं कि स्कूलों का दर्जा बढ़ाने से हमारी लड़कियां जो बाहर या दूर पढ़ने के लिए नहीं जा पाती उनको गांव के अंदर पढ़ने में आसानी हो जाएगी। नौलथा गांव में P.H.C. है उसको C.H.C. बनाने के लिए 2 साल से ज्यादा समय से लोगों की कोशिश है और लोगों ने इसके लिए रैजोल्यूशन भी दे रखा है। जमीन और सरकार की जो दूसरी कंडीशंज हैं उनको पूरा करने के लिए लोग तैयार हैं क्योंकि सारे एरिया में आसपास कोई और C.H.C. नहीं है इस बारे में मुझे पता नहीं लग पाया कि यह केस किस स्टेज पर है और यह C.H.C. क्यों नहीं बन पा रही है? इसी तरह एक और C.H.C. है वहां डाक्टरों की कमी है। हमें पता नहीं

चल रहा कि क्या कारण है कि इस C.H.C. में डाक्टरों की कमी पूरी क्यों नहीं हो रही? सभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि लोग सारी सुविधाओं का फायदा उठा सकें। वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री को किसी काम के लिए बहुत कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती बल्कि लोग किसी बात को मुख्यमंत्री से कहने के लिए सोचते हैं उससे पहले मुख्यमंत्री जी की तरफ से उस काम के लिए अनाउंसमैंट हो जाती है। जिस तेजी के साथ हमारी स्टेट तरक्की कर रही है, ऐसी बहुत कम स्टेट्स मिलेंगी। मैंने कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम करके देखा है जितनी लग्न से हमारे मुख्यमंत्री सभी क्षेत्रों की तरफ ध्यान दे रहे हैं उतना कभी किसी अन्य मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। गांव की, देहात की सारी समस्याओं का उन्हें पता है। जिस तरीके से हरियाणा में काम चल रहे हैं यह एक सराहनीय कदम है। सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि विधान सभा भवन का बहुत अच्छा रैनोवेशन किया गया है इसके लिए हम मुख्यमंत्री महोदय और अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करना चाहते हैं लेकिन एम०एल०ए० होस्टल की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं कहना चाहूंगी कि हरियाणा के एम०एल०ए० होस्टल को पंजाब के एम०एल०ए० होस्टल की तरह बल्कि उससे भी अच्छा बनाया जाना चाहिए।

श्री सभापति : सैशन के बाद एम०एल०ए० होस्टल का काम भी हो रहा है। अब आप वाइंड-अप करें।

श्रीमती प्रसन्नी देवी : सभापति महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपने आप को शारदा राठौर द्वारा सदन में रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव के साथ शामिल करती हूं।

श्री कुलवीर सिंह बेनीवाल : सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। आज प्रदेश के अंदर बिजली की सबसे बड़ी दिक्कत है। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने बिजली के बारे में जैसे कदम उठाए हैं वैसे आज तक हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी और मुख्यमंत्री ने नहीं उठाये। हरियाणा के अंदर 10-10 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वालों ने भी कभी बिजली की समस्या का हल नहीं किया। ओम प्रकाश चौटाला जी लोगों को कहते थे कि एक बार मुझे सत्ता दे दो मैं 24-24 घंटे मुफ्त बिजली दूंगा लेकिन उन्होंने बिजली उत्पादन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)** अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने बिजली उत्पादन की तरफ विशेष ध्यान दिया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने यमुनानगर में स्थापित की जा रही 300 मैगावाट की दो इकाइयों में से पहली इकाई को नवम्बर, 2007 में चालू कर दिया था तथा दूसरी इकाई इस वर्ष मार्च में सिंकरोनाईज होने वाली है। इसके अतिरिक्त हिसार के खेदड़ गांव में 1200 मैगावाट का कोयला आधारित राजीव गांधी थर्मल प्लांट का कार्य शुरू हो चुका है जो वर्ष 2009-10 तक चालू हो जायेगा। इसी तरह से झज्जर में 1500 मैगावाट क्षमता का पावर प्लांट लगाया जा रहा है जो 2010 तक चालू हो जायेगा। इसी तरह से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए 'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना' के तहत 242 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे

[श्री कुलबीर सिंह बेनीवाल]

मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश में हर जाति को मान सम्मान दिया है सरपंचों को मान सम्मान दिया है और चौकीदारों को भी मान सम्मान दिया है, लोगों के हाउस टैक्स और चूल्हा टैक्स हमारी सरकार ने माफ किए हैं। इसके अतिरिक्त गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लाट दिए हैं जो कि बहुत ही सराहनीय काम हमारी सरकार ने किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं जिस हल्के से आता हूं वहां पर सबसे ज्यादा लोग ढाणियों में रहते हैं। एक ढाणी में बिजली पहुंचाने के लिए एक-एक लाख रुपये लग जाता है लेकिन हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे वहां हर ढाणी में लाईट पहुंचाई है इसके लिए अपने हल्के के लोगों की तरफ से मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, चौटाला जी कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे। आज वे भूल गये कि उनकी सरकार के समय में कानून व्यवस्था की कितनी बुरी हालत प्रदेश में थी? उनकी सरकार के समय में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी गयी थी। उस समय उनके रिश्तेदारों और चहेतों को शराब के ठेके दिए जाते थे। चौटाला जी के राज में खानों पर गुण्डा टैक्स लगा दिया गया था। सोनीपत की खानें उन्होंने अपने रिश्तेदारों और चहेतों को दे दी थीं। अध्यक्ष महोदय, चौटाला जी अपने विधायकों के हाथ तोड़ दिया करते थे। लेकिन आज वे कानून व्यवस्था की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने विपक्ष के साथियों को बोलने के लिए समय दिया लेकिन उनके पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। वे केवल टाईम पास के लिए ही बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक कृषि का सवाल है, कृषि की तरफ भी हमारी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है जिसके कारण वर्ष 2006-07 के दौरान प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन 147 लाख टन से भी अधिक हुआ है। यह उत्पादन आज तक का सबसे बड़ा उत्पादन है। गत फरवरी और मार्च, 2007 के दौरान ओले गिरने से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए प्रभावित किसानों को हमारी सरकार ने 208 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है जबकि चौटाला जी की सरकार के समय में किसानों को 25 पैसे, 75 पैसे और एक-एक रुपये मुआवजे के तौर पर देकर किसानों के साथ भद्दा मजाक किया गया था। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जिला सोनीपत के गन्नौर शहर में लगभग 500 एकड़ क्षेत्र पर एक विश्व स्तर की टर्मिनल मार्केट बनाने जा रही है। यह मण्डी भारत में फल एवं सब्जियों की सबसे बड़ी थोक मण्डी होगी। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने गेहूं का भाव 250 से 300 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया है जबकि पिछली सरकार के समय में 20-20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया जाता था। ये उस समय अपने आपको किसानों के नेता कहते थे। अध्यक्ष महोदय, चौटाला जी की सरकार के समय में एक नारा था कि "चौटाला तेरे राज में, जीरी गई ब्याज में" और आज चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार के समय यह नारा दिया जाता है कि "हुड्डा तेरे राज में, जीरी चढ़ी जहाज में"। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के क्षेत्र में हमारी सरकार एस०वाई०एल० नहर के माध्यम से नदियों के जल में हरियाणा का हिस्सा लेने की अपनी वचनबद्धता को दोहराती है। उपलब्ध नहरी पानी के सदुपयोग और समान वितरण करने के लिए सिंचाई के क्षेत्र में नई पहल की गई है। हरियाणा के अतिरिक्त पानी का सदुपयोग करने के लिए 30 करोड़ रुपये की लागत से पश्चिमी यमुना नहर की कैपेसिटी 13500 क्यूसिक से बढ़ाकर 20 हजार क्यूसिक की जा रही है। दादुपुर-नलवी नहर का निर्माण किया जा रहा है और पानी

को अंतिम टेल तक पहुंचाने का कार्य भी युद्धस्तर पर किया जा रहा हैं। राष्ट्रीय राजधानी पश्चिमी क्षेत्र की पेयजल की मांग को पूरा करने के लिए 225 करोड़ रुपये की लागत से 500 क्यूसिक पानी की वहन क्षमता वाला एक चैनल बनाया जा रहा है। हमारी सरकार हरियाणा के सभी गांवों और शहरों के लिए पर्याप्त स्वच्छ जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान पेयजल की कमी वाले 500 गांवों में जलापूर्ति बढ़ा दी गई है तथा वर्ष 2008-09 में ऐसे ही 368 और गांवों की जलापूर्ति में बढ़ोतरी की जायेगी। नवम्बर, 2006 में शुरू की गई 'इंदिरा गांधी पेयजल स्कीम' के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 8 लाख अनुसूचित जाति के परिवारों को मुफ्त में 200 लीटर की पानी की टंकी और कनैक्शन दिया गया। इस योजना के तहत आगामी वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान 4 से 4.50 लाख लोगों को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने हल्के की 2-3 समस्याओं को सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। भट्टू मण्डी में वाटर वर्क्स की हालत बहुत चिंताजनक है इसलिए उसकी रिपेयर किया जाना बहुत जरूरी है। उसके अन्दर जो पानी के टैंक हैं वे बहुत ही जर्जर हालत में हैं इसके अलावा मेरी कांस्टीच्युएंसी में तमाम वाटर वर्क्स की रिपेयर अपेक्षित है। इसके अलावा भट्टू मण्डी में सीवरेज की व्यवस्था भी दोबारा से करवाये जाने का मैं सरकार से अनुरोध करूंगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के समुचित विकास को सतत प्राथमिकता देती हैं। स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना को भी कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भी कार्यान्वित की जा रही है जो कि पहले हरियाणा प्रदेश के दो जिलों सिरसा और महेन्द्रगढ़ में ही थी लेकिन आगामी वित्त वर्ष के दौरान इसको प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति और गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों को आवास स्थान आबंटित करना भी हमारी सरकार का मुख्य कार्यक्रम है। 1 नवम्बर, 2007 को 'हरियाणा दिवस' के अवसर पर सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के गृह कर को समाप्त किया गया। अध्यक्ष महोदय, एक बात और है जो मेरी अन्तरात्मा बार-बार कहने को कह रही है कि हमारी सरकार की कोशिश से हमारे माननीय मुख्यमंत्री की कोशिश से हमारी केन्द्रीय सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है और 60 हजार करोड़ रुपये के किसानों के ऋण माफ किये गये हैं। इससे जन-जन को फायदा होगा क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है अगर हमारा किसान कर्ज मुक्त होगा तो वह खुशहाल होगा और अगर किसान खुशहाल होगा तो जो हमारा मजदूर व व्यापारी वर्ग है उसको भी उसकी खुशहाली का फायदा होगा। इस कार्य के लिए विधान सभा के सभी सदस्यों को भारत सरकार और हरियाणा सरकार का आभार प्रकट करना चाहिए कि ऐसा जनहितकारी फैसला लिया गया है जो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं लिया था। इस बार लोक सभा के बजट सत्र में पहली बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम दो बार लिया गया। इसके साथ ही स्पीकर साहब आपने मुझे राज्यपाल महोदय के बजट अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

प्रो० छत्तर पाल सिंह : स्पीकर सर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के बजट अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय

[प्रो० छत्तर पाल सिंह]

राज्यपाल महोदय ने हरियाणा सरकार द्वारा जो पॉपुलर कार्य इन पिछले तीन साल के अन्दर किये गये हैं उनका ऐतिहासिक वर्णन अपने अभिभाषण के अन्दर किया है। मैं उनके इस अभिभाषण के पक्ष में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हूं। स्पीकर सर, यहां पर विपक्ष के साथियों का जो आचरण है।

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 13th March, 2008.

*13.30 Hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Thursday, the 13th March, 2008).

44391—HVS—H.G.P., Chd.